

BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED

CIN: L74202MP1984PLC002592

Registered Office: 228 Part-B, The Zodiac Mall, Bicholi Mardana,
Indore(MP).452016

Email id- info@indraindustries.in, Tel. [+917383380911](tel:+917383380911)

Date: 07th June, 2025

**To,
The Listing Department
BSE Limited
Department of Corporate Affairs
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001**

Reference: ISIN: INE924N01016; Scrip Code: 539175; Symbol: INDRAIND

Subject: Newspaper clipping for extension of Right issue.

Respected Sir / Madam,

The company has made advertisement in Newspaper for informing shareholders about extension of closing date for the Right issue originally scheduled to close on Friday 06th June 2025 now has been extended to Monday 09th June 2025

In this regard please find enclosed newspaper clipping and oblique.

Thanking You,

Yours Faithfully,

**FOR BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED)**

**NITIN
KHANNA**

Digitally signed by NITIN KHANNA
DN: c=IN, postalCode=380015, st=GUJARAT,
street=RD, MAXY, JAMNEDARSATTELITE, 380015,
l=AHMEDABAD, o=Personal,
serialNumber=1a00026792bc34348001a4ac124a4a355cf4
55c4e3388f8398b302090d4,
pseudoym=cdf72425ab0416a02174b8889f2842,
2.5.4.20/*560662ac907641450d0d0748f894015a3303309
34-2089ca248f80bc9eb,
email=NITIN@NITININDUSTRIES.COM, cn=NITIN KHANNA
Date: 2025.06.07 15:59:30 +05'30'

**NITIN ASHOK KUMAR KHANNA
MANAGING DIRECTOR
DIN: 09816597**

**BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED
(Formerly known as Indra Industries Limited)**

3 प्रतिशत सीआरआर नया सामान्य स्तर

प्रभावी नकदी प्रबंधन के लिए 3 प्रतिशत सीआरआर पर्याप्त

अंजलि कुमारी
मुंबई, 6 जून

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) जरूरतों को 100 आधार अंक घटाकर शुद्ध मांग और सावधि देनदारी (एनडीटीएल) का 3 प्रतिशत करने का फैसला किया है। यह फैसला चरणबद्ध तरीके से 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाले पखवाड़ों से प्रभावी होगा।

सीआरआर में कटौती से दिसंबर 2025 तक बैंकिंग व्यवस्था में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये की प्राथमिक नकदी आएगी। ऐतिहासिक रूप से सामान्य समय में सीआरआर 4 प्रतिशत बहाल रखा जाता रहा है। यह राशि बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखनी पड़ती है और इस पर उन्हें ब्याज नहीं मिलता है। कोविड-19 महामारी के दौरान सीआरआर घटाकर 3 प्रतिशत किया गया था।

अब माना जा रहा है कि 3 प्रतिशत सीआरआर नया सामान्य स्तर हो सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सीआरआर घटाने की वजह बताते हुए कहा, 'इससे न सिर्फ नकदी में सुधार होगा, बल्कि इससे बैंकों को फंड की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी।'

मल्होत्रा ने नीतिगत फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'पिछले 12-13 साल के आंकड़ों से पता चलता है और कोई भी इसे देख सकता है कि सीआरआर ज्यादातर समय 4 प्रतिशत पर रहा है। कोविड के दौरान हमने इसे 1 प्रतिशत घटाया। अब इस रिजर्व को दरअसल नकदी प्रबंधन के लिए रखा जाता है। ऐसे में अब तक के अनुभव हमें बताते हैं कि



रिजर्व बैंक के फैसले से न सिर्फ नकदी में सुधार होगा, बल्कि बैंकों को फंड की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी

यह 4 प्रतिशत रखने की जरूरत नहीं है और शायद 3 प्रतिशत पर्याप्त है।'

उन्होंने कहा, 'हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा। अब ऐसा लग रहा है कि 3 प्रतिशत आरक्षित अनुपात नकदी प्रबंधन के लिए सहज है।' मल्होत्रा ने कहा कि सीआरआर में कटौती से मौद्रिक नीति का असर भी तेज होगा। उन्होंने जोर दिया कि रिजर्व बैंक नकदी और वित्तीय बाजार की स्थिति की निगरानी जारी रखेगा और जरूरत के मुताबिक सक्रिय रूप से भविष्य में कदम उठाएगा।

सीआरआर में कटौती के कारण बैंकों को मिलने वाली नकदी का उपयोग अब राजस्व आय परिसंपत्तियों में किया जा सकेगा, जिससे बैंकों को मार्जिन में सुधार करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर नीतिगत दर में 100 आधार अंक की कटौती से बैंकों के ब्याज से शुद्ध मुनाफे पर दबाव कम होगा। रिजर्व बैंक के

अनुमान के मुताबिक बैंकों का मार्जिन 7 आधार अंक सुधरेगा। उन्होंने कहा, 'नकदी मुहैया कराने के अलावा इसकी वजह से लागत भी घटेगी और हमारे अनुमान के मुताबिक उनका शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) कम से कम करीब 7 आधार अंक सुधरेगा। (हम नकदी मुहैया करा रहे हैं) इसलिए नीतिगत फैसले का बेहतर और तेजी से ट्रांसमिशन होगा।'

आईडीएफसी फ्रस्ट बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट गौरा सेनगुप्ता ने कहा, 'आकलन पूरी तरह से बदल गया है। कोविड के पहले सीआरआर कभी भी 4 प्रतिशत से नीचे नहीं आया। हाल के इतिहास में... संभवतः 1960 के दशक में ऐसा हुआ होगा। यही कारण है कि कोई सीआरआर में कटौती की उम्मीद नहीं कर रहा था। बिना संकट वाले दौर के पर दबाव कम होगा। रिजर्व बैंक के

देखा गया था। अब सीआरआर 3 प्रतिशत करने का मतलब यह है कि रिजर्व बैंक के विचार में बदलाव आया है कि सामान्य दिनों में कितना पर्याप्त है। अब यह गैर संकट के दौर का सामान्य स्तर लग रहा है।' उन्होंने कहा, 'इसका और भी कुछ मतलब है। रिजर्व बैंक नकदी बढ़ाने के लिए ओएमओ का विकल्प चुना। यह निर्णय खासकर बैंकों के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ से नकदी बढ़ाने की जरूरत बताता है।' ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक बैंकों के लिए मार्जिन का प्रबंध करते हुए नकदी तक उनकी पहुंच आसान करने की कोशिश कर रहा है।' पिछली बार दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति की घोषणा में रिजर्व बैंक ने सीआरआर 50 आधार अंक घटाकर 4 प्रतिशत किया था।

सवाल जवाब

पहले की तुलना में समिति के फैसलों का तेज असर

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर जवाब दिए। उन्होंने कहा कि पिछले रुझानों को देखते तो मौद्रिक नीति का असर बहुत तेजी से हुआ है। मुद्रा बाजारों में जो हमने किया है उससे भी अधिक असर हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह आकलन मुश्किल होगा कि मौद्रिक नीति से ऋण की दरों और वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इसका असर कैसा रहेगा। संपादित अंश:

इस चक्र में आप दरों को कहां टिकता देख रहे हैं? हमने रुख को उदार से तटस्थ कर दिया है। साथ ही इसमें उल्लेख किया गया है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वास्तव में मौद्रिक नीति को लेकर अब बहुत सीमित गुंजाइश है। आप मौजूदा हालात के बारे में जानते हैं, वृद्धि दर करीब 6.5 प्रतिशत है। इस वर्ष के लिए हम महंगाई दर 3.7 प्रतिशत और अगले वर्ष 4 प्रतिशत से ऊपर या करीब 4.5 प्रतिशत रखने का अनुमान लगा रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए एमपीसी के लिए बहुत कम गुंजाइश बची है। हमने अब रुख तटस्थ कर दिया है। समिति का यह भी कहना है कि आने वाले उन आंकड़ों और आधारों पर खासकर अनिश्चितताओं को देखते हुए लगातार नजर रखी जाएगी। हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, यह मुख्य रूप से आंकड़ों पर निर्भर होगा।

रुख अब तटस्थ कर दिया गया है। क्या लंबे समय का विराम होगा?

यह अब आंकड़ों पर निर्भर करेगा। तटस्थ का यही मतलब है। मैंने इसे पहले एमपीसी के ब्योरे में साफ किया था कि तटस्थ का मतलब है कि यह किसी भी दिशा में जा सकता है। यह इस पर निर्भर होगा कि आंकड़े कैसे आते हैं। अगर वृद्धि कमजोर है, तो इसका मतलब है कि यह नीचे जाएगी। अगर वृद्धि अच्छी है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि रीपो रेट बढ़ सकती है। इसलिए यह इस बात पर निर्भर करेगा कि महंगाई और वृद्धि के आंकड़े कैसे आते हैं।

क्या रुख पर मतदान हुआ था?

रुख पर मतदान को लेकर हमने पहले ही उल्लेख किया है कि कानून में मतदान अनिवार्य नहीं है। इस पर चर्चा हुई। निश्चित रूप से हमें संकेत देने, अनुमान देने की जरूरत थी। यह अनुमान है, जो हमें बाजार के प्रतिभागियों को देना होता है। इसलिए इस पर चर्चा हुई और समिति के सभी 6 सदस्यों का विचार था कि हमें तटस्थ रुख रखना चाहिए। इसलिए कोई मतदान नहीं हुआ। समिति के सभी सदस्यों का विचार यह है कि आगे चलकर रुख बदलकर उदार से तटस्थ किया जाना चाहिए।

क्या नीति के अब तक हुए असर से संतुष्ट हैं?

पिछले रुझानों को देखते तो मौद्रिक नीति का असर बहुत तेजी से हुआ है। मुद्रा बाजारों में आप बड़ा असर देख सकते हैं। जो हमने किया है उससे भी अधिक असर हुआ है। खासकर कम अवधि के हिसाब से मुद्रा बाजारों में 50 आधार अंक की तुलना में भी अधिक असर दिख रहा है। ऋण पर भी शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। ज्यादातर बैंकों ने थोक और खुदरा दोनों जमा दरों में करीब 40 आधार अंक की कमी की है। औसतन करीब 27 आधार अंक कमी हुई



है। ऋण के हिसाब से देखें तो बचे हुए ऋण पर 17 आधार अंक कमी आई है। नए ऋण के हिसाब से देखें तो असर थोड़ा धीमा है।

हमारे आंकड़ों के मुताबिक यह करीब 6 आधार अंक है। इस तरह से यह सुस्त है, लेकिन इससे पहले के वक्त की तुलना में बहुत तेज है। आम तौर पर इसमें 6 से 9 महीने लगते हैं। पहली नीतिगत कटौती से केवल 4 महीने हुए हैं। इसलिए 25 आधार अंक की पहली नीतिगत कटौती के मुकाबले जमा में 27 आधार अंक और ऋण में 17 आधार अंक और नए ऋण के लिए 6 आधार अंक की कटौती हुई है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा ट्रांसमिशन है। लेकिन हमें इसे और तेजी से करने की जरूरत है, इसलिए इस बार हमने कुछ कार्रवाई पहले ही कर ली है।

रीपो रेट में कुल 100 आधार अंक की कटौती से आप वृद्धि में कितनी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं? क्या वित्त वर्ष 2026 के वृद्धि अनुमान में संशोधन होगा?

जाहिर है, इसका (वृद्धि पर) सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह आकलन करना बहुत मुश्किल होगा कि मौद्रिक नीति से ऋण की दरों और उसके बाद वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इसका असर कैसा रहेगा। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इसका असर दिखले में कम से कम 6 से 9 महीने लगते हैं। हम इसे तेज करना चाहते हैं, लेकिन इसका असर दूसरी छमाही में ही दिखेगा। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इस साल जब इतनी अनिश्चितता है, हम कुछ ठोस रूप से बताने की स्थिति में नहीं हैं कि जीडीपी के आंकड़ों पर इसका कितना असर होगा।

यह नकदी का वृद्धि पर वाकई कैसे असर डालती है? व्यवस्था में अधिक नकदी का क्या लाभ है? यह अन्य कारकों पर भी निर्भर करेगा। मौद्रिक नीति पर्याप्त नहीं, लेकिन जरूरी है। हमें विश्वास है कि इससे ऋण वृद्धि बेहतर होगी। मैं कोई स्पष्ट आंकड़ा देने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन भरोसे के साथ यह कहा जा सकता है कि इससे ऋण प्रवाह बढ़ेगा। इसलिए नकदी महत्वपूर्ण है। रीपो रेट में कमी महत्वपूर्ण है। इसमें कितना वक्त लगेगा, यह कहना कठिन है।



नीतिगत दर में 50 आधार अंक की कटौती, सीआरआर में 100 आधार अंक की कटौती और रुख को बदलकर तटस्थ करने का फैसला अप्रत्याशित रूप से आश्चर्यजनक था।

सीएस शेड्डी
चेयरमैन, भारतीय स्टेट बैंक

मौद्रिक नीति समिति ने सुखद रूप से बाजारों को आश्चर्य-चकित कर दिया है। अतिरिक्त नकदी के साथ ब्याज दर कम होने से उधारी की लागत कम होगी और आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा।

पीडी सिंह
सीईओ, भारत-दक्षिण एशिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

रिजर्व बैंक द्वारा ढील दिए जाने के तरीकों को आगे बढ़ाने का फैसला भारत की वृद्धि की कहानी को और मजबूती से आगे बढ़ाता है। इन उपायों से नीति का तेज असर होगा और ऋण की लागत घटेगी

के बाला सुब्रमण्यन
सीईओ सिटी बैंक

परिपक्व बाजार का संकेत

धन वापसी के कारण शुद्ध एफडीआई में कमी आई

अभिजित लेले
मुंबई, 6 जून

वित्त वर्ष 2025 के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में तेज गिरावट धन वापस अपने देश भेजने की वजह से आई है। यह परिपक्व बाजार का संकेत है, जिसमें निवेशक आसानी से बाजार में कदम रख सकते और निकल सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा करते हुए यह बात कही।

इस महीने की शुरुआत में जारी रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध एफडीआई की आवक घटकर 0.4 अरब डॉलर रह गई है जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 10.1 अरब डॉलर थी। सकल

एफडीआई की आवक मजबूत बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह 14 प्रतिशत बढ़कर 8.1 अरब डॉलर हो गया है जो एक साल पहले 7.13 अरब डॉलर था।

मल्होत्रा ने कहा, 'यह बताना मुनासिब है कि (शुद्ध एफडीआई में) यह कमी धन वापस भेजने में इजाफा और शुद्ध रूप से विदेश में निवेशक विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण है, जबकि सकल एफडीआई वास्तव में 14 प्रतिशत बढ़ा है। अपने देश में धन वापस ले जाने में वृद्धि एक परिपक्व बाजार का संकेत है जहां विदेशी निवेशक आसानी से बाजार में प्रवेश कर सकते और निकल सकते हैं, जबकि उच्च सकल एफडीआई इंगित करता है कि भारत लगातार आकर्षक निवेश गंतव्य बना हुआ है।'



प्रवासी भारतीयों ने जमा किया ज्यादा धन

उन्होंने कहा कि बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) और प्रवासी भारतीयों की जमा में शुद्ध आवक पिछले के वित्त वर्ष की तुलना में अधिक रही है। भारत में ईसीबी से शुद्ध आवक वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 18.7 अरब डॉलर

हो गई है, जो एक साल पहले 3.6 अरब डॉलर थी। अप्रैल 2025 में शुद्ध ईसीबी बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गई जो पिछले वर्ष 0.5 अरब डॉलर थी। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रवासी जमा बढ़कर 16.2 अरब डॉलर हो गई है जो एक साल पहले 14.7 अरब डॉलर थी। उन्होंने कहा, 'कुल मिलाकर भारत का बाहरी क्षेत्र मजबूत बना हुआ है और प्रमुख बाहरी क्षेत्र के उतार-चढ़ाव वाले संकेतकों में सुधार जारी है। हमें भरोसा है कि हम अपनी बाहरी विदेशी वित्तपोषण की जरूरतें पूरी कर लेंगे।' वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश तेजी से गिरकर 1.7 अरब डॉलर रह गया है क्योंकि शेयर बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मुनाफावसूली की है।

बॉन्ड बाजार

3 साल की तुलना में सर्वाधिक उतार-चढ़ाव

अंजलि कुमारी
मुंबई, 6 जून

बॉन्ड बाजार में शुक्रवार को भारी उतार-चढ़ाव रहा। डीलरों ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक के फैसलों के बाद ऐसी अस्थिरता अगस्त 2022 के बाद से लगभग 3 वर्षों में पहली बार सबसे अधिक रही है। कई आश्चर्यजनक कदमों ने बाजार को चौंकाया।

समिति ने नीतिगत रीपो दर में 50 आधार अंक की कटौती का फैसला किया जबकि आम राय 25 आधार अंक कटौती की थी। रुख भी बदलकर तटस्थ कर दिया। यह एक

और आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था क्योंकि पिछली बैठक में रुख तटस्थ से बदलकर अनुकूल किया गया था। इसके अलावा सीआरआर जरूरतों को चरणबद्ध तरीके से 100 आधार अंक घटाने का फैसला किया गया।

शुक्रवार को कारोबार के दौरान बेंचमार्क गिल्ड 15 आधार अंक बढ़ा जो 5 अगस्त, 2022 के बाद सबसे ऊपर का स्तर है। तब एक दिन में गिल्ड 21 आधार अंक बढ़ा था। तटस्थ रुख में बदलाव के बाद 10 साल के बॉन्ड ने बाद में कुछ बढ़त गंवा दी। बेंचमार्क बॉन्ड ने कारोबार के अंत तक सभी बढ़त



कई मोर्चों पर फैसलों से हक्का-बक्का रह गया बॉन्ड बाजार

खत्म कर दगी और वह 6.29 प्रतिशत पर बंद हुआ जो पिछले बंद 6.25 प्रतिशत के मुकाबले 4 आधार अंक अधिक है।

पीएनबी गिल्ड्स में वरिष्ठ कार्यकारी वाइस प्रेसीडेंट विजय शर्मा ने कहा, 'रीपो दर में अप्रत्याशित कटौती से शुरुआत में बॉन्ड में तेजी आई। लेकिन नीतिगत रुख में बदलाव की बात से बाजार

भौंक रह गया। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के ताज्जुबों के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव रहा। सीआरआर में कटौती से फिर राहत मिली, लेकिन सारे नीतिगत कदम तभी घोषित कर दिए गए और भविष्य में आरबीआई की ओर से कदम उठाने का कोई संकेत नहीं मिला तो तो बाजार ने पोजीशन बेचनी शुरू कर दी।'

कम अवधि वाले खासकर 5 साल तक के सेगमेंट में एसएलआर और गैर एसएलआर (कॉर्पोरेट बॉन्ड) श्रेणी दोनों में ही बेहतर प्रदर्शन रहा है। फंडिंग लागत में कमी के कारण ऐसा हुआ।

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated May 09, 2025 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with BSE Limited ("BSE")

BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED)
Corporate Identification Number: L74140MP1984PLC002592
Registered Office: 228 Part-B, The Zodiac Mall, Bicholi Mardana, Indore (MP) - 452001
Contact Details: 7383380911; Email-ID: info@indraindustries.in; Website: www.indraindustries.in
Contact Person: Ms. Sweetsy Purohit, Company Secretary & Compliance Officer:

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE ISSUE

RIGHTS ISSUE OF UP TO 4,85,78,025*FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (RUPEE TEN ONLY) (EQUITY SHARES) EACH AT A PRICE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) PER EQUITY SHARE ("RIGHT SHARES") FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹48,57,80,250/- (RUPEES FOURTY EIGHT CRORE FIFTY SEVEN LAKHS EIGHTY THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED) (COMPANY OR 'ISSUER') IN THE RATIO OF 15 (FIFTEEN) EQUITY SHARES FOR EVERY 2 (TWO) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE. THURSDAY, MAY 09, 2025 ('ISSUE'). THE ISSUE PRICE IS 1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 130 OF THIS LETTER OF OFFER.

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") - ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MAY 9, 2025

This notice should be read in conjunction with the LOF filed by the Company with the Stock Exchange and the ALOF and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please note the following:

This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday 23rd May 2025 and was scheduled to close on Wednesday, Friday 06th June 2025, has now been extended to Monday, June 09, 2025, by the Rights Issue Committee in its meeting held on June 06 2025 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Monday, 09 June, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, 09 June, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE	
ISSUE OPENING DATE	ISSUE CLOSING DATE
FRIDAY 23RD MAY 2025	MONDAY 09TH MAY 2025

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

** Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms on or before the Issue Closing Date. #Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date. This addendum shall be available on the respective websites of our Company at info@indraindustries.in the Registrar to the Issue at www.puravshare.com, and the Stock Exchanges at www.bseindia.com.

Accordingly, there is no change in the LOF and ALOF dated May 09, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing date. Change in Issue closing date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.

All Capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

Date: May 09, 2025
Place: Indore
For Bluegod Entertainment Limited (Formerly Known As Indra Industries Limited)
Sd/-
Nitinashok kumar Khanna
Managing Director

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the BSE Limited The Draft Letter of Offer is available on the website of the Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com. Our Company at info@indraindustries.in and the Registrar to the Issue at www.puravshare.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Draft Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 31 of the Draft Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

Over 7% flights cancelled for 3 mths at Delhi airport

DIAL CEO cites runway upgrade as reason for cancellations

DEEPAK PATEL
New Delhi, 6 June

About 7.5 per cent daily flights to and from the Delhi airport will be cancelled between June 15 and September 15 as one of its four runways undergoes an upgrade, Delhi International Airport Limited (DIAL) Chief Executive Officer (CEO) Videsh Kumar Jaipuria said on Friday.

GMR Group-led DIAL operates the Delhi airport, which is the largest in the country.

"The Delhi airport handles 1,45,000 aircraft movements per day. Of these, 114 daily movements will be cancelled during the runway upgrade," Jaipuria said at a press conference.

"The number of cancellations will be in the range of 7-7.5 per cent, compared to the usual 3-4 per cent on a normal day. However, this time we have coordinated with airlines in advance and rescheduled flights accordingly, which will help reduce any cascading impact," he said.

Referring to a similar upgrade effort earlier this year, he added, "Last time, the lack of proper rescheduling led to cascading disruptions when wind patterns changed. This time, the impact on passengers will be much lower. Since they've been informed in advance, they will have enough time to rebook or make alternative arrangements," he added.

The upgrade of runway 10/28 will include installing an instrument landing system (ILS) and make it compliant with CAT III-B operations. CAT III-B is a precision landing system that allows aircraft to land in very low visibility conditions, such as dense fog.

It was originally scheduled for April-May. However, unexpected changes in wind patterns during that time severely affected flight operations, causing delays.

As a result, the Ministry of Civil Aviation — on April 21 — directed DIAL to postpone the upgrade and resume oper-



The airport will see flight cancellations between June 15 and September 15.

ations on the runway. The runway was made operational again on May 6, and the upgrade was deferred to June 15-September 15.

"The revised timeline was agreed upon by all airlines," Jaipuria said.

Following this, airlines collaborated with DIAL to rework slot allocations and align with the revised arrival capacity.

"The objective was to ensure optimum use of available runway capacity while maintaining on-time performance," he added.

"During the fog season, the arrival capacity of all runways comes down due to safety concerns, as arriving aircraft have to be spaced out," Jaipuria said.

"In case of westerly winds, arrivals drop from 42 per hour to 30 during CAT III-B operations. But with easterly winds, arrivals fall sharply from 42 per hour to just 15. Once the upgrade is complete, this number will go up to 30 even with easterly winds, significantly improving efficiency," he added.

"Every hour of fog disruption takes

Akasa to launch over 100 weekly flights from Navi Mumbai airport

Akasa Air will start more than 100 weekly domestic flights from the upcoming Navi Mumbai International Airport (NMI), expanding to more than 300 domestic and over 50 international weekly departures in the winter schedule, it said on Friday.

Akasa joins IndiGo in confirming its early commitment to NMI.

"No airline in India will have a larger percentage of its fleet and operations based out of NMI than Akasa Air," said Vinay Dube, founder and chief executive officer (CEO) of Akasa Air.

AHIL CEO Arun Bansal welcomed Akasa as an inaugural partner, stressing the airline's rapid growth and forward-looking approach.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

three hours for us to return to normal operations. This becomes much worse with easterly winds, where every hour of disruption takes six hours to recover. This impacts not just Delhi airport but also nearby ones.

Therefore, we decided to upgrade runway 10/28 and make it ready to handle CAT III-B flight operations," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

'By 2030, 80% of our new onboardings will be EVs'

Logistics startup Porter is aiming to bring in more driver partners and customers into its fold. In a video interaction with Udit Shah Srivastava, cofounder and executive vice-chairman, Praveen Goel, talks about the recent fundraising, how the amount is being used, the company's expansion plans and partnership with ONDC, among others. Edited excerpts:

Let us know about the company's recent fundraising and how is the amount being used?

■ It's been a fairly large fundraise, a mix of both primary and secondary capital. With this amount, we want to go deeper and launch more categories. Over the years, we realised that there's still 20 per cent of customers that we are not able to service.

■ Delhi is the biggest city, because of different requirements. So, the intent is to solve that. E-loader is one segment that we want to launch across India. The other big objective is to go wider and replicate the same business model into multiple cities in India. Also, launch in more international geographies where this model makes sense.

What are the targets for the years to come?

■ In the next five years, we will move from 2 million to 10 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver

partners, and that number will exceed 1.2 million. We are present in close to 22 cities in India and this number will be around 50 cities.

■ There is also a massive sustainability goal. (EVs).

What are the top cities of operations for Porter? Which vehicle categories are the high-frequency ones?

■ Delhi is the biggest city, given its size and scale. After Delhi, there are Mumbai and Bengaluru. Chennai, Hyderabad, and Ahmedabad follow. We probably have around 10 vehicle categories and they're fairly distributed. We have four high-frequency categories, including two-wheelers, three-wheelers, and entry-level four-wheelers. They represent 80 per cent of our revenues. The other six categories comprise nearly 20 per cent of the revenues.

Do you also have fleet partners or is it a driver-owned model completely?

■ We are a completely asset-light model where the driver-partner has his vehicle. In



IN THE NEXT FIVE YEARS, WE WILL MOVE FROM 2 MILLION SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES WHO COME TO THE PLATFORM EVERY MONTH TO SERVICING MORE THAN 10 MILLION CUSTOMERS

more than 90 per cent of the cases, the owner and the driver are one person. We also have fleet operators, but they comprise less than 10 per cent of our volumes. There are more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

What's the company's revenue breakdown?

■ Around 85 per cent of our revenue comes from micro, small, and medium enter-

prises (MSMEs), which are local retail stores, small manufacturers, furniture shops, paints and chemicals shops, among others. Then, more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

FROM PAGE 1

Experts flag infra limitations at major airports as hurdle for ATR operations

The Indian carrier, which currently operates a fleet of about 46 ATR 72-600s, had earlier placed an order for 50 such aircraft in 2017 as part of a strategy to expand its regional footprint under the government's UDAN

scheme to improve air connectivity to underserved towns. Four aircraft since have been sold or leased to other.

Deliveries under that contract were completed by early 2025.

The ATR 72-600 is a twin-engine turboprop aircraft typically seating around 70 passengers, although IndiGo configures its planes in a high-density 78-seat layout. The aircraft is primarily deployed on short regional routes, with a range of about 1,300km.

"IndiGo has utilised the ATRs on all sorts of routes, from monopoly under regional connectivity scheme UDAN to some intra-metro high frequency ones in South India," said Armeja Joshi, aviation analyst and founder of the blog Network Thoughts. "The airline has also experimented with routes, some working well and some not continuing," he said.

The turboprop fleet enabled IndiGo to expand its network to smaller destinations such as Kolhapur, Kishanganj and Kadapa, which are not feasible for the airline's Airbus fleet, according to Joshi.

But the also flagged infrastructure limitations at major airports as a major hurdle for ATR operations.

"One of the biggest challenges has been getting slots at Delhi or Mumbai for the ATR," he said. "The development of secondary airports — like Navi Mumbai and Jewar — could ease this constraint and support rapid network expansion. How much does the government incentivise going forward also needs to be seen."

Since 2023, IndiGo has placed several aircraft orders. Last Sunday, it announced an order for 30 additional Airbus A320neo widebody planes, adding to its April 2024 order for 30 A320s, bringing its total widebody order to 60 aircraft. Deliveries will begin in 2027 and continue into the

next decade. These widebody planes, which have larger fuel tanks than narrow-body A320s, are key to IndiGo's long-haul expansion, targeting routes like India-US, India-Europe, and India-Australia to compete with Air India and Gulf carriers.

The recent widebody orders followed IndiGo's record-breaking June 2023 order for 50 Airbus A320neo family aircraft to boost its narrow-body fleet for domestic and short-haul

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED)

Corporate Identification Number: L74140MPT984PLC002592
Registered Office: 232, Part-B, The Zodiac Mall, Bichol, Marolund, Indore (M.P.) - 452001
Contact Details: 7383330911 | Email-ID: info@indraindustries.in | Website: www.indraindustries.in

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE ISSUE

RIGHTS ISSUE OF UP TO 4,85,78,025 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) (EQUITY SHARES) EACH AT A PRICE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) PER EQUITY SHARE (EIGHTY SHARES) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹ 48,57,80,250 (RUPEES FORTY EIGHT CRORE FIFTY SEVEN LAKHS EIGHTY THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED) (COMPANY OR ISSUER) AT THE RATIO OF 15 (FIFTEEN) EQUITY SHARES FOR EVERY 2 (TWO) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, THURSDAY MAY 09, 2025 (ISSUE). THE ISSUE PRICE IS 1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE BEGINNING PAGE 130 OF THIS LETTER OF OFFER.'

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") - ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MAY 9, 2025

This notice should be read in conjunction with the LDF filed by the Company with the Stock Exchange and the ADFP and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please read the following:

This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday 23rd May 2025 and was scheduled to close on Wednesday, Friday 06th June 2025, has now been extended to Monday, June 09, 2025, by the Rights Issue Committee in meeting held on June 06, 2025 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Monday, 09, June, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, 09, June, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE

ISSUE OPENING DATE	ISSUE CLOSING DATE
FRIDAY 23RD MAY 2025	MONDAY 09TH MAY 2025

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

**Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms or on before the Issue Closing Date.

#Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the renunciatee (on or prior to the Issue Closing Date).

This addendum shall be available on the respective websites of the Company at info@indraindustries.in in the Registrar to the Issue at www.purushare.com and the Stock Exchanges at www.bseindia.com.

Accordingly, there is no change in the LDF and ADFP dated May 09, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing Date. Please note the Issue Closing Date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date.

INVESTORS MAY CHANGE THE LETTER OF OFFER, ABBREVED LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.

All capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For Bluegod Entertainment Limited
(Formerly Known As Indra Industries Limited) Sd/-
Nitinshankar Kumar Khanna
Managing Director

Date: May 09, 2025
Place: Indore

Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
CIN: 69808

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the BSE Limited. The Draft Letter of Offer is available on the website of Stock Exchanges where the Equity Shares are listed, i.e. BSE at www.bseindia.com, Our Company at info@indraindustries.in and the Registrar to the Issue at www.purushare.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Draft Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 31 of the Draft Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

LLOYDS ENTERPRISES LIMITED
Registered Address: A-2, 2nd Floor, Madhu Estate,
Punarnagar, Borivali, Mumbai, Maharashtra - 400013
Tel: 022-6911 9111 Email: lloydenterprises@lloyds.in www.lloydenterprises.in
(CIN) L27100MH1988PLC041252

NOTICE FOR POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION
MEMBERS ARE HEREBY INFORMED THAT:

In compliance with Section 108 and 110 of Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Act" including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Rules" including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies Act, 2013, 17/2020 dated April 13, 2020, read with other relevant circulars, including General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (the "SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretarial Standards on General Circular No. 09/2023 and Secretarial Standards on General Circular No. 09/2024 issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), Lloyds Enterprises Limited (the "Company") has completed dispatch of Postal Ballot Notice along with explanatory statement on Friday, 06th June, 2025 through electronic mode only to those Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited or with their Depository Participant(s) on Friday, 30th May, 2025 ("cut-off date"). The requirement of sending physical copy of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form has been dispensed with vide relevant MCA circulars.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mitesh Shah, Partner of Mitesh Shah & Co., Practising Company Secretary (FCS No. 10070 and CP No. 12891), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and Postal Ballot.

In this regard, the Members are hereby informed that:

- a. The Business relating to approval of:

Sl. No.	Type of Resolution	Description of Resolution
1.	Special Resolution	Approval for Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
2.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Subsidiary Companies in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
3.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Associate Company in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
4.	Special Resolution	Approval for the provision of loan by the Company for the purchase of its own shares by the trust / trustees for the benefit of employees under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
5.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Engineering Works Limited (formerly known as Lloyds Steel Industries Limited).
6.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals and Energy Limited.
7.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Realty Developers Limited.
8.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Indrajit Properties Private Limited.
9.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Infrastructure & Construction Limited.
10.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals & Minerals Trading LLP.

b. The e-voting period commences from Saturday, 07th June, 2025 (09:00 AM (IST)).

c. The e-voting period ends on Sunday, 08th June, 2025 (05:00 PM (IST)) when remote e-voting will be blocked and voting shall not be allowed beyond the said time.

d. Only those Members, whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date, i.e., Friday, 30th May, 2025 are entitled to cast their votes on the Resolutions. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.

e. Members who have not received Postal Ballot Notice may write to investor@lloydenterprises.in and obtain the same.

f. For any query or grievance connected with the voting by electronic means, members may address to Mr. Rakesh Dahiya, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 29 Floor, Marathon Floor, Malabar Hill Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk@cDSL.com or call on 022-23058424/43. Members may also write to the Company at the Email ID: investor@lloydenterprises.in

Members who have not registered their e-mail address with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company/Depository Participant, are requested to register by completing the process for registration of email address as under:

• Members holding shares in physical form can get their E-mail Ids registered by contacting their respective Depository Participant.

• Members holding shares in demat form can get their E-mail Ids registered by contacting our Registrar and Share Transfer Agent "Bigshare Services Private Limited" or their Email ID investor@lloydenterprises.in along with relevant documents to our Registrar and Share Transfer Agent Office No. 307, 3rd Floor, Punarnagar Business Park, next to Anura Centre, Malabar Cross Road, Andheri (East), Mumbai - 400095.

• The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.lloydenterprises.in and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of CDSL at www.evotingindia.com

Result of Postal Ballot shall be declared within two working days from the conclusion of the Postal Ballot and shall be displayed on the Company's website at www.lloydenterprises.in and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of NSDL at www.evotingindia.com

For Lloyds Enterprises Limited Sd/-
Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
CIN: 69808

Place: Mumbai
Date: 06th June, 2025

ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED
Regd. Office: 18th floor, A Wing, Marathon Futurax,
N.M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013
Tel: 91 22 7106 1234 Fax: 91 22 2001 2107
CIN: L92132MH1982PLC028767
Website: www.zee.com

NOTICE OF THE POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ("Act") including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations), the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, other Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars") and other applicable laws, each as amended, seeking approval of the Members of Zee Entertainment Enterprises Limited (the "Company"), on the Resolutions set forth in the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025.

Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025 along with explanatory statement through electronic mode on June 6, 2025 to those Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners and whose e-mail IDs are registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent (RTA)/ Depository Participant(s) ("DPs") as on the cut-off date i.e. Friday, May 30, 2025. Accordingly, a physical copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

The Members, whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, May 30, 2025, being the cut-off date, are entitled to vote on the Resolutions set forth in Postal Ballot Notice through remote e-voting only. The voting rights of Members shall be in proportion to their shareholdings in the equity share capital of the Company as on the said cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Company has obtained the services of National Securities Depository Limited ("NSDL"), for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure for remote e-voting is given in the Postal Ballot Notice. The remote e-voting period will commence Monday, June 9, 2025, at 9:00 a.m. (IST) and conclude on Tuesday, June 8, 2025, at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting will be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on resolutions is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The resolutions passed by the Members through the Postal Ballot (through remote e-voting) shall be deemed to have been passed as it has been passed at a General Meeting of the Members. The resolutions, if approved by the requisite majority of Members by means of Postal Ballot, shall be deemed to have been passed on the last date of remote e-voting, i.e. on July 8, 2025.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by sending a mail along with the relevant documents to the Company's RTA, MIFUG Intime India Private Limited (earlier known as Link Intime India Private Limited, Unit: Zee Entertainment Enterprises Limited, C 101, 247, L B S Marg, Vikhroli West-400083 or the scanned copies of the documents may alternatively be mailed to RTA at mt.helpdesk@in.mps.mifug.com or to the Company at share@zee.com. Members holding shares in demat form who have not updated their email addresses with the depository participant are requested to update their email addresses.

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website i.e. www.zee.com and also on the website of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evotingindia.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Vinita Nair, (Membership No. F10559, COP No. 11902) Joint Managing Partner, M/s. Vinod Kohari & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of the e-voting by Postal Ballot will be announced on or before Wednesday, June 9, 2025. The result declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website i.e. www.zee.com and on the website of NSDL www.evotingindia.com. The Company shall simultaneously intimate to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed.

In case of any query on remote e-voting, Members may refer to FAQs and/or e-voting user manual available on website of NSDL at www.evotingindia.com or call on toll free no. 022-4986 7000.

By Order of the Board
For Zee Entertainment Enterprises Limited Sd/-

Over 7% flights cancelled for 3 mths at Delhi airport

DIAL CEO cites runway upgrade as reason for cancellations

DEEPAK PATEL
New Delhi, 6 June

About 7.5 per cent daily flights to and from the Delhi airport will be cancelled between June 15 and September 15 as one of its four runways undergoes an upgrade, Delhi International Airport Limited (DIAL) Chief Executive Officer (CEO) Videsh Kumar Jaipuria said on Friday.

GMR Group-led DIAL operates the Delhi airport, which is the largest in the country.

"The Delhi airport handles 1,45,000 aircraft movements per day. Of these, 114 daily movements will be cancelled during the runway upgrade," Jaipuria said at a press conference.

"The number of cancellations will be in the range of 7-7.5 per cent, compared to the usual 3-4 per cent on a normal day. However, this time we have coordinated with airlines in advance and rescheduled flights accordingly, which will help reduce any cascading impact," he said.

Referring to a similar upgrade effort earlier this year, he added, "Last time, the lack of proper rescheduling led to cascading disruptions when wind patterns changed. This time, the impact on passengers will be much lower. Since they've been informed in advance, they will have enough time to rebook or make alternative arrangements."

The upgrade of runway 10/28 will include installing an instrument landing system (ILS) and make it compliant with CAT III-B operations. CAT III-B is a precision landing system that allows aircraft to land in very low visibility conditions, such as dense fog.

It was originally scheduled for April-May. However, unexpected changes in wind patterns during that time severely affected flight operations, causing delays.

As a result, the Ministry of Civil Aviation — on April 21 — directed DIAL to postpone the upgrade and resume oper-



The airport will see flight cancellations between June 15 and September 15.

ations on the runway. The runway was made operational again on May 6, and the upgrade was deferred to June 15-September 15.

"The revised timeline was agreed upon by all airlines," Jaipuria said.

Following this, airlines collaborated with DIAL to rework slot allocations and align with the revised arrival capacity.

"The objective was to ensure optimum use of available runway capacity while maintaining on-time performance," he added.

"During the fog season, the arrival capacity of all runways comes down due to safety concerns, as arriving aircraft have to be spaced out," Jaipuria said.

"In case of westerly winds, arrivals drop from 42 per hour to 30 during CAT III-B operations. But with easterly winds, arrivals fall sharply from 42 per hour to just 15. Once the upgrade is complete, this number will go up to 30 even with easterly winds, significantly improving efficiency," he added.

"Every hour of fog disruption takes

Akasa to launch over 100 weekly flights from Navi Mumbai airport

Akasa Air will start more than 100 weekly domestic flights from the upcoming Navi Mumbai International Airport (NMI), expanding to more than 300 domestic and over 50 international weekly departures in the winter schedule, it said on Friday.

Akasa joins IndiGo in confirming its early commitment to NMI.

"No airline in India will have a larger percentage of its fleet and operations based out of NMI than Akasa Air," said Vinay Dube, founder and chief executive officer (CEO) of Akasa Air.

AHIL CEO Arun Bansal welcomed Akasa as an inaugural partner, stressing the airline's rapid growth and forward-looking approach.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

three hours for us to return to normal operations. This becomes much worse with easterly winds, where every hour of disruption takes six hours to recover. This impacts not just Delhi airport but also nearby ones."

Therefore, we decided to upgrade runway 10/28 and make it ready to handle CAT III-B flight operations," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

'By 2030, 80% of our new onboardings will be EVs'

Logistics startup Porter is aiming to bring in more driver partners and customers into its fold. In a video interaction with Uditsha Srivastava, cofounder and executive vice-chairman, Praveen Goel, talks about the recent fundraising, how the amount is being used, the company's expansion plans and partnership with ONDC, among others. Edited excerpts:

Let us know about the company's recent fundraising and how is the amount being used?

■ It's been a fairly large fundraise, a mix of both primary and secondary capital. With this amount, we want to go deeper and launch more categories. Over the years, we realised that there's still 20 per cent of customers that we are not able to service.

■ Delhi is the biggest city, because of different requirements. So, the intent is to solve that. E-loader is one segment that we want to launch across India. The other big objective is to go wider and replicate the same business model into multiple cities in India.

■ Also, launch in more international geographies where this model makes sense.

What are the target for the years to come?

■ In the next five years, we will move from 2 million to 10 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver

partners, and that number will exceed 1.2 million. We are present in close to 22 cities in India and this number will be around 50 cities.

■ There is also a massive sustainability goal. (EVs).

What are the top cities of operations for Porter? Which vehicle categories are the high-frequency ones?

■ Delhi is the biggest city, given its size and scale. After Delhi, there are Mumbai and Bengaluru. Chennai, Hyderabad, and Ahmedabad follow. We probably have around 10 vehicle categories and they're fairly distributed. We have four high-frequency categories, including two-wheelers, three-wheelers, and entry-level four-wheelers. They represent 80 per cent of our revenues. The other six categories comprise nearly 20 per cent of the revenues.

Do you also have fleet partners or is it a driver-owned model completely?

■ We are a completely asset-light model where the driver-partner has his vehicle. In



IN THE NEXT FIVE YEARS, WE WILL MOVE FROM 2 MILLION SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES WHO COME TO THE PLATFORM EVERY MONTH TO SERVICING MORE THAN 10 MILLION CUSTOMERS

more than 90 per cent of the cases, the owner and the driver are one person. We also have fleet operators, but they comprise less than 10 per cent of our volumes. There are more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

What's the company's revenue breakdown?

■ Around 85 per cent of our revenue comes from micro, small, and medium enter-

prises (MSMEs), which are local retail stores, small manufacturers, furniture shops, paints and chemicals shops, among others. Then, more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

FROM PAGE 1

Experts flag infra limitations at major airports as hurdle for ATR operations

The Indian carrier, which currently operates a fleet of about 46 ATR 72-600s, had earlier placed an order for 50 such aircraft in 2017 as part of a strategy to expand its regional footprint under the government's UDAN

scheme to improve air connectivity to underserved towns. Four aircraft since have been sold or leased to other.

Deliveries under that contract were completed by early 2025.

The ATR 72-600 is a twin-engine turboprop aircraft typically seating around 70 passengers, although IndiGo configures its planes in a high-density 78-seat layout. The aircraft is primarily deployed on short regional routes, with a range of about 1,370km.

"IndiGo has utilised the ATRs on all sorts of routes, from monopoly under regional connectivity scheme UDAN to some intra-metro high frequency ones in South India," said Ameya Joshi, aviation analyst and founder of the blog Network Thoughts. "The airline has also experimented with routes, some working well and some not continuing," he said.

The turboprop fleet enabled IndiGo to expand its network to smaller destinations such as Kolhapur, Kishanganj and Kadapa, which are not feasible for the airline's Airbus fleet, according to Joshi.

But the also flagged infrastructure limitations at major airports as a major hurdle for ATR operations. "One of the biggest challenges has been getting slots at Delhi or Mumbai for the ATR," he said. "The development of secondary airports — like Navi Mumbai and Jewar — could ease this constraint and support rapid network expansion. How much does the government incentivise going forward also needs to be seen."

Since 2023, IndiGo has placed several aircraft orders. Last Sunday, it announced an order for 30 additional Airbus A320neo widebody planes, adding to its April 2024 order for 30 A320s, bringing its total widebody order to 60 aircraft. Deliveries will begin in 2027 and continue into the

next decade. These widebody planes, which have larger fuel tanks than narrow-body A320s, are key to IndiGo's long-haul expansion, targeting routes like India-US, India-Europe, and India-Australia to compete with Air India and Gulf carriers.

The recent widebody orders followed IndiGo's record-breaking June 2023 order for 50 Airbus A320neo family aircraft to boost its narrow-body fleet for domestic and short-haul

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent widebody orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalised terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated May 09, 2025 the "Letter of Offer" or "LOF" filed with BSE Limited ("BSE").

BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED)

Corporate Identification Number: L74140MPP1984PLC002592
Registered Office: 232 Park Street, The Zodiac Mall, Bicholi, Madurai, Andhra Pradesh (AP), 520001
Contact Details: 7383380911 | Email-ID: info@indraindustries.in | Website: www.indraindustries.in

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE ISSUE
RIGHTS ISSUE OF UP TO 4,85,78,025 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) (EQUITY SHARES) EACH AT A PRICE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) PER EQUITY SHARE (EIGHTY SHARES) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹ 48,57,80,250/- (RUPEES FORTY EIGHT CRORE FIFTY SEVEN LAKHS EIGHTY THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED) (COMPANY OR ISSUER) AT THE RATIO OF 15 (FIFTEEN) EQUITY SHARES FOR EVERY 2 (TWO) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, THURSDAY MAY 09, 2025 (ISSUE). THE ISSUE PRICE IS 1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE BEGINNING PAGE 130 OF THIS LETTER OF OFFER.'

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") - ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MAY 9, 2025
This notice should be read in conjunction with the LOF filed by the Company with the Stock Exchange and the ADFP and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please read the following:

This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday 23rd May 2025 and was scheduled to close on Wednesday, Friday 06th June 2025, has now been extended to Monday, June 09, 2025, by the Rights Issue Committee in meeting held on June 06, 2025 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Monday, 09, June, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, 09, June, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE

ISSUE OPENING DATE	ISSUE CLOSING DATE
FRIDAY 23RD MAY 2025	MONDAY 09TH MAY 2025

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).
**Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms or on before the Issue Closing Date.
#Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renunciatee (on or prior to the Issue Closing Date).
This addendum shall be available on the respective websites of the Company at info@indraindustries.in the Registrar to the Issue at www.purushare.com and the Stock Exchanges at www.bseindia.com.

Accordingly, there is no change in the LOF and ADFP dated May 09, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing Date. Please Note the Issue Closing Date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of Issue Closing Date.
INVESTORS MAY CHANGE THE LETTER OF OFFER, ABROGATED LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.
All capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For Bluegod Entertainment Limited
(Formerly Known As Indra Industries Limited)
Sd/-
Nitinashok Kumar Khanna
Managing Director

Date: May 09, 2025
Place: Indore

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the BSE Limited. The Draft Letter of Offer is available on the website of Stock Exchanges where the Equity Shares are listed, i.e. BSE at www.bseindia.com, Our Company at info@indraindustries.in and the Registrar to the Issue at www.purushare.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Draft Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 31 of the Draft Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

For Lloyds Enterprises Limited
Sd/-
Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 06th June, 2025

Place: Mumbai

LLOYDS ENTERPRISES LIMITED
Registered Address: A-2, 2nd Floor, Madhu Estate,
Parvathy Bahadur Marg, Lower Park, Mumbai - 400013
Tel: 022-6911 9111 Email: lloydsevents@lloyds.in www.lloydsevents.in
(CIN) L27100MH1988PLC041252

NOTICE FOR POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION
MEMBERS ARE HEREBY INFORMED THAT:

In compliance with Section 108 and 110 of Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Act" including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Rules" including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), Lloyds Enterprises Limited (the "Company") has completed dispatch of Postal Ballot Notice along with explanatory statement on Friday, 06th June, 2025 through electronic mode only to those Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited or with their Depositories/Depository Participants on Friday, 30th May, 2025 ("Cut-off Date"). The requirement of sending physical copy of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form has been dispensed with vide relevant MCA circulars.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mitesh Shah, Partner of Mitesh Shah & Co., Practising Company Secretary (FCS No. 10070 and CP No. 12891), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and Postal Ballot.

In this regard, the Members are hereby informed that:

a. The Business relating to approval of:

Sl. No.	Type of Resolution	Description of Resolution
1.	Special Resolution	Approval for Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
2.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Subsidiary Companies in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
3.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Associate Company, in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
4.	Special Resolution	Approval for the provision of loan by the Company for the purchase of its own shares by the trust / trustees for the benefit of employees under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
5.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Engineering Works Limited (formerly known as Lloyds Steel Industries Limited).
6.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals and Energy Limited.
7.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Realty Developers Limited.
8.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Indrajit Properties Private Limited.
9.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Infrastructure & Construction Limited.
10.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals & Minerals Trading LLP.

b. The e-voting period commences from Saturday, 07th June, 2025 (09:00 AM (IST)).

c. The e-voting period ends on Sunday, 08th June, 2025 (05:00 PM (IST)) when remote e-voting will be blocked and voting shall not be allowed beyond the said time.

d. Only those Members, whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date, i.e., Friday, 30th May, 2025 are entitled to cast their votes on the Resolutions. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.

e. Members who have not received Postal Ballot Notice may write to investor@lloydsevents.in and obtain the same.

f. For any query or grievance connected with the voting by electronic means, members may address to Mr. Rakesh Dahiya, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 29th Floor, Marathon Floor, Malabar Hill Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Park (E), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk@cDSL.com or call on 022-23058424/43. Members may also write to the Company at the Email ID: investor@lloydsevents.in

Members who have not registered their e-mail address with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company/Depository Participant, are requested to register by completing the process for registration of email address as under:

• Members holding shares in physical form can get their E-mail Ids registered by contacting their respective Depository Participant.

• Members holding shares in demat form can get their E-mail Ids registered by contacting our Registrar and Share Transfer Agent "Bigshare Services Private Limited" or their Email ID investor@lloydsevents.in along with relevant documents to our Registrar and Share Transfer Agent Office No. 30th Floor, Lower Park, next to Anura Centre, Malabar Cross Road, (Andhra) Estate, Mumbai - 400005.

• The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.lloydsevents.in and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of CDSL at www.evotingindia.com

Result of Postal Ballot shall be declared within two working days from the conclusion of the Postal Ballot and shall be displayed on the Company's website at www.lloydsevents.in and on the websites of the Registrar and Share Transfer Agent "Bigshare Services Private Limited" or other communication to Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The Scrutinizer's decision on validity of the Postal Ballot shall be final.

For Lloyds Enterprises Limited
Sd/-
Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 06th June, 2025

Place: Mumbai

ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED
Regd. Office: 18th floor, A Wing, Marathon Futurex,
N.M. Joshi Marg, Lower Park, Mumbai 400 013
Tel: 91 22 7106 1234 Fax: 91 22 2001 2107
CIN: L92132MH1982PLC028767
Website: www.zee.com

NOTICE OF THE POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION
NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ("Act") (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, other Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars") and other applicable laws, each as amended, seeking approval of the Members of Zee Entertainment Enterprises Limited (the "Company"), on the Resolutions set forth in the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025.

Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025 along with explanatory statement through electronic mode on June 6, 2025 to those Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners and whose e-mail IDs are registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) / Depository Participants ("DPs") as on the cut-off date i.e. Friday, May 30, 2025. Accordingly, a physical copy of the Postal Ballot Notice with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

The Members, whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, May 30, 2025, being the cut-off date, are entitled to vote on the Resolutions set forth in Postal Ballot Notice through remote e-voting only. The voting rights of Members shall be in proportion to their shareholdings in the equity share capital of the Company as on the said cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Company has obtained the services of National Securities Depository Limited ("NSDL"), for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure for remote e-voting is provided in the Postal Ballot Notice. The remote e-voting period will commence Monday, June 9, 2025, at 9:00 a.m. (IST) and conclude on Tuesday, June 8, 2025, at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting will be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on resolutions is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The resolutions passed by the Members through the Postal Ballot (through remote e-voting) shall be deemed to have been passed as it has been passed at a General Meeting of the Members. The resolutions, if approved by the requisite majority of Members by means of Postal Ballot, shall be deemed to have been passed on the last date of remote e-voting, i.e. on July 8, 2025.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by sending a mail along with the relevant documents to the Company's RTA, MIFUG Intime India Private Limited (earlier known as Link Intime India Private Limited, Unit: Zee Entertainment Enterprises Limited, C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West-400083 or the scanned copies of the documents may alternatively be mailed to RTA at mt.helpdesk@in.mps.mifug.com or to the Company at share@zee.com. Members holding shares in demat form who have not updated their email addresses with the depository/ depository participant are requested to approach the concerned depository participant to update their email addresses.

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website i.e. www.zee.com and also on the website of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evotingindia.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Vinita Nair, (Membership No. F10559, COP No.11902) Joint Managing Partner, M/s. Vinod Kohari & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of the e-voting by Postal Ballot will be announced on or before Wednesday, July 9, 2025. The result declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website i.e. www.zee.com and on the website of NSDL www.evotingindia.com. The Company shall simultaneously intimate to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed.

In case of any query on remote e-voting, Members may refer to FAQs and/or e-voting user manual available on website of NSDL at www.evotingindia.com or call on toll free no. 022-4986 7000.

By Order of the Board
For Zee Entertainment Enterprises Limited
Sd/-
Ashish Agarwal
Company Secretary
Date: June 3, 2025

Place: Mumbai

Membership No. FCS 6669

Over 7% flights cancelled for 3 mths at Delhi airport

DIAL CEO cites runway upgrade as reason for cancellations

DEEPAK PATEL
New Delhi, 6 June

About 7.5 per cent daily flights to and from the Delhi airport will be cancelled between June 15 and September 15 as one of its four runways undergoes an upgrade, Delhi International Airport Limited (DIAL) Chief Executive Officer (CEO) Vaidh Kumar Jaipuria said on Friday.

GMR Group-led DIAL operates the Delhi airport, which is the largest in the country.

"The Delhi airport handles 1,450 aircraft movements per day. Of these, 114 daily movements will be cancelled during the runway upgrade," Jaipuria said at a press conference.

"The number of cancellations will be in the range of 7-7.5 per cent, compared to the usual 3-4 per cent on a normal day. However, this time we have coordinated with airlines in advance and rescheduled flights accordingly, which will help reduce any cascading impact," he said.

Referring to a similar upgrade effort earlier this year, he added, "Last time, the lack of proper rescheduling led to cascading disruptions when wind patterns changed. This time, the impact on passengers will be much lower. Since they've been informed in advance, they will have enough time to rebook or make alternative arrangements."

The upgrade of runway 10/28 will include installing an instrument landing system (ILS) and make it compliant with CAT III-B operations. CAT III-B is a precision landing system that allows aircraft to land in very low visibility conditions, such as dense fog.

It was originally scheduled for April-May. However, unexpected changes in wind patterns during that time severely affected flight operations, causing delays.

As a result, the Ministry of Civil Aviation — on April 21 — directed DIAL to postpone the upgrade and resume oper-



The airport will see flight cancellations between June 15 and September 15.

ations on the runway. The runway was made operational again on May 6, and the upgrade was deferred to June 15-September 15.

"The revised timeline was agreed upon by all airlines," Jaipuria said.

Following this, airlines collaborated with DIAL to rework slot allocations and align with the revised arrival capacity.

"The objective was to ensure optimum use of available runway capacity while maintaining on-time performance," he added.

"During the fog season, the arrival capacity of all runways comes down due to safety concerns, as arriving aircraft have to be spaced out," Jaipuria said.

"In case of westerly winds, arrivals drop from 42 per hour to 30 during CAT III-B operations. But with easterly winds, arrivals fall sharply from 42 per hour to just 15. Once the upgrade is complete, this number will go up to 30 even with easterly winds, significantly improving efficiency," he added.

"Every hour of fog disruption takes

Akasa to launch over 100 weekly flights from Navi Mumbai airport

Akasa Air will start more than 100 weekly domestic flights from the upcoming Navi Mumbai International Airport (NMAIA), expanding to more than 300 domestic and over 50 international weekly departures in the winter schedule, it said on Friday.

Akasa joins IndiGo in confirming its early commitment to NMAIA.

"No airline in India will have a larger percentage of its fleet and operations based out of NMAIA than Akasa Air," said Vinay Dube, founder and chief executive officer (CEO) of Akasa Air.

AAHL CEO Arun Bansal welcomed Akasa as an inaugural partner, stressing the airline's rapid growth and forward-looking approach.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

three hours for us to return to normal operations. This becomes much worse with easterly winds, where every hour of disruption takes six hours to recover. This impacts not just Delhi airport but also nearby ones."

Therefore, we decided to upgrade runway 10/28 and make it ready to handle CAT III-B flight operations," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

FROM PAGE 1

Experts flag infra limitations at major airports as hurdle for ATR operations

The Indian carrier, which currently operates a fleet of about 46 ATR 72-600s, had earlier placed an order for 50 such aircraft in 2017 as part of a strategy to expand its regional footprint under the government's UDAN scheme to improve air connectivity to underserved towns. Four aircraft since have been sold or leased to other.

Deliveries under that contract were completed by early 2025.

The ATR 72-600 is a twin-engine turboprop aircraft typically seating around 70 passengers, although IndiGo configures its planes in a high-density 78-seat layout. The aircraft is primarily deployed on short regional routes, with a range of about 1,370km.

"IndiGo has utilised the ATRs on all sorts of routes, from monopoly under regional connectivity scheme UDAN to some intra-metro high frequency ones in South India," said Ameya Joshi, aviation analyst and founder of the blog Network Thoughts. "The airline has also experimented with routes, some working well and some not continuing," he said.

The turboprop fleet enabled IndiGo to expand its network to smaller destinations such as Kolhapur, Kishanganj and Kadapa, which are not feasible for the airline's Airbus fleet, according to Joshi.

But the also flagged infrastructure limitations at major airports as a major hurdle for ATR operations. "One of the biggest challenges has been getting slots at Delhi or Mumbai for the ATR," he said. "The development of secondary airports — like Navi Mumbai and Jewar — could ease this constraint and support rapid network expansion. How much does the government incentivise going forward also needs to be seen."

Since 2023, IndiGo has placed several aircraft orders. Last Sunday, it announced an order for 30 additional Airbus A320neo Widebody planes, adding to its April 2024 order for 30 A320s, bringing its total widebody order to 60 aircraft. Deliveries will begin in 2027 and continue into the

next decade. These widebody planes, which have larger fuel tanks than narrow-body A320s, are key to IndiGo's long-haul expansion, targeting routes like India-US, India-Europe, and India-Australia to compete with Air India and Gulf carriers.

The recent widebody orders followed IndiGo's record-breaking June 2023 order for 50 Airbus A320neo family aircraft to boost its narrow-body fleet for domestic and short-haul

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 430 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

'By 2030, 80% of our new onboardings will be EVs'

Logistics startup Porter is aiming to bring in more driver partners and customers into its fold. In a video interaction with Uditsha Srivastava, cofounder and executive vice-chairman, Praveen Goel, talks about the recent fundraising, how the amount is being used, the company's expansion plans and partnership with ONDC, among others. Edited excerpts:

Let us know about the company's recent fundraising and how is the amount being used?

It's been a fairly large fundraise, a mix of both primary and secondary capital. With this amount, we want to go deeper and launch more categories. Over the years, we realised that there's still 20 per cent of customers that we are not able to service.

Delhi is the biggest city, because of different requirements. So, the intent is to solve that. E-loader is one segment that we want to launch across India. The other big objective is to go wider and replicate the same business model into multiple cities in India.

Also, launch in more international geographies where this model makes sense.

What are the target for the years to come?

In the next five years, we will move from 2 million to 10 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver

partners, and that number will exceed 1.2 million. We are present in close to 22 cities in India and this number will be around 50 cities.

There is also a massive sustainability goal. (EVs).

What are the top cities of operations for Porter? Which vehicle categories are the high-frequency ones?

Delhi is the biggest city, given its size and scale. After Delhi, there are Mumbai and Bengaluru. Chennai, Hyderabad, and Ahmedabad follow. We probably have around 10 vehicle categories and they're fairly distributed. We have four high-frequency categories, including two-wheelers, three-wheelers, and entry-level four-wheelers. They represent 80 per cent of our revenues. The other six categories comprise nearly 20 per cent of the revenues.

Do you also have fleet partners or is it a driver-owned model completely?

We are a completely asset-light model where the driver-partner has his vehicle. In



IN THE NEXT FIVE YEARS, WE WILL MOVE FROM 2 MILLION SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES WHO COME TO THE PLATFORM EVERY MONTH TO SERVICING MORE THAN 10 MILLION CUSTOMERS

more than 90 per cent of the cases, the owner and the driver are one person. We also have fleet operators, but they comprise less than 10 per cent of our volumes. There are more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

What's the company's revenue breakdown?

Around 85 per cent of our revenue comes from micro, small, and medium enter-

prises (MSMEs), which are local retail stores, small manufacturers, furniture shops, paints and chemicals shops, among others. Then, more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

LLOYDS ENTERPRISES LIMITED
Registered Address: A-2, 2nd Floor, Madhu Estate, Parkside, Bandra West, Mumbai - 400015
Tel: 022-6911 9111 Email: lloydsecurities@lloyds.in www.lloydsecurities.in
(CIN) L27100MH1988PLC041252

NOTICE FOR POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION
MEMBERS ARE HEREBY INFORMED THAT:

In compliance with Section 108 and 110 of Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Act" including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Rules") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretariat Standards on General Circular No. 09/2024 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("SEBI

Over 7% flights cancelled for 3 mths at Delhi airport

DIAL CEO cites runway upgrade as reason for cancellations

DEEPAK PATEL
New Delhi, 6 June

About 7.5 per cent daily flights to and from the Delhi airport will be cancelled between June 15 and September 15 as one of its four runways undergoes an upgrade, Delhi International Airport Limited (DIAL) Chief Executive Officer (CEO) Videsh Kumar Jaipuria said on Friday.

GMR Group-led DIAL operates the Delhi airport, which is the largest in the country.

"The Delhi airport handles 1,450 aircraft movements per day. Of these, 114 daily movements will be cancelled during the runway upgrade," Jaipuria said at a press conference.

"The number of cancellations will be in the range of 7-7.5 per cent, compared to the usual 3-4 per cent on a normal day. However, this time we have coordinated with airlines in advance and rescheduled flights accordingly, which will help reduce any cascading impact," he said.

Referring to a similar upgrade effort earlier this year, he added, "Last time, the lack of proper rescheduling led to cascading disruptions when wind patterns changed. This time, the impact on passengers will be much lower. Since they've been informed in advance, they will have enough time to rebook or make alternative arrangements," he added.

The upgrade of runway 10/28 will include installing an instrument landing system (ILS) and make it compliant with CAT III-B operations. CAT III-B is a precision landing system that allows aircraft to land in very low visibility conditions, such as dense fog.

It was originally scheduled for April-May. However, unexpected changes in wind patterns during that time severely affected flight operations, causing delays.

As a result, the Ministry of Civil Aviation — on April 21 — directed DIAL to postpone the upgrade and resume oper-



The airport will see flight cancellations between June 15 and September 15.

ations on the runway. The runway was made operational again on May 6, and the upgrade was deferred to June 15-September 15.

"The revised timeline was agreed upon by all airlines," Jaipuria said.

Following this, airlines collaborated with DIAL to rework slot allocations and align with the revised arrival capacity.

"The objective was to ensure optimum use of available runway capacity while maintaining on-time performance," he added.

"During the fog season, the arrival capacity of all runways comes down due to safety concerns, as arriving aircraft have to be spaced out," Jaipuria said.

"In case of westerly winds, arrivals drop from 42 per hour to 30 during CAT III-B operations. But with easterly winds, arrivals fall sharply from 42 per hour to just 15. Once the upgrade is complete, this number will go up to 30 even with easterly winds, significantly improving efficiency," he added.

"Every hour of fog disruption takes

Akasa to launch over 100 weekly flights from Navi Mumbai airport

Akasa Air will start more than 100 weekly domestic flights from the upcoming Navi Mumbai International Airport (NMI), expanding to more than 300 domestic and over 50 international weekly departures in the winter schedule, it said on Friday.

Akasa joins IndiGo in confirming its early commitment to NMI.

"No airline in India will have a larger percentage of its fleet and operations based out of NMI than Akasa Air," said Vinay Dube, founder and chief executive officer (CEO) of Akasa Air.

AHIL CEO Arun Bansal welcomed Akasa as an inaugural partner, stressing the airline's rapid growth and forward-looking approach.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

three hours for us to return to normal operations. This becomes much worse with easterly winds, where every hour of disruption takes six hours to recover. This impacts not just Delhi airport but also nearby ones."

Therefore, we decided to upgrade runway 10/28 and make it ready to handle CAT III-B flight operations," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

'By 2030, 80% of our new onboardings will be EVs'

Logistics startup Porter is aiming to bring in more driver partners and customers into its fold. In a video interaction with Uditsha Srivastava, cofounder and executive vice-chairman, Praveen Goel, talks about the recent fundraising, how the amount is being used, the company's expansion plans and partnership with ONDC, among others. Edited excerpts:

Let us know about the company's recent fundraising and how is the amount being used?

■ It's been a fairly large fundraise, a mix of both primary and secondary capital. With this amount, we want to go deeper and launch more categories. Over the years, we realised that there's still 20 per cent of customers that we are not able to service.

■ Delhi is the biggest city, because of different requirements. So, the intent is to solve that. E-loader is one segment that we want to launch across India. The other big objective is to go wider and replicate the same business model into multiple cities in India.

■ Also, launch in more international geographies where this model makes sense.

What are the targets for the years to come?

■ In the next five years, we will move from 2 million to 10 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver

partners, and that number will exceed 1.2 million. We are present in close to 22 cities in India and this number will be around 50 cities.

■ There is also a massive sustainability goal. (EVs).

What are the top cities of operations for Porter? Which vehicle categories are the high-frequency ones?

■ Delhi is the biggest city, given its size and scale. After Delhi, there are Mumbai and Bengaluru. Chennai, Hyderabad, and Ahmedabad follow. We probably have around 10 vehicle categories and they're fairly distributed. We have four high-frequency categories, including two-wheelers, three-wheelers, and entry-level four-wheelers. They represent 80 per cent of our revenues. The other six categories comprise nearly 20 per cent of the revenues.

Do you also have fleet partners or is it a driver-owned model completely?

■ We are a completely asset-light model where the driver-partner has his vehicle. In



IN THE NEXT FIVE YEARS, WE WILL MOVE FROM 2 MILLION SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES WHO COME TO THE PLATFORM EVERY MONTH TO SERVICING MORE THAN 10 MILLION CUSTOMERS

more than 90 per cent of the cases, the owner and the driver are one person. We also have fleet operators, but they comprise less than 10 per cent of our volumes. There are more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

What's the company's revenue breakdown?

■ Around 85 per cent of our revenue comes from micro, small, and medium enter-

prises (MSMEs), which are local retail stores, small manufacturers, furniture shops, paints and chemicals shops, among others. Then, more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

FROM PAGE 1

Experts flag infra limitations at major airports as hurdle for ATR operations

The Indian carrier, which currently operates a fleet of about 46 ATR 72-600s, had earlier placed an order for 50 such aircraft in 2017 as part of a strategy to expand its regional footprint under the government's UDAN

scheme to improve air connectivity to underserved towns. Four aircraft since have been sold or leased to other.

Deliveries under that contract were completed by early 2025.

The ATR 72-600 is a twin-engine turboprop aircraft typically seating around 70 passengers, although IndiGo configures its planes in a high-density 78-seat layout. The aircraft is primarily deployed on short regional routes, with a range of about 1,370km.

"IndiGo has utilised the ATRs on all sorts of routes, from monopoly under regional connectivity scheme UDAN to some intra-metro high frequency ones in South India," said Ameya Joshi, aviation analyst and founder of the blog Network Thoughts. "The airline has also experimented with routes, some working well and some not continuing," he said.

The turboprop fleet enabled IndiGo to expand its network to smaller destinations such as Kolhapur, Kishanganj and Kadapa, which are not feasible for the airline's Airbus fleet, according to Joshi.

But the also flagged infrastructure limitations at major airports as a major hurdle for ATR operations.

"One of the biggest challenges has been getting slots at Delhi or Mumbai for the ATR," he said. "The development of secondary airports — like Navi Mumbai and Jewar — could ease this constraint and support rapid network expansion. How much does the government incentivise going forward also needs to be seen."

Since 2023, IndiGo has placed several aircraft orders. Last Sunday, it announced an order for 30 additional Airbus A320neo Widebody planes, adding to its April 2024 order for 30 A320s, bringing its total widebody order to 60 aircraft. Deliveries will begin in 2027 and continue into the

next decade. These widebody planes, which have larger fuel tanks than narrow-body A320s, are key to IndiGo's long-haul expansion, targeting routes like India-US, India-Europe, and India-Australia to compete with Air India and Gulf carriers.

The recent widebody orders followed IndiGo's record-breaking June 2023 order for 50 Airbus A320neo family aircraft to boost its narrow-body fleet for domestic and short-haul

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent widebody orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED)

Corporate Identification Number: L74140MPT984PLC002592
Registered Office: 232 Park 5, The Zodiac Mall, Bichol, Marolund, Indore (MP), 452001
Contact Details: 7383380911 | Email-ID: info@indraindustries.in | Website: www.indraindustries.in

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE ISSUE

RIGHTS ISSUE OF UP TO 4,85,78,025 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) (EQUITY SHARES) EACH AT A PRICE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) PER EQUITY SHARE (EIGHTY SHARES) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹ 48,57,80,250 (RUPEES FORTY EIGHT CRORE FIFTY SEVEN LAKHS EIGHTY THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED) (COMPANY OR ISSUER) AT THE RATE OF 15 (FIFTEEN) EQUITY SHARES FOR EVERY 2 (TWO) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, THURSDAY MAY 09, 2025 (ISSUE), THE ISSUE PRICE IS 1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE BEGINNING PAGE 130 OF THIS LETTER OF OFFER.'

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") - ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MAY 9, 2025

This notice should be read in conjunction with the LDF filed by the Company with the Stock Exchange and the ADFP and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please read the following:

This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday 23rd May 2025 and was scheduled to close on Wednesday, Friday 06th June 2025, has now been extended to Monday, 09th June 2025, by the Rights Issue Committee in meeting held on June 06 2025 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Monday, 09, June, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, 09, June, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE

ISSUE OPENING DATE	ISSUE CLOSING DATE
FRIDAY 23RD MAY 2025	MONDAY 09TH MAY 2025

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

**Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms or on before the Issue Closing Date.

#Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renunciatee (on or prior to the Issue Closing Date).

This addendum shall be available on the respective websites of the Company at info@indraindustries.in the Registrar to the Issue at www.purshare.com and the Stock Exchanges at www.bseindia.com.

Accordingly, there is no change in the LDF and ADFP dated May 09, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing Date. Please note the Issue Closing Date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date.

INVESTORS MAY CHANGE THE LETTER OF OFFER, ABBREVED LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.

All capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For Bluegod Entertainment Limited
(Formerly Known As Indra Industries Limited)
Sd/-
Nilnashok Kumar Khanna
Managing Director

Date: May 09, 2025
Place: Indore

Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
CIN: 694008

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the BSE Limited. The Draft Letter of Offer is available on the website of Stock Exchanges where the Equity Shares are listed, i.e. BSE at www.bseindia.com, Our Company at info@indraindustries.in and the Registrar to the Issue at www.purshare.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Draft Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 31 of the Draft Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

LLOYDS ENTERPRISES LIMITED
Registered Address: A-2, 2nd Floor, Madhu Estate,
Parvathy Bahadur Marg, Lower Park, Mumbai - 400013
Tel: 022-6911 9111 Email: lloydenterprises@lloyds.in www.lloydenterprises.in
(CIN) L27100MH1988PLC041252

NOTICE FOR POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION
MEMBERS ARE HEREBY INFORMED THAT:

In compliance with Section 108 and 110 of Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Act" including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, read with other relevant circulars, including General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, issued by the Securities and Exchange Board of India (the "SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretarial Standards on General Circular No. 08/2024 issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification(s), amendment(s), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), Lloyds Enterprises Limited (the "Company") has completed dispatch of Postal Ballot Notice along with explanatory statement on Friday, 06th June, 2025 through electronic mode only to those Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited or with their Depository/Depository Participants on Friday, 30th May, 2025 ("Cut-off Date"). The requirement of sending physical copy of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form has been dispensed with vide relevant MCA circulars.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mitesh Shah, Partner of Mitesh Shah & Co., Practising Company Secretary (FCS No. 10070 and CP No. 12891), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and Postal Ballot.

In this regard, the Members are hereby informed that:

- The Business relating to approval of:

Sl. No.	Type of Resolution	Description of Resolution
1.	Special Resolution	Approval for Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
2.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Subsidiary Companies in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
3.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Associate Company, in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
4.	Special Resolution	Approval for the provision of loan by the Company for the purchase of its own shares by the trust / trustees for the benefit of employees under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
5.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Engineering Works Limited (formerly known as Lloyds Steel Industries Limited).
6.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals and Energy Limited.
7.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Realty Developers Limited.
8.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Indrajit Properties Private Limited.
9.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Infrastructure & Construction Limited.
10.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals & Minerals Trading LLP.

- The e-voting period commences from Saturday, 07th June, 2025 (09:00 AM (IST)).
- The e-voting period ends on Sunday, 08th June, 2025 (05:00 PM (IST)) when remote e-voting will be blocked and voting shall not be allowed beyond the said time.
- Only those Members, whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date, i.e., Friday, 30th May, 2025 are entitled to cast their votes on the Resolutions. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.
- Members who have not received Postal Ballot Notice may write to investor@lloydenterprises.in and obtain the same.
- For any query or grievance connected with the voting by electronic means, members may address to Mr. Rakesh Dahiya, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 29 Floor, Marathon Floor, Malabar Hill Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Park (E), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk@cDSL.com or call on 022-23058424/43. Members may also write to the Company at the Email ID: investor@lloydenterprises.in.
- The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.lloydenterprises.in and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of CDSL at www.evotingindia.com.
- Result of Postal Ballot shall be declared within two working days from the conclusion of the Postal Ballot and shall be displayed on the Company's website at www.lloydenterprises.in and Central Depository Services (India) Limited www.evotingindia.com after communication to Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The Scrutinizer's decision on validity of the Postal Ballot shall be final.

For Lloyds Enterprises Limited
Sd/-
Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
CIN: 694008

Place: Mumbai
Date: 06th June, 2025

ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED
Regd. Office: 18th floor, A Wing, Marathon Futurax,
N.M. Joshi Marg, Lower Park, Mumbai 400 013
Tel: 91 22 7106 1234 Fax: 91 22 2300 2107
CIN: L92132MH1982PLC028767
Website: www.zee.com

NOTICE OF THE POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ("Act") (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations), the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, other Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars") and other applicable laws, each as amended, seeking approval of the Members of Zee Entertainment Enterprises Limited (the "Company"), on the Resolutions set forth in the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025.

Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025 along with explanatory statement through electronic mode on June 6, 2025 to those Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners and whose e-mail IDs are registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants ("DPs") as on the cut-off date i.e. Friday, May 30, 2025. Accordingly, a physical copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

The Members, whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, May 30, 2025, being the cut-off date, are entitled to vote on the Resolutions set forth in Postal Ballot Notice through remote e-voting only. The voting rights of Members shall be in proportion to their shareholdings in the equity share capital of the Company as on the said cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Company has obtained the services of National Securities Depository Limited ("NSDL"), for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure to remote e-voting is given in the Postal Ballot Notice. The remote e-voting period will commence Monday, June 9, 2025, at 9:00 a.m. (IST) and conclude on Tuesday, June 8, 2025, at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting will be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on resolutions is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The resolutions passed by the Members through the Postal Ballot (through remote e-voting) shall be deemed to have been passed as it has been passed at a General Meeting of the Members. The resolutions, if approved by the requisite majority of Members by means of Postal Ballot, shall be deemed to have been passed on the last date of remote e-voting, i.e. on July 8, 2025. Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by sending a mail along with the relevant documents to the Company's RTA, MIFUG Intime India Private Limited (earlier known as Link Intime India Private Limited, Unit: Zee Entertainment Enterprises Limited, C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West-400083 or the scanned copies of the documents may alternatively be mailed to RTA at mt.helpdesk@nse.com or to the Company at share@zee.com. Members holding shares in demat form who have not updated their email addresses with the depository/ depository participant are requested to approach the concerned depository participant to update their email addresses.

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website i.e. www.zee.com and also on the website of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evotingindia.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Vinita Nair, (Membership No. F10559, COP No. 11902) Joint Managing Partner, M/s. Vinod Kohari & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of the e-voting by Postal Ballot will be announced on or before Wednesday, July 9, 2025. The result declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website i.e. www.zee.com and on the website of NSDL www.evotingindia.com. The Company shall simultaneously intimate to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed.

In case of any query on remote e-voting, Members may refer to FAQs and/or e-voting user manual available on website of NSDL at www.evotingindia.com or call on toll free no. 022-4986 7000.

By Order of the Board
For Zee Entertainment Enterprises Limited
Sd/-
Ashish Agarwal
Company Secretary
Date: June 3, 2025
Membership No. FCS 6669

Over 7% flights cancelled for 3 mths at Delhi airport

DIAL CEO cites runway upgrade as reason for cancellations

DEEPAK PATEL
New Delhi, 6 June

About 7.5 per cent daily flights to and from the Delhi airport will be cancelled between June 15 and September 15 as one of its four runways undergoes an upgrade, Delhi International Airport Limited (DIAL) Chief Executive Officer (CEO) Videsh Kumar Jaipuria said on Friday.

GMR Group-led DIAL operates the Delhi airport, which is the largest in the country.

"The Delhi airport handles 1,450 aircraft movements per day. Of these, 114 daily movements will be cancelled during the runway upgrade," Jaipuria said at a press conference.

"The number of cancellations will be in the range of 7-7.5 per cent, compared to the usual 3-4 per cent on a normal day. However, this time we have coordinated with airlines in advance and rescheduled flights accordingly, which will help reduce any cascading impact," he said.

Referring to a similar upgrade effort earlier this year, he added, "Last time, the lack of proper rescheduling led to cascading disruptions when wind patterns changed. This time, the impact on passengers will be much lower. Since they've been informed in advance, they will have enough time to rebook or make alternative arrangements," he added.

The upgrade of runway 10/28 will include installing an instrument landing system (ILS) and make it compliant with CAT III-B operations. CAT III-B is a precision landing system that allows aircraft to land in very low visibility conditions, such as dense fog.

It was originally scheduled for April-May. However, unexpected changes in wind patterns during that time severely affected flight operations, causing delays.

As a result, the Ministry of Civil Aviation — on April 21 — directed DIAL to postpone the upgrade and resume oper-



The airport will see flight cancellations between June 15 and September 15.

ations on the runway. The runway was made operational again on May 6, and the upgrade was deferred to June 15-September 15.

"The revised timeline was agreed upon by all airlines," Jaipuria said. Following this, airlines collaborated with DIAL to rework slot allocations and align with the revised arrival capacity.

"The objective was to ensure optimum use of available runway capacity while maintaining on-time performance," he added.

"During the fog season, the arrival capacity of all runways comes down due to safety concerns, as arriving aircraft have to be spaced out," Jaipuria said. "In case of westerly winds, arrivals drop from 42 per hour to 30 during CAT III-B operations. But with easterly winds, arrivals fall sharply from 42 per hour to just 15. Once the upgrade is complete, this number will go up to 30 even with easterly winds, significantly improving efficiency," he added.

"Every hour of fog disruption takes three hours for us to return to normal operations. This becomes much worse with easterly winds, where every hour of disruption takes six hours to recover. This impacts not just Delhi airport but also nearby ones."

Therefore, we decided to upgrade runway 10/28 and make it ready to handle CAT III-B flight operations," he said. Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Akasa to launch over 100 weekly flights from Navi Mumbai airport

Akasa Air will start more than 100 weekly domestic flights from the upcoming Navi Mumbai International Airport (NMAIA), expanding to more than 300 domestic and over 50 international weekly departures in the winter schedule, it said on Friday.

Akasa joins IndiGo in confirming its early commitment to NMAIA. "No airline in India will have a larger percentage of its fleet and operations based out of NMAIA than Akasa Air," said Vinay Dube, founder and chief executive officer (CEO) of Akasa Air.

AAHL CEO Arun Bansal welcomed Akasa as an inaugural partner, stressing the airline's rapid growth and forward-looking approach.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Therefore, we decided to upgrade runway 10/28 and make it ready to handle CAT III-B flight operations," he said. Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

'By 2030, 80% of our new onboardings will be EVs'

Logistics startup Porter is aiming to bring in more driver partners and customers into its fold. In a video interaction with Uditsha Srivastava, cofounder and executive vice-chairman, Praveen Goel, talks about the recent fundraising, how the amount is being used, the company's expansion plans and partnership with ONDC, among others. Edited excerpts:

Let us know about the company's recent fundraising and how is the amount being used?

■ It's been a fairly large fundraise, a mix of both primary and secondary capital. With this amount, we want to go deeper and launch more categories. Over the years, we realised that there's still 20 per cent of customers that we are not able to service.

■ Delhi is the biggest city, because of different requirements. So, the intent is to solve that. E-loader is one segment that we want to launch across India. The other big objective is to go wider and replicate the same business model into multiple cities in India.

■ Also, launch in more international geographies where this model makes sense.

What are the top cities for operations for Porter?

Which vehicle categories are the high-frequency ones?

■ Delhi is the biggest city, given its size and scale. After Delhi, there are Mumbai and Bengaluru. Chennai, Hyderabad, and Ahmedabad follow. We probably have around 10 vehicle categories and they're fairly distributed. We have four high-frequency categories, including two-wheelers, three-wheelers, and entry-level four-wheelers. They represent 80 per cent of our revenues. The other six categories comprise nearly 20 per cent of the revenues.

What are the targets for the years to come?

■ In the next five years, we will move from 2 million to 10 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver



IN THE NEXT FIVE YEARS, WE WILL MOVE FROM 2 MILLION SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES WHO COME TO THE PLATFORM EVERY MONTH TO SERVICING MORE THAN 10 MILLION CUSTOMERS

partners, and that number will exceed 1.2 million. We are present in close to 22 cities in India and this number will be around 50 cities.

■ There is also a massive sustainability goal. (EVs).

What percentage of vehicles is currently electric?

■ Metro, Tier-1 cities typically do slightly better compared to Tier-II markets. In Delhi, 70 per cent of three-wheelers are EVs. At an overall level, this number might be around 30-40 per cent. In cargo vehicles, India still doesn't have EVs for all payload capacities.

What's the company's revenue breakdown?

■ Around 85 per cent of our revenue comes from micro, small, and medium enter-

prises (MSMEs), which are local retail stores, small manufacturers, furniture shops, paints and chemicals shops, among others. Then, more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

FROM PAGE 1

Experts flag infra limitations at major airports as hurdle for ATR operations

The Indian carrier, which currently operates a fleet of about 46 ATR 72-600s, had earlier placed an order for 50 such aircraft in 2017 as part of a strategy to expand its regional footprint under the government's UDAN

scheme to improve air connectivity to underserved towns. Four aircraft since have been sold or leased to other.

Deliveries under that contract were completed by early 2025.

The ATR 72-600 is a twin-engine turboprop aircraft typically seating around 70 passengers, although IndiGo configures its planes in a high-density 78-seat layout. The aircraft is primarily deployed on short regional routes, with a range of about 1,370km.

"IndiGo has utilised the ATRs on all sorts of routes, from monopoly under regional connectivity scheme UDAN to some intra-metro high frequency ones in South India," said Ameya Joshi, aviation analyst and founder of the blog Network Thoughts. "The airline has also experimented with routes, some working well and some not continuing," he said.

The turboprop fleet enabled IndiGo to expand its network to smaller destinations such as Kolhapur, Kishanganj and Kadapa, which are not feasible for the airline's Airbus fleet, according to Joshi.

But the also flagged infrastructure limitations at major airports as a major hurdle for ATR operations. "One of the biggest challenges has been getting slots at Delhi or Mumbai for the ATR," he said. "The development of secondary airports — like Navi Mumbai and Jewar — could ease this constraint and support rapid network expansion. How much does the government incentivise going forward also needs to be seen."

Since 2023, IndiGo has placed several aircraft orders. Last Sunday, it announced an order for 30 additional Airbus A320neo Widebody planes, adding to its April 2024 order for 30 A320s, bringing its total widebody order to 60 aircraft. Deliveries will begin in 2027 and continue into the

next decade. These widebody planes, which have larger fuel tanks than narrow-body A320s, are key to IndiGo's long-haul expansion, targeting routes like India-US, India-Europe, and India-Australia to compete with Air India and Gulf carriers.

The recent widebody orders followed IndiGo's record-breaking June 2023 order for 50 Airbus A320neo family aircraft to boost its narrow-body fleet for domestic and short-haul

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 430 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 430 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

LLOYDS ENTERPRISES LIMITED

Registered Address: A-2, 2nd Floor, Madhu Estate, Parkside, Barakhamba Road, Lower Park, Mumbai - 400013
Tel: 022-69119111 Email: lloydsevents@lloyds.in www.lloydsevents.in
(CIN) L27100MH1988PLC041252

NOTICE FOR POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

MEMBERS ARE HEREBY INFORMED THAT:

In compliance with Section 108 and 110 of Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Act" including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, read with other relevant circulars, including General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (the "SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), Lloyds Enterprises Limited (the "Company") has completed dispatch of Postal Ballot Notice along with explanatory statement on Friday, 06th June, 2025 through electronic mode only to those Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited or with their Depository/Depository Participants on Friday, 30th May, 2025 ("Cut-off Date"). The requirement of sending physical copy of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form has been dispensed with vide relevant MCA circulars.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mitesh Shah, Partner of Mitesh Shah & Co., Practising Company Secretary (FCS No. 10070 and CP No. 12891), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting by Postal Ballot.

In this regard, the Members are hereby informed that:

- The Business relating to approval of:

Sl. No.	Type of Resolution	Description of Resolution
1.	Special Resolution	Approval for Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
2.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Subsidiary Companies in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
3.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Associate Company, in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
4.	Special Resolution	Approval for the provision of loan by the Company for the purchase of its own shares by the trust / trustees for the benefit of employees under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
5.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Engineering Works Limited (formerly known as Lloyds Metals and Energy Limited).
6.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals and Energy Limited.
7.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Realty Developers Limited.
8.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Indrajit Properties Private Limited.
9.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Infrastructure & Construction Limited.
10.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals & Minerals Trading LLP.

b. The e-voting period commences from Saturday, 07th June, 2025 (09:00 AM (IST)).

c. The e-voting period ends on Sunday, 09th June, 2025 (05:00 PM (IST)). When remote e-voting will be blocked and voting shall not be allowed beyond the said time.

d. Only those Members, whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date i.e., Friday, 30th May, 2025 are entitled to cast their votes on the Resolutions. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.

e. Members who have not received Postal Ballot Notice may write to investor@lloydsevents.in and obtain the same.

f. For any query or grievance connected with the voting by electronic means, members may address to Mr. Rakesh Dahiya, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 29 Floor, Marathon Floor, Market III Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Park, Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk@cDSL.in or call on 022-23058424/43. Members may also write to the Company at the Email ID: investor@lloydsevents.in

Members who have not registered their e-mail address with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company/Depository Participant, are required to register by completing the process for registration of e-mail address as under:

■ Members holding shares in physical form can get their E-mail Id registered by contacting their respective Depository Participant.

■ Members holding shares in demat form can get their E-mail Id registered by contacting our Registrar and Share Transfer Agent "Bigshare Services Private Limited" or their Email ID investor@lloydsevents.in along with relevant documents to our Registrar and Share Transfer Agent Office No. 30th Floor, Market III Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Park, Mumbai - 400013. Members may also write to the Company at the Email ID: investor@lloydsevents.in

■ The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.lloydsevents.in and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of CDSL at www.evotingindia.com

Result of Postal Ballot shall be declared within two working days from the conclusion of the Postal Ballot and shall be displayed on the Company's website at www.lloydsevents.in and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The Scrutinizer's decision on validity of the Postal Ballot shall be final.

For Lloyds Enterprises Limited
Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 06th June, 2025

BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED)
Corporate Identification Number: L74140MP1984PLC002592
Registered Office: 232 Park-S, The Zodiac Mall, Bicholi, Madhya Pradesh, India (MPL) - 452001
Contact Details: 7383330911 | Email-ID: info@indraindustries.in | Website: www.indraindustries.in
Contact Person: Ms. Sweety Purohit, Company Secretary & Compliance Officer.

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE ISSUE
RIGHTS ISSUE OF UP TO 4,85,78,025 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) (EQUITY SHARES) EACH AT A PRICE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) PER EQUITY SHARE (EIGHTY SHARES) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹ 48,57,80,250/- (RUPEES FORTY EIGHT CRORE FIFTY SEVEN LAKHS EIGHTY THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED) (COMPANY OR ISSUER) AT THE RATIO OF 15 (FIFTEEN) EQUITY SHARES FOR EVERY 2 (TWO) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, THURSDAY MAY 09, 2025 (ISSUE). THE ISSUE PRICE IS 1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE BEGINNING PAGE 130 OF THIS LETTER OF OFFER.'

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") - ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MAY 9, 2025
This notice should be read in conjunction with the LDF filed by the Company with the Stock Exchange and the ADFP and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please read the following:

This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday 23rd May 2025 and was scheduled to close on Wednesday, Friday 06th June 2025, has now been extended to Monday, 09th June, 2025, by the Rights Issue Committee in meeting held on June 06, 2025 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Monday, 09th June, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, 09th June, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE

ISSUE OPENING DATE	ISSUE CLOSING DATE
FRIDAY 23RD MAY 2025	MONDAY 09TH JUNE 2025

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).
**Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms or on before the Issue Closing Date.
#Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee (on or prior to the Issue Closing Date).
This addendum shall be available on the respective websites of the Company at www.indraindustries.in in the Registrar to the Issue at www.purushare.com and the Stock Exchanges at www.bseindia.com.

Accordingly, there is no change in the LDF and ADFP dated May 09, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing Date. Please note the Issue Closing Date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of Issue Closing Date.

INVESTORS MAY CHANGE THE LETTER OF OFFER, ABROGATED LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.
All capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For Bluegod Entertainment Limited
(Formerly Known As Indra Industries Limited)
Sd/-
Nilnashok Kumar Khanna
Managing Director
Date: May 09, 2025
Place: Indore

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the BSE Limited. The Draft Letter of Offer is available on the website of Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com, our Company at www.indraindustries.in and the Registrar to the Issue at www.purushare.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Draft Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 31 of the Draft Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: 18th floor, A Wing, Marathon Futurex, N.M Joshi Marg, Lower Park, Mumbai 400 013
Tel: 91 22 7106 1234 Fax: 91 22 2001 2107
CIN: L92132MH1982PLC028767
Website: www.zee.com

NOTICE OF THE POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ("Act") (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Rules), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations), the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, other Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars") and other applicable laws, each as amended, seeking approval of the Members of Zee Entertainment Enterprises Limited (the "Company"), on the Resolutions set forth in the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025.

Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025 along with explanatory statement through electronic mode on June 6, 2025 to those Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners and whose e-mail IDs are registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants ("DPs") as on the cut-off date i.e. Friday, May 30, 2025. Accordingly, a physical copy of the Postal Ballot Notice with the Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

The Members, whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, May 30, 2025, being the cut-off date, are entitled to vote on the Resolutions set forth in Postal Ballot Notice through remote e-voting only. The voting rights of Members shall be in proportion to their shareholdings in the equity share capital of the Company as on the said cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Company has obtained the services of National Securities Depository Limited ("NSDL"), for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure to remote e-voting by NSDL is available on the website of NSDL. The remote e-voting period will commence Monday, June 9, 2025, at 9:00 a.m. (IST) and conclude on Tuesday, June 8, 2025, at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting will be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on resolutions is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The resolutions passed by the Members through the Postal Ballot (through remote e-voting) shall be deemed to have been passed as it has been passed at a General Meeting of the Members. The resolutions, if approved by the requisite majority of Members by means of Postal Ballot, shall be deemed to have been passed on the last date of remote e-voting, i.e. on July 8, 2025.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by sending a mail along with the relevant documents to the Company's RTA, MUGS Intime India Private Limited (earlier known as Link Intime India Private Limited, Unit: Zee Entertainment Enterprises Limited, C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West-400083 or the scanned copies of the documents may alternatively be mailed to RTA at mt.helpdesk@in.mps.mugl.com or to the Company at share@zee.com. Members holding shares in demat form who have not updated their email addresses with the depository/ depository participant are requested to approach the concerned depository participant to update their email addresses.

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website i.e. www.zee.com and also on the website of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evotingindia.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Vinita Nair, (Membership No. F10559, COP No.11902) Joint Managing Partner, M/s. Vinod Kohari & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of the e-voting by Postal Ballot will be announced on or before Wednesday, June 9, 2025. The result declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website i.e. www.zee.com and on the website of NSDL www.evotingindia.com. The Company shall simultaneously intimate to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed.

Over 7% flights cancelled for 3 mths at Delhi airport

DIAL CEO cites runway upgrade as reason for cancellations

DEEPAK PATEL
New Delhi, 6 June

About 7.5 per cent daily flights to and from the Delhi airport will be cancelled between June 15 and September 15 as one of its four runways undergoes an upgrade, Delhi International Airport Limited (DIAL) Chief Executive Officer (CEO) Videsh Kumar Jaipuria said on Friday.

GMR Group-led DIAL operates the Delhi airport, which is the largest in the country.

"The Delhi airport handles 1,450 aircraft movements per day. Of these, 114 daily movements will be cancelled during the runway upgrade," Jaipuria said at a press conference.

"The number of cancellations will be in the range of 7-7.5 per cent, compared to the usual 3-4 per cent on a normal day. However, this time we have coordinated with airlines in advance and rescheduled flights accordingly, which will help reduce any cascading impact," he said.

Referring to a similar upgrade effort earlier this year, he added, "Last time, the lack of proper rescheduling led to cascading disruptions when wind patterns changed. This time, the impact on passengers will be much lower. Since they've been informed in advance, they will have enough time to rebook or make alternative arrangements."

The upgrade of runway 10/28 will include installing an instrument landing system (ILS) and make it compliant with CAT III-B operations. CAT III-B is a precision landing system that allows aircraft to land in very low visibility conditions, such as dense fog.

It was originally scheduled for April-May. However, unexpected changes in wind patterns during that time severely affected flight operations, causing delays.

As a result, the Ministry of Civil Aviation — on April 21 — directed DIAL to postpone the upgrade and resume oper-



The airport will see flight cancellations between June 15 and September 15.

ations on the runway. The runway was made operational again on May 6, and the upgrade was deferred to June 15-September 15.

"The revised timeline was agreed upon by all airlines," Jaipuria said. Following this, airlines collaborated with DIAL to rework slot allocations and align with the revised arrival capacity.

"The objective was to ensure optimum use of available runway capacity while maintaining on-time performance," he added.

"During the fog season, the arrival capacity of all runways comes down due to safety concerns, as arriving aircraft have to be spaced out," Jaipuria said. "In case of westerly winds, arrivals drop from 42 per hour to 30 during CAT III-B operations. But with easterly winds, arrivals fall sharply from 42 per hour to just 15. Once the upgrade is complete, this number will go up to 30 even with easterly winds, significantly improving efficiency," he added.

"Every hour of fog disruption takes three hours for us to return to normal operations. This becomes much worse with easterly winds, where every hour of disruption takes six hours to recover. This impacts not just Delhi airport but also nearby ones."

Therefore, we decided to upgrade runway 10/28 and make it ready to handle CAT III-B flight operations," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Akasa to launch over 100 weekly flights from Navi Mumbai airport

Akasa Air will start more than 100 weekly domestic flights from the upcoming Navi Mumbai International Airport (NMAIA), expanding to more than 300 domestic and over 50 international weekly departures in the winter schedule, it said on Friday.

Akasa joins IndiGo in confirming its early commitment to NMAIA.

"No airline in India will have a larger percentage of its fleet and operations based out of NMAIA than Akasa Air," said Vinay Dube, founder and chief executive officer (CEO) of Akasa Air.

AALH CEO Arun Bansal welcomed Akasa as an inaugural partner, stressing the airline's rapid growth and forward-looking approach.

DEEPAK PATEL

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

three hours for us to return to normal operations. This becomes much worse with easterly winds, where every hour of disruption takes six hours to recover. This impacts not just Delhi airport but also nearby ones."

Therefore, we decided to upgrade runway 10/28 and make it ready to handle CAT III-B flight operations," he said. Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

'By 2030, 80% of our new onboardings will be EVs'

Logistics startup Porter is aiming to bring in more driver partners and customers into its fold. In a video interaction with Uditsha Srivastava, cofounder and executive vice-chairman, Praveen Goel, talks about the recent fundraising, how the amount is being used, the company's expansion plans and partnership with ONDC, among others. Edited excerpts:

Let us know about the company's recent fundraising and how is the amount being used?

■ It's been a fairly large fundraise, a mix of both primary and secondary capital. With this amount, we want to go deeper and launch more categories. Over the years, we realised that there's still 20 per cent of customers that we are not able to service.

■ Delhi is the biggest city, because of different requirements. So, the intent is to solve that. E-loader is one segment that we want to launch across India. The other big objective is to go wider and replicate the same business model into multiple cities in India. Also, launch in more international geographies where this model makes sense.

What are the targets for the years to come?

■ In the next five years, we will move from 2 million to 10 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver

partners, and that number will exceed 1.2 million. We are present in close to 22 cities in India and this number will be around 50 cities.

■ There is also a massive sustainability goal. (EVs).

What are the top cities of operations for Porter?

■ Which vehicle categories are the high-frequency ones?

■ Delhi is the biggest city, given its size and scale. After Delhi, there are Mumbai and Bengaluru. Chennai, Hyderabad, and Ahmedabad follow. We probably have around 10 vehicle categories and they're fairly distributed. We have four high-frequency categories, including two-wheelers, three-wheelers, and entry-level four-wheelers. They represent 80 per cent of our revenues. The other six categories comprise nearly 20 per cent of the revenues.

Do you also have fleet partners or is it a driver-owner model completely?

■ We are a completely asset-light model where the driver-partner has his vehicle. In



IN THE NEXT FIVE YEARS, WE WILL MOVE FROM 2 MILLION SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES WHO COME TO THE PLATFORM EVERY MONTH TO SERVICING MORE THAN 10 MILLION CUSTOMERS

more than 90 per cent of the cases, the owner and the driver are one person. We also have fleet operators, but they comprise less than 10 per cent of our volumes. There are more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

What's the company's revenue breakdown?

■ Around 85 per cent of our revenue comes from micro, small, and medium enter-

prises (MSMEs), which are local retail stores, small manufacturers, furniture shops, paints and chemicals shops, among others. Then, more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

FROM PAGE 1

Experts flag infra limitations at major airports as hurdle for ATR operations

The Indian carrier, which currently operates a fleet of about 46 ATR 72-600s, had earlier placed an order for 50 such aircraft in 2017 as part of a strategy to expand its regional footprint under the government's UDAN scheme to improve air connectivity to underserved towns. Four aircraft since have been sold or leased to other.

Deliveries under that contract were completed by early 2025.

The ATR 72-600 is a twin-engine turboprop aircraft typically seating around 70 passengers, although IndiGo configures its planes in a high-density 78-seat layout. The aircraft is primarily deployed on short regional routes, with a range of about 1,370km.

"IndiGo has utilised the ATRs on all sorts of routes, from monopoly under regional connectivity scheme UDAN to some intra-metro high frequency ones in South India," said Armeja Joshi, aviation analyst and founder of the blog Network Thoughts. "The airline has also experimented with routes, some working well and some not continuing," he said.

The turboprop fleet enabled IndiGo to expand its network to smaller destinations such as Kolhapur, Kishanganj and Kadapa, which are not feasible for the airline's Airbus fleet, according to Joshi.

But the also flagged infrastructure limitations at major airports as a major hurdle for ATR operations. "One of the biggest challenges has been getting slots at Delhi or Mumbai for the ATR," he said. "The development of secondary airports — like Navi Mumbai and Jewar — could ease this constraint and support rapid network expansion. How much does the government incentivise going forward also needs to be seen."

Since 2023, IndiGo has placed several aircraft orders. Last Sunday, it announced an order for 30 additional Airbus A320XLR narrowbody planes, adding to its April 2024 order for 30 A320s, bringing its total widebody order to 60 aircraft. Deliveries will begin in 2027 and continue into the

next decade. These widebody planes, which have larger fuel tanks than narrow-body A320s, are key to IndiGo's long-haul expansion, targeting routes like India-US, India-Europe, and India-Australia to compete with Air India and Gulf carriers.

The recent widebody orders followed IndiGo's record-breaking June 2023 order for 50 Airbus A320neo family aircraft to boost its narrow-body fleet for domestic and short-haul

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent widebody orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalised terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated May 09, 2025 the "Letter of Offer" or "LOF" filed with BSE Limited ("BSE").

BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED)

Corporate Identification Number: L74140MPT1984PLC002592
Registered Office: 232 Park Street, The Zodiac Mall, Bichol, Madras, Andhra Pradesh (AP), 520001
Contact Details: 7383330911 | Email-ID: info@indraindustries.in | Website: www.indraindustries.in

Contact Person: Ms. Sweety Purohit, Company Secretary & Compliance Officer.

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE ISSUE

RIGHTS ISSUE OF UP TO 4,85,78,025 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) (EQUITY SHARES) EACH AT A PRICE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) PER EQUITY SHARE (EIGHTY SHARES) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹ 48,57,80,250 (RUPEES FORTY EIGHT CRORE FIFTY SEVEN LAKHS EIGHTY THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED) (COMPANY OR ISSUER) AT THE RATIO OF 15 (FIFTEEN) EQUITY SHARES FOR EVERY 2 (TWO) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, THURSDAY MAY 09, 2025 (ISSUE). THE ISSUE PRICE IS 1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE BEGINNING PAGE 130 OF THIS LETTER OF OFFER.'

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") - ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MAY 9, 2025

This notice should be read in conjunction with the LOF filed by the Company with the Stock Exchange and the ADFP and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please read the following:

This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday 23rd May 2025 and was scheduled to close on Wednesday, Friday 06th June 2025, has now been extended to Monday, June 09, 2025, by the Rights Issue Committee in meeting held on June 06, 2025 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Monday, 09, June, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, 09, June, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE

ISSUE OPENING DATE: FRIDAY 23RD MAY 2025 MONDAY 09TH MAY 2025

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

**Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms or on before the Issue Closing Date. #Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renunciatee (on or prior to the Issue Closing Date).

This addendum shall be available on the respective websites of the Company at info@indraindustries.in the Registrar to the Issue at www.purushare.com and the Stock Exchanges at www.bseindia.com.

Accordingly, there is no change in the LOF and ADFP dated May 09, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing Date. Please Note the Issue Closing Date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of Issue Closing Date.

INVESTORS MAY CHANGE THE LETTER OF OFFER, ABROGATED LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.

All capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For Bluegod Entertainment Limited (Formerly Known As Indra Industries Limited) Sd/- Nilnashok Kumar Khanna Managing Director

Date: May 09, 2025 Place: Indore

LLOYDS ENTERPRISES LIMITED

Registered Address: A-2, 2nd Floor, Madhu Estate, Parsipalya Bahadur Math, Lower Park, Mumbai - 400013
Tel: 022-69119111 Email: lloydseventures@lloyds.in www.lloydseventures.in (CIN) L27100MH1988PLC041252

NOTICE FOR POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION MEMBERS ARE HEREBY INFORMED THAT:

In compliance with Section 108 and 110 of Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Act" including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, read with other relevant circulars, including General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (the "SEBI Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretarial Standards on General Circular No. 09/2023 and the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Rules), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations), the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, other Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars") and other applicable laws, each as amended, seeking approval of the Members of Zee Entertainment Enterprises Limited (the "Company"), on the Resolutions set forth in the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025.

Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025 along with explanatory statement through electronic mode on June 6, 2025 to those Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners and whose e-mail IDs are registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants ("DPs") as on the cut-off date i.e. Friday, May 30, 2025. Accordingly, a physical copy of the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

The Members, whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, May 30, 2025, being the cut-off date, are entitled to vote on the Resolutions set forth in Postal Ballot Notice through remote e-voting only. The voting rights of Members shall be in proportion to their shareholdings in the equity share capital of the Company as on the said cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Company has obtained the services of National Securities Depository Limited ("NSDL"), for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure to remote e-voting is given in the Annexure to the Postal Ballot Notice. The remote e-voting period will commence Monday, June 9, 2025, at 9:00 a.m. (IST) and conclude on Tuesday, June 8, 2025, at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting will be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on resolutions is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The resolutions passed by the Members through the Postal Ballot (through remote e-voting) shall be deemed to have been passed as it has been passed at a General Meeting of the Members. The resolutions, if approved by the requisite majority of Members by means of Postal Ballot, shall be deemed to have been passed on the last date of remote e-voting, i.e. on July 8, 2025.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by sending a mail along with the relevant documents to the Company's RTA, MFGS Intime India Private Limited (earlier known as Link Intime India Private Limited, Unit: Zee Entertainment Enterprises Limited, C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West-400083 or the scanned copies of the documents may alternatively be mailed to RTA at mt_helodesk@in.mps.mfg.com or to the Company at shatasrivastava@zee.com. Members holding shares in demat form who have not updated their email addresses with the depository/ depository participant are requested to approach the concerned depository participant to update their email addresses.

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website i.e. www.zee.com and also on the website of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Vinita Nair, (Membership No. F10559, COP No. 11902) Joint Managing Partner, M/s. Vinod Kohari & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of the e-voting by Postal Ballot will be announced on or before Wednesday, June 9, 2025. The result declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website at www.zee.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com. The Company shall simultaneously intimate to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed.

In case of any query on remote e-voting, Members may refer to FAQs and/or e-voting user manual available on website of NSDL at www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 022-4986 7000.

By Order of the Board For Zee Entertainment Enterprises Limited Sd/- Ashish Agarwal Company Secretary

Date: June 3, 2025 Place: Mumbai

Pranjali Mahapatra Company Secretary & Compliance Officer Sd/- A.C. 69/08

Members who have not registered their e-mail address with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company/ Depository Participant, are requested to register by completing the process for registration of email address as under:

Members holding shares in physical form can get their E-mail IDs registered by contacting their respective Depository Participant.

Members holding shares in the demat form can get their E-mail IDs registered by contacting our Registrar and Share Transfer Agent "Bighare Services Private Limited" or their Email ID: bighare@bighare.com along with relevant documents to our Registrar and Share Transfer Agent Office No. 307, 3rd Floor, The Business Park, next to Anura Centre, Malabar Cresent, Andheri (East), Mumbai - 400095.

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.lloydseventures.in and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Result of Postal Ballot shall be declared within two working days from the conclusion of the Postal Ballot and shall be displayed on the Company's website at www.lloydseventures.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The Scrutinizer's decision on validity of the Postal Ballot shall be final.

ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: 18th floor, A Wing, Marathon Futurex, N M Joshi Marg, Lower Park, Mumbai 400 013
Tel: 91 22 7106 1234 Fax: 91 22 2000 2107
CIN: L92132MH1982PLC028767
Website: www.zee.com

NOTICE OF THE POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ("Act") (including any statutory modification or re-enactment thereof) for the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Rules), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations), the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, other Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars") and other applicable laws, each as amended, seeking approval of the Members of Zee Entertainment Enterprises Limited (the "Company"), on the Resolutions set forth in the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025.

Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025 along with explanatory statement through electronic mode on June 6, 2025 to those Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners and whose e-mail IDs are registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants ("DPs") as on the cut-off date i.e. Friday, May 30, 2025. Accordingly, a physical copy of the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

The Members, whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, May 30, 2025, being the cut-off date, are entitled to vote on the Resolutions set forth in Postal Ballot Notice through remote e-voting only. The voting rights of Members shall be in proportion to their shareholdings in the equity share capital of the Company as on the said cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Company has obtained the services of National Securities Depository Limited ("NSDL"), for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure to remote e-voting is given in the Annexure to the Postal Ballot Notice. The remote e-voting period will commence Monday, June 9, 2025, at 9:00 a.m. (IST) and conclude on Tuesday, June 8, 2025, at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting will be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on resolutions is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The resolutions passed by the Members through the Postal Ballot (through remote e-voting) shall be deemed to have been passed as it has been passed at a General Meeting of the Members. The resolutions, if approved by the requisite majority of Members by means of Postal Ballot, shall be deemed to have been passed on the last date of remote e-voting, i.e. on July 8, 2025.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by sending a mail along with the relevant documents to the Company's RTA, MFGS Intime India Private Limited (earlier known as Link Intime India Private Limited, Unit: Zee Entertainment Enterprises Limited, C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West-400083 or the scanned copies of the documents may alternatively be mailed to RTA at mt_helodesk@in.mps.mfg.com or to the Company at shatasrivastava@zee.com. Members holding shares in demat form who have not updated their email addresses with the depository/ depository participant are requested to approach the concerned depository participant to update their email addresses.

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website i.e. www.zee.com and also on the website of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Vinita Nair, (Membership No. F10559, COP No. 11902) Joint Managing Partner, M/s. Vinod Kohari & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of the e-voting by Postal Ballot will be announced on or before Wednesday, June 9, 2025. The result declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website at www.zee.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com. The Company shall simultaneously intimate to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed.

In case of any query on remote e-voting, Members may refer to FAQs and/or e-voting user manual available on website of NSDL at www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 022-4986 7000.

By Order of the Board For Zee Entertainment Enterprises Limited Sd/- Ashish Agarwal Company Secretary

Date: June 3, 2025 Place: Mumbai

Pranjali Mahapatra Company Secretary & Compliance Officer Sd/- A.C. 69/08

Members who have not registered their e-mail address with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company/ Depository Participant, are requested to register by completing the process for registration of email address as under:

Members holding shares in physical form can get their E-mail IDs registered by contacting their respective Depository Participant.

Over 7% flights cancelled for 3 mths at Delhi airport

DIAL CEO cites runway upgrade as reason for cancellations

DEEPAK PATEL
New Delhi, 6 June

About 7.5 per cent daily flights to and from the Delhi airport will be cancelled between June 15 and September 15 as one of its four runways undergoes an upgrade, Delhi International Airport Limited (DIAL) Chief Executive Officer (CEO) Videsh Kumar Jaipuria said on Friday.

GMR Group-led DIAL operates the Delhi airport, which is the largest in the country.

"The Delhi airport handles 1,450 aircraft movements per day. Of these, 114 daily movements will be cancelled during the runway upgrade," Jaipuria said at a press conference.

"The number of cancellations will be in the range of 7-7.5 per cent, compared to the usual 3-4 per cent on a normal day. However, this time we have coordinated with airlines in advance and rescheduled flights accordingly, which will help reduce any cascading impact," he said.

Referring to a similar upgrade effort earlier this year, he added, "Last time, the lack of proper rescheduling led to cascading disruptions when wind patterns changed. This time, the impact on passengers will be much lower. Since they've been informed in advance, they will have enough time to rebook or make alternative arrangements," he added.

The upgrade of runway 10/28 will include installing an instrument landing system (ILS) and make it compliant with CAT III-B operations. CAT III-B is a precision landing system that allows aircraft to land in very low visibility conditions, such as dense fog.

It was originally scheduled for April-May. However, unexpected changes in wind patterns during that time severely affected flight operations, causing delays.

As a result, the Ministry of Civil Aviation — on April 21 — directed DIAL to postpone the upgrade and resume oper-



The airport will see flight cancellations between June 15 and September 15.

ations on the runway. The runway was made operational again on May 6, and the upgrade was deferred to June 15-September 15.

"The revised timeline was agreed upon by all airlines," Jaipuria said.

Following this, airlines collaborated with DIAL to rework slot allocations and align with the revised arrival capacity.

"The objective was to ensure optimum use of available runway capacity while maintaining on-time performance," he added.

"During the fog season, the arrival capacity of all runways comes down due to safety concerns, as arriving aircraft have to be spaced out," Jaipuria said.

"In case of westerly winds, arrivals drop from 42 per hour to 30 during CAT III-B operations. But with easterly winds, arrivals fall sharply from 42 per hour to just 15. Once the upgrade is complete, this number will go up to 30 even with easterly winds, significantly improving efficiency," he added.

"Every hour of fog disruption takes

Akasa to launch over 100 weekly flights from Navi Mumbai airport

Akasa Air will start more than 100 weekly domestic flights from the upcoming Navi Mumbai International Airport (NMAIA), expanding to more than 300 domestic and over 50 international weekly departures in the winter schedule, it said on Friday.

Akasa joins IndiGo in confirming its early commitment to NMAIA.

"No airline in India will have a larger percentage of its fleet and operations based out of NMAIA than Akasa Air," said Vinay Dube, founder and chief executive officer (CEO) of Akasa Air.

AALH CEO Arun Bansal welcomed Akasa as an inaugural partner, stressing the airline's rapid growth and forward-looking approach.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

three hours for us to return to normal operations. This becomes much worse with easterly winds, where every hour of disruption takes six hours to recover. This impacts not just Delhi airport but also nearby ones."

Therefore, we decided to upgrade runway 10/28 and make it ready to handle CAT III-B flight operations," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"Every hour of fog disruption takes

'By 2030, 80% of our new onboardings will be EVs'

Logistics startup Porter is aiming to bring in more driver partners and customers into its fold. In a video interaction with UdiShah Srivastava, cofounder and executive vice-chairman, Praveen Goel, talks about the recent fundraising, how the amount is being used, the company's expansion plans and partnership with ONDC, among others. Edited excerpts:

Let us know about the company's recent fundraising and how is the amount being used?

■ It's been a fairly large fundraise, a mix of both primary and secondary capital. With this amount, we want to go deeper and launch more categories. Over the years, we realised that there's still 20 per cent of customers that we are not able to service.

■ Delhi is the biggest city, because of different requirements. So, the intent is to solve that. E-loader is one segment that we want to launch across India. The other big objective is to go wider and replicate the same business model into multiple cities in India.

■ Also, launch in more international geographies where this model makes sense.

What are the top cities for operations for Porter?

■ Which vehicle categories are the high-frequency ones?

■ Delhi is the biggest city, given its size and scale. After Delhi, there are Mumbai and Bengaluru. Chennai, Hyderabad, and Ahmedabad follow.

■ We probably have around 10 vehicle categories and they're fairly distributed. We have four high-frequency categories, including two-wheelers, three-wheelers, and entry-level four-wheelers. They represent 80 per cent of our revenues. The other six categories comprise nearly 20 per cent of the revenues.

What are the targets for the year 2025?

■ In the next five years, we will move from 2 million to 10 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver

partners, and that number will exceed 1.2 million. We are present in close to 22 cities in India and this number will be around 50 cities.

■ There is also a massive sustainability goal. (EVs).

What's the company's revenue model completely?

■ We are a completely asset-light model where the driver-partner has his vehicle. In



IN THE NEXT FIVE YEARS, WE WILL MOVE FROM 2 MILLION SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES WHO COME TO THE PLATFORM EVERY MONTH TO SERVICING MORE THAN 10 MILLION CUSTOMERS

more than 90 per cent of the cases, the owner and the driver are one person. We also have fleet operators, but they comprise less than 10 per cent of our volumes. There are more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

What's the company's revenue breakdown?

■ Around 85 per cent of our revenue comes from micro, small, and medium enter-

prises (MSMEs), which are local retail stores, small manufacturers, furniture shops, paints and chemicals shops, among others. Then, more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

What's the company's revenue breakdown?

■ Around 85 per cent of our revenue comes from micro, small, and medium enter-

FROM PAGE 1

Experts flag infra limitations at major airports as hurdle for ATR operations

The Indian carrier, which currently operates a fleet of about 46 ATR 72-600s, had earlier placed an order for 50 such aircraft in 2017 as part of a strategy to expand its regional footprint under the government's UDAN scheme to improve air connectivity to underserved towns. Four aircraft since have been sold or leased to other.

Deliveries under that contract were completed by early 2025.

The ATR 72-600 is a twin-engine turboprop aircraft typically seating around 70 passengers, although IndiGo configures its planes in a high-density 78-seat layout. The aircraft is primarily deployed on short regional routes, with a range of about 1,370km.

"IndiGo has utilised the ATRs on all sorts of routes, from monopoly under regional connectivity scheme UDAN to some intra-metro high frequency ones in South India," said Ameya Joshi, aviation analyst and founder of the blog Network Thoughts. "The airline has also experimented with routes, some working well and some not continuing," he said.

The turboprop fleet enabled IndiGo to expand its network to smaller destinations such as Kolhapur, Kishanganj and Kadapa, which are not feasible for the airline's Airbus fleet, according to Joshi.

But the also flagged infrastructure limitations at major airports as a major hurdle for ATR operations. "One of the biggest challenges has been getting slots at Delhi or Mumbai for the ATR," he said. "The development of secondary airports — like Navi Mumbai and Jewar — could ease this constraint and support rapid network expansion. How much does the government incentivise going forward also needs to be seen."

Since 2023, IndiGo has placed several aircraft orders. Last Sunday, it announced an order for 30 additional Airbus A320neo Widebody planes, adding to its April 2024 order for 30 A320s, bringing its total widebody order to 60 aircraft. Deliveries will begin in 2027 and continue into the

next decade. These widebody planes, which have larger fuel tanks than narrow-body A320s, are key to IndiGo's long-haul expansion, targeting routes like India-US, India-Europe, and India-Australia to compete with Air India and Gulf carriers.

The recent widebody orders followed IndiGo's record-breaking June 2023 order for 50 Airbus A320neo family aircraft to boost its narrow-body fleet for domestic and short-haul

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 430 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 430 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 430 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED)

Corporate Identification Number: L74140MPT984PLC002592
Registered Office: 232 Park 5, The Zodiac Mall, Bichol, Madras, Andhra (AP), 452001
Contact Details: 7383380911 | Email-ID: info@indraindustries.in | Website: www.indraindustries.in
Contact Person: Ms. Sweety Purohit, Company Secretary & Compliance Officer.

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE ISSUE

RIGHTS ISSUE OF UP TO 4,85,78,025 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) (EQUITY SHARES) EACH AT A PRICE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) PER EQUITY SHARE (EIGHTY SHARES) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹ 48,57,80,250/- (RUPEES FORTY EIGHT CRORE FIFTY SEVEN LAKHS EIGHTY THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED) (COMPANY OR ISSUER) AT THE RATIO OF 15 (FIFTEEN) EQUITY SHARES FOR EVERY 2 (TWO) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, THURSDAY MAY 09, 2025 (ISSUE). THE ISSUE PRICE IS 1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE BEGINNING PAGE 130 OF THIS LETTER OF OFFER.'

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") - ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MAY 9, 2025

This notice should be read in conjunction with the LDF filed by the Company with the Stock Exchange and the ADFP and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please read the following:

This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday 23rd May 2025 and was scheduled to close on Wednesday, Friday 06th June 2025, has now been extended to Monday, June 09, 2025, by the Ministry of Company Affairs in its letter of offer to the letter of offer to the Eligible Shareholders to exercise their rights in the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Monday, 09, June, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, 09, June, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE

ISSUE OPENING DATE	ISSUE CLOSING DATE
FRIDAY 23RD MAY 2025	MONDAY 09TH MAY 2025

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).
**Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms or on before the Issue Closing Date.
#Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee (on or prior to the Issue Closing Date).
This addendum shall be available on the respective websites of the Company at info@indraindustries.in the Registrar to the Issue at www.purushare.com and the Stock Exchanges at www.bseindia.com.

Accordingly, there is no change in the LDF and ADFP dated May 09, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing Date. Please note the Issue Closing Date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of Issue Closing Date.

INVESTORS MAY CHANGE THE LETTER OF OFFER, ABROGATED LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.
All capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For Bluegod Entertainment Limited
(Formerly Known As Indra Industries Limited) Sd/-
Nitinshank kumar Khanna
Managing Director

Date: May 09, 2025
Place: Indore

For Bluegod Entertainment Limited Sd/-
Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 06th June, 2025

Members who have not registered their e-mail address with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company/Depository Participant, are requested to register by completing the process for registration of e-mail address as under:

- Members holding shares in physical form can get their E-mail Id registered by contacting their respective Depository Participant.
- Members holding shares in demat form can get their E-mail Id registered by contacting our Registrar and Share Transfer Agent 'Bighare Services Private Limited' or their Email Id investor@bighare.com along with relevant documents to our Registrar and Share Transfer Agent Office No. 232 Park 5, First Floor, The Zodiac Mall, Bichol, Madras, Andhra Pradesh, India. Contact: (Andhra) Email: info@bighare.com and info@bighare.com.
- The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.bluegodentertainment.com and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of CDSL at www.evotingindia.com.

Result of Postal Ballot shall be declared within two working days from the conclusion of the Postal Ballot and shall be displayed on the Company's website at www.bluegodentertainment.com and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The Scrutinizer's decision on validity of the Postal Ballot shall be final.

For Lloyds Enterprises Limited Sd/-
Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 06th June, 2025

Members who have not registered their e-mail address with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company/Depository Participant, are requested to register by completing the process for registration of e-mail address as under:

- Members holding shares in physical form can get their E-mail Id registered by contacting their respective Depository Participant.
- Members holding shares in demat form can get their E-mail Id registered by contacting our Registrar and Share Transfer Agent 'Bighare Services Private Limited' or their Email Id investor@bighare.com along with relevant documents to our Registrar and Share Transfer Agent Office No. 232 Park 5, First Floor, The Zodiac Mall, Bichol, Madras, Andhra Pradesh, India. Contact: (Andhra) Email: info@bighare.com and info@bighare.com.
- The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.lloydsenterprises.com and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of CDSL at www.evotingindia.com.

Result of Postal Ballot shall be declared within two working days from the conclusion of the Postal Ballot and shall be displayed on the Company's website at www.lloydsenterprises.com and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The Scrutinizer's decision on validity of the Postal Ballot shall be final.

For Lloyds Enterprises Limited Sd/-
Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 06th June, 2025

Members who have not registered their e-mail address with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company/Depository Participant, are requested to register by completing the process for registration of e-mail address as under:

- Members holding shares in physical form can get their E-mail Id registered by contacting their respective Depository Participant.
- Members holding shares in demat form can get their E-mail Id registered by contacting our Registrar and Share Transfer Agent 'Bighare Services Private Limited' or their Email Id investor@bighare.com along with relevant documents to our Registrar and Share Transfer Agent Office No. 232 Park 5, First Floor, The Zodiac Mall, Bichol, Madras, Andhra Pradesh, India. Contact: (Andhra) Email: info@bighare.com and info@bighare.com.
- The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.lloydsenterprises.com and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of CDSL at www.evotingindia.com.

Result of Postal Ballot shall be declared within two working days from the conclusion of the Postal Ballot and shall be displayed on the Company's website at www.lloydsenterprises.com and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The Scrutinizer's decision on validity of the Postal Ballot shall be final.

For Lloyds Enterprises Limited Sd/-
Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 06th June, 2025

Members who have not registered their e-mail address with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company/Depository Participant, are requested to register by completing the process for registration of e-mail address as under:

- Members holding shares in physical form can get their E-mail Id registered by contacting their respective Depository Participant.
- Members holding shares in demat form can get their E-mail Id registered by contacting our Registrar and Share Transfer Agent 'Bighare Services Private Limited' or their Email Id investor@bighare.com along with relevant documents to our Registrar and Share Transfer Agent Office No. 232 Park 5, First Floor, The Zodiac Mall, Bichol, Madras, Andhra Pradesh, India. Contact: (Andhra) Email: info@bighare.com and info@bighare.com.
- The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.lloydsenterprises.com and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of CDSL at www.evotingindia.com.

Result of Postal Ballot shall be declared within two working days from the conclusion of the Postal Ballot and shall be displayed on the Company's website at www.lloydsenterprises.com and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The Scrutinizer's decision on validity of the Postal Ballot shall be final.

For Lloyds Enterprises Limited Sd/-
Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 06th June, 2025

ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED
Regd. Office: 18th floor, A Wing, Marathan Futurex, N M Joshi Marg, Lower Phase, F-1, Mumbai 400 013
Tel: 91 22 7106 1234 Fax: 91 22 2000 2107
CIN: L92132MH1982PLC028767
Website: www.zee.com

NOTICE OF THE POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, (Act) (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Rules), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations), the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India (SS-2), General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, other Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) from time to time (MCA Circulars) and other applicable laws, each as amended, seeking approval of the Members of Zee Entertainment Enterprises Limited (the 'Company'), on the Resolutions set forth in the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025.

Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025 along with explanatory statement through electronic mode on June 6, 2025 to those Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners and whose e-mail IDs are registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants (DPs) as on the cut-off date i.e. Friday, May 30, 2025. Accordingly, a physical copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

The Members, whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, May 30, 2025, being the cut-off date, are entitled to vote on the Resolutions set forth in Postal Ballot Notice through remote e-voting only. The voting rights of Members shall be in proportion to their shareholdings in the equity share capital of the Company as on the said cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Company has obtained the services of National Securities Depository Limited (NSDL), for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure to remote e-voting is given in the Postal Ballot Notice. The remote e-voting period will commence Monday, June 9, 2025, at 9:00 a.m. (IST) and conclude on Tuesday, June 8, 2025, at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting will be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on resolutions is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The resolutions passed by the Members through the Postal Ballot (through remote e-voting) shall be deemed to have been passed as it has been passed at a General Meeting of the Members. The resolutions, if approved by the requisite majority of Members by means of Postal Ballot, shall be deemed to have been passed on the last date of remote e-voting, i.e. on July 8, 2025. Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by sending a mail along with the relevant documents to the Company's RTA, MFGS Intime India Private Limited (earlier known as Link Intime India Private Limited, Unit: Zee Entertainment Enterprises Limited, C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West-400083 or the scanned copies of the documents may alternatively be mailed to RTA at mt.helodesk@in.mps.mfg.com or to the Company at share@zee.com. Members holding shares in demat form who have not updated their email addresses with the depository participant are requested to update their email addresses.

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website i.e. www.zee.com and also on the website of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evotingindia.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Vinita Nair, (Membership No. F10559, COP No.11902) Joint Managing Partner, M/s. Vinod Kohari & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of the e-voting by Postal Ballot will be announced on or before Wednesday, July 9, 2025. The result declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website i.e. www.zee.com and on the website of NSDL www.evotingindia.com. The Company shall simultaneously intimate to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed.

In case of any query on remote e-voting, Members may refer to FAQs and/or e-voting user manual available on website of NSDL at www.evotingindia.com or call on toll free no. 022-4986 7000.

By Order of the Board
For Zee Entertainment Enterprises Limited Sd/-
Ashish Agarwal
Company Secretary
Date: June 3, 2025

Over 7% flights cancelled for 3 mths at Delhi airport

DIAL CEO cites runway upgrade as reason for cancellations

DEEPAK PATEL
New Delhi, 6 June

About 7.5 per cent daily flights to and from the Delhi airport will be cancelled between June 15 and September 15 as one of its four runways undergoes an upgrade, Delhi International Airport Limited (DIAL) Chief Executive Officer (CEO) Vaidh Kumar Jaipuria said on Friday.

GMR Group-led DIAL operates the Delhi airport, which is the largest in the country.

"The Delhi airport handles 1,450 aircraft movements per day. Of these, 114 daily movements will be cancelled during the runway upgrade," Jaipuria said at a press conference.

"The number of cancellations will be in the range of 7-7.5 per cent, compared to the usual 3-4 per cent on a normal day. However, this time we have coordinated with airlines in advance and rescheduled flights accordingly, which will help reduce any cascading impact," he said.

Referring to a similar upgrade effort earlier this year, he added, "Last time, the lack of proper rescheduling led to cascading disruptions when wind patterns changed. This time, the impact on passengers will be much lower. Since they've been informed in advance, they will have enough time to rebook or make alternative arrangements," he added.

The upgrade of runway 10/28 will include installing an instrument landing system (ILS) and make it compliant with CAT III-B operations. CAT III-B is a precision landing system that allows aircraft to land in very low visibility conditions, such as dense fog.

It was originally scheduled for April-May. However, unexpected changes in wind patterns during that time severely affected flight operations, causing delays.

As a result, the Ministry of Civil Aviation — on April 21 — directed DIAL to postpone the upgrade and resume oper-



The airport will see flight cancellations between June 15 and September 15.

ations on the runway. The runway was made operational again on May 6, and the upgrade was deferred to June 15-September 15.

"The revised timeline was agreed upon by all airlines," Jaipuria said.

Following this, airlines collaborated with DIAL to rework slot allocations and align with the revised arrival capacity.

"The objective was to ensure optimum use of available runway capacity while maintaining on-time performance," he added.

"During the fog season, the arrival capacity of all runways comes down due to safety concerns, as arriving aircraft have to be spaced out," Jaipuria said.

"In case of westerly winds, arrivals drop from 42 per hour to 30 during CAT III-B operations. But with easterly winds, arrivals fall sharply from 42 per hour to just 15. Once the upgrade is complete, this number will go up to 30 even with easterly winds, significantly improving efficiency," he added.

"Every hour of fog disruption takes

Akasa to launch over 100 weekly flights from Navi Mumbai airport

Akasa Air will start more than 100 weekly domestic flights from the upcoming Navi Mumbai International Airport (NMIA), expanding to more than 300 domestic and over 50 international weekly departures in the winter schedule, it said on Friday.

Akasa joins IndiGo in confirming its early commitment to NMIA.

"No airline in India will have a larger percentage of its fleet and operations based out of NMIA than Akasa Air," said Vinay Dube, founder and chief executive officer (CEO) of Akasa Air.

AALH CEO Arun Bansal welcomed Akasa as an inaugural partner, stressing the airline's rapid growth and forward-looking approach.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

three hours for us to return to normal operations. This becomes much worse with easterly winds, where every hour of disruption takes six hours to recover. This impacts not just Delhi airport but also nearby ones.

Therefore, we decided to upgrade runway 10/28 and make it ready to handle CAT III-B flight operations," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

'By 2030, 80% of our new onboardings will be EVs'

Logistics startup Porter is aiming to bring in more driver partners and customers into its fold. In a video interaction with Uditsha Srivastava, cofounder and executive vice-chairman, Praveen Goel, talks about the recent fundraising, how the amount is being used, the company's expansion plans and partnership with ONDC, among others. Edited excerpts:

Let us know about the company's recent fundraising and how is the amount being used?

■ It's been a fairly large fundraise, a mix of both primary and secondary capital. With this amount, we want to go deeper and launch more categories. Over the years, we realised that there's still 20 per cent of customers that we are not able to service.

■ Delhi is the biggest city, because of different requirements. So, the intent is to solve that. E-loader is one segment that we want to launch across India. The other big objective is to go wider and replicate the same business model into multiple cities in India.

■ Also, launch in more international geographies where this model makes sense.

What are the target for the years to come?

■ In the next five years, we will move from 2 million to 10 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver

partners, and that number will exceed 1.2 million. We are present in close to 22 cities in India and this number will be around 50 cities.

■ There is also a massive sustainability goal. (EVs).

What are the top cities of operations for Porter? Which vehicle categories are the high-frequency ones?

■ Delhi is the biggest city, given its size and scale. After Delhi, there are Mumbai and Bengaluru. Chennai, Hyderabad, and Ahmedabad follow. We probably have around 10 vehicle categories and they're fairly distributed. We have four high-frequency categories, including two-wheelers, three-wheelers, and entry-level four-wheelers. They represent 80 per cent of our revenues. The other six categories comprise nearly 20 per cent of the revenues.

Do you also have fleet partners or is it a driver-owned model completely?

■ We are a completely asset-light model where the driver-partner has his vehicle. In



IN THE NEXT FIVE YEARS, WE WILL MOVE FROM 2 MILLION SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES WHO COME TO THE PLATFORM EVERY MONTH TO SERVICING MORE THAN 10 MILLION CUSTOMERS

more than 90 per cent of the cases, the owner and the driver are one person. We also have fleet operators, but they comprise less than 10 per cent of our volumes. There are more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

What's the company's revenue breakdown?

■ Around 85 per cent of our revenue comes from micro, small, and medium enter-

prises (MSMEs), which are local retail stores, small manufacturers, furniture shops, paints and chemicals shops, among others. Then, more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

What's the company's revenue breakdown?

■ Around 85 per cent of our revenue comes from micro, small, and medium enter-

FROM PAGE 1

Experts flag infra limitations at major airports as hurdle for ATR operations

The Indian carrier, which currently operates a fleet of about 46 ATR 72-600s, had earlier placed an order for 50 such aircraft in 2017 as part of a strategy to expand its regional footprint under the government's UDAN

scheme to improve air connectivity to underserved towns. Four aircraft since have been sold or leased to other.

Deliveries under that contract were completed by early 2025.

The ATR 72-600 is a twin-engine turboprop aircraft typically seating around 70 passengers, although IndiGo configures its planes in a high-density 78-seat layout. The aircraft is primarily deployed on short regional routes, with a range of about 1,370km.

"IndiGo has utilised the ATRs on all sorts of routes, from monopoly under regional connectivity scheme UDAN to some intra-metro high frequency ones in South India," said Ameya Joshi, aviation analyst and founder of the blog Network Thoughts. "The airline has also experimented with routes, some working well and some not continuing," he said.

The turboprop fleet enabled IndiGo to expand its network to smaller destinations such as Kolhapur, Kishanganj and Kadapa, which are not feasible for the airline's Airbus fleet, according to Joshi.

But the also flagged infrastructure limitations at major airports as a major hurdle for ATR operations.

"One of the biggest challenges has been getting slots at Delhi or Mumbai for the ATR," he said. "The development of secondary airports — like Navi Mumbai and Jewar — could ease this constraint and support rapid network expansion. How much does the government incentivise going forward also needs to be seen."

Since 2023, IndiGo has placed several aircraft orders. Last Sunday, it announced an order for 30 additional Airbus A320neo Widebody planes, adding to its April 2024 order for 30 A320s, bringing its total widebody order to 60 aircraft. Deliveries will begin in 2027 and continue into the

next decade. These widebody planes, which have larger fuel tanks than narrow-body A320s, are key to IndiGo's long-haul expansion, targeting routes like India-US, India-Europe, and India-Australia to compete with Air India and Gulf carriers.

The recent widebody orders followed IndiGo's record-breaking June 2023 order for 50 Airbus A320neo family aircraft to boost its narrow-body fleet for domestic and short-haul

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 430 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 430 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 430 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 430 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED)

Corporate Identification Number: L74140MNP1984PLC002592
Registered Office: 232 Park Street, The Zodiac Mall, Bichol, Madurai, India (MPL) - 625001
Contact Details: 7383330911 | Email-ID: info@indraindustries.in | Website: www.indraindustries.in

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE ISSUE

RIGHTS ISSUE OF UP TO 4,85,78,025 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) (EQUITY SHARES) EACH AT A PRICE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) PER EQUITY SHARE (EIGHTY SHARES) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹ 48,57,80,250 (RUPEES FORTY EIGHT CRORE FIFTY SEVEN LAKHS EIGHTY THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED) (COMPANY OR ISSUER) AT THE RATIO OF 15 (FIFTEEN) EQUITY SHARES FOR EVERY 2 (TWO) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, THURSDAY MAY 09, 2025 (ISSUE), THE ISSUE PRICE IS 1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE BEGINNING PAGE 130 OF THIS LETTER OF OFFER.'

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") - ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MAY 9, 2025

This notice should be read in conjunction with the LDF filed by the Company with the Stock Exchange and the ADFP and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please read the following:

This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday 23rd May 2025 and was scheduled to close on Wednesday, Friday 06th June 2025, has now been extended to Monday, June 09, 2025, by the Rights Issue Committee in meeting held on June 06, 2025 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Monday, 09, June, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, 09, June, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE

ISSUE OPENING DATE	ISSUE CLOSING DATE
FRIDAY 23RD MAY 2025	MONDAY 09TH MAY 2025

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

**Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms or on before the Issue Closing Date.

#Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee (on or prior to the Issue Closing Date).

This addendum shall be available on the respective websites of the Company at info@indraindustries.in the Registrar to the Issue at www.purushare.com and the Stock Exchanges at www.bseindia.com.

Accordingly, there is no change in the LDF and ADFP dated May 09, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing Date. Please note the Issue Closing Date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of Issue Closing Date.

INVESTORS MAY CHANGE THE LETTER OF OFFER, ABROGATED LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.

All capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For Bluegod Entertainment Limited
(Formerly Known As Indra Industries Limited)

Sd/-
Nilnashok Kumar Khanna
Managing Director

Date: May 09, 2025
Place: Indore

Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
CIN: 690818

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the BSE Limited. The Draft Letter of Offer is available on the website of Stock Exchanges where the Equity Shares are listed, i.e. BSE at www.bseindia.com, Our Company at info@indraindustries.in and the Registrar to the Issue at www.purushare.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Draft Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 31 of the Draft Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

LLOYDS ENTERPRISES LIMITED
Registered Address: A-2, 2nd Floor, Madhu Estate,
Parvathy Bahadur Marg, Lower Park, Mumbai - 400013
Tel: 022-69119111 Email: lloydenterprises@lloyds.in www.lloydenterprises.in
(CIN) L27100MH1988PLC041252

NOTICE FOR POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION
MEMBERS ARE HEREBY INFORMED THAT:

In compliance with Section 108 and 110 of Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Act" including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Government of India (the "MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), Lloyds Enterprises Limited (the "Company") has completed dispatch of Postal Ballot Notice along with explanatory statement on Friday, 06th June, 2025 through electronic mode only to those Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited or with their Depositories/Depository Participants on Friday, 30th May, 2025 ("cut-off date"). The requirement of sending physical copy of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form has been dispensed with vide relevant MCA circulars.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mitesh Shah, Partner of Minshah & Co., Practising Company Secretary (FCS No. 10070 and CP No. 12891), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and Postal Ballot.

In this regard, the Members are hereby informed that:

- a. The Business relating to approval of:

Sl. No.	Type of Resolution	Description of Resolution
1.	Special Resolution	Approval for Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
2.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Subsidiary Companies in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
3.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Associate Company, in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
4.	Special Resolution	Approval for the provision of loan by the Company for the purchase of its own shares by the trust / trustees for the benefit of employees under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
5.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Engineering Works Limited (formerly known as Lloyds Steel Industries Limited).
6.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals and Energy Limited.
7.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Realty Developers Limited.
8.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Indrajit Properties Private Limited.
9.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Infrastructure & Construction Limited.
10.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals & Minerals Trading LLP.

b. The e-voting period commences from Saturday, 07th June, 2025 (09:00 AM (IST)).

c. The e-voting period ends on Sunday, 08th June, 2025 (05:00 PM (IST)). When remote e-voting will be blocked and voting shall not be allowed beyond the said time.

d. Only those Members, whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date i.e., Friday, 30th May, 2025 are entitled to cast their votes on the Resolutions. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.

e. Members who have not received Postal Ballot Notice may write to investor@lloydenterprises.in and obtain the same.

f. For any query or grievance connected with the voting by electronic means, members may address to Mr. Rakesh Dahiya, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 29 Floor, Marathon Floor, Malabar Hill Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Park, Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk@cDSL.com or call on 022-23058424/43. Members may also write to the Company at the Email ID: investor@lloydenterprises.in

Members who have not registered their e-mail address with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company/Depository Participant, are requested to register by completing the process for registration of e-mail address as under:

• Members holding shares in physical form can get their E-mail ID registered by contacting their respective Depository Participant.

• Members holding shares in demat form can get their E-mail ID registered by contacting our Registrar and Share Transfer Agent "Bigshare Services Private Limited" or their Email ID investor@lloydenterprises.in along with relevant documents to our Registrar and Share Transfer Agent Office No. 307, 3rd Floor, Indira Business Park, next to Anura Centre, Malabar Cross Road, Andheri (East), Mumbai - 400095.

• The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.lloydenterprises.in and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of CDSL at www.evotingindia.com

Result of Postal Ballot shall be declared within two working days from the conclusion of the Postal Ballot and shall be displayed on the website of the Company's Registrar www.lloydenterprises.in and Central Depository Services (India) Limited www.evotingindia.com after communication to Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The Scrutinizer's decision on validity of the Postal Ballot shall be final.

For Lloyds Enterprises Limited
Sd/-
Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
CIN: 690818

Place: Mumbai
Date: 06th June, 2025

ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED
Regd. Office: 18th floor, A Wing, Marathon Futurex,
N.M. Joshi Marg, Lower Park, Mumbai 400 013
Tel: 91 22 7106 1234 Fax: 91 22 2001 2107
CIN: L92132MH1982PLC028767
Website: www.zee.com

NOTICE OF THE POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ("Act") (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations), the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, other Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars") and other applicable laws, each as amended, seeking approval of the Members of Zee Entertainment Enterprises Limited (the "Company"), on the Resolutions set forth in the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025.

Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025 along with explanatory statement through electronic mode on June 6, 2025 to those Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners and whose e-mail IDs are registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants ("DPs") as on the cut-off date i.e. Friday, May 30, 2025. Accordingly, a physical copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

The Members, whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, May 30, 2025, being the cut-off date, are entitled to vote on the Resolutions set forth in Postal Ballot Notice through remote e-voting only. The voting rights of Members shall be in proportion to their shareholdings in the equity share capital of the Company as on the said cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Company has obtained the services of National Securities Depository Limited ("NSDL"), for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure for remote e-voting is given in the Postal Ballot Notice. The remote e-voting period will commence Monday, June 9, 2025, at 9:00 a.m. (IST) and conclude on Tuesday, June 8, 2025, at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting will be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on resolutions is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The resolutions passed by the Members through the Postal Ballot (through remote e-voting) shall be deemed to have been passed as it has been passed at a General Meeting of the Members. The resolutions, if approved by the requisite majority of Members by means of Postal Ballot, shall be deemed to have been passed on the last date of remote e-voting, i.e. on July 8, 2025.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by sending a mail along with the relevant documents to the Company's RTA, MIFUG Intime India Private Limited (earlier known as Link Intime India Private Limited, Unit: Zee Entertainment Enterprises Limited, C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West-400083 or the scanned copies of the documents may alternatively be mailed to RTA at mt.helpdesk@in.mps.mifug.com or to the Company at share@zee.com. Members holding shares in demat form who have not updated their email addresses with the depository/ depository participant are requested to approach the concerned depository participant to update their email addresses.

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website i.e. www.zee.com and also on the website of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evotingindia.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Vinita Nair, (Membership No. F10559, COP No. 11902) Joint Managing Partner, M/s. Vinod Kohari & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of the e-voting by Postal Ballot will be announced on or before Wednesday, June 9, 2025. The result declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website i.e. www.zee.com and on the website of NSDL www.evotingindia.com. The Company shall simultaneously intimate to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed.

In case of any query on remote e-voting, Members may refer to FAQs and/or e-voting user manual available on website of NSDL at www.evotingindia.com or call on toll free no. 022-4986 7000.

By Order of the Board
For Zee Entertainment Enterprises Limited

Over 7% flights cancelled for 3 mths at Delhi airport

DIAL CEO cites runway upgrade as reason for cancellations

DEEPAK PATEL
New Delhi, June 6

About 7.5 per cent daily flights to and from the Delhi airport will be cancelled between June 15 and September 15 as one of its four runways undergoes an upgrade, Delhi International Airport Limited (DIAL) Chief Executive Officer (CEO) Vaidh Kumar Jaipuria said on Friday.

GMR Group-led DIAL operates the Delhi airport, which is the largest in the country.

"The Delhi airport handles 1,450 aircraft movements per day. Of these, 114 daily movements will be cancelled during the runway upgrade," Jaipuria said at a press conference.

"The number of cancellations will be in the range of 7-7.5 per cent, compared to the usual 3-4 per cent on a normal day. However, this time we have coordinated with airlines in advance and rescheduled flights accordingly, which will help reduce any cascading impact," he said.

Referring to a similar upgrade effort earlier this year, he added, "Last time, the lack of proper rescheduling led to cascading disruptions when wind patterns changed. This time, the impact on passengers will be much lower. Since they've been informed in advance, they will have enough time to rebook or make alternative arrangements," he said.

The upgrade of runway 10/28 will include installing an instrument landing system (ILS) and make it compliant with CAT III-B operations. CAT III-B is a precision landing system that allows aircraft to land in very low visibility conditions, such as dense fog.

It was originally scheduled for April-May. However, unexpected changes in wind patterns during that time severely affected flight operations, causing delays.

As a result, the Ministry of Civil Aviation — on April 21 — directed DIAL to postpone the upgrade and resume oper-



The airport will see flight cancellations between June 15 and September 15.

ations on the runway. The runway was made operational again on May 6, and the upgrade was deferred to June 15-September 15.

"The revised timeline was agreed upon by all airlines," Jaipuria said.

Following this, airlines collaborated with DIAL to rework slot allocations and align with the revised arrival capacity.

"The objective was to ensure optimum use of available runway capacity while maintaining on-time performance," he added.

"During the fog season, the arrival capacity of all runways comes down due to safety concerns, as arriving aircraft have to be spaced out," Jaipuria said.

"In case of westerly winds, arrivals drop from 42 per hour to 30 during CAT III-B operations. But with easterly winds, arrivals fall sharply from 42 per hour to just 15. Once the upgrade is complete, this number will go up to 30 even with easterly winds, significantly improving efficiency," he added.

"Every hour of fog disruption takes

Akasa to launch over 100 weekly flights from Navi Mumbai airport

Akasa Air will start more than 100 weekly domestic flights from the upcoming Navi Mumbai International Airport (NMAIA), expanding to more than 300 domestic and over 50 international weekly departures in the winter schedule, it said on Friday.

Akasa joins IndiGo in confirming its early commitment to NMAIA.

"No airline in India will have a larger percentage of its fleet and operations based out of NMAIA than Akasa Air," said Vinay Dube, founder and chief executive officer (CEO) of Akasa Air.

AAHL CEO Arun Bansal welcomed Akasa as an inaugural partner, stressing the airline's rapid growth and forward-looking approach.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

three hours for us to return to normal operations. This becomes much worse with easterly winds, where every hour of disruption takes six hours to recover. This impacts not just Delhi airport but also nearby ones.

Therefore, we decided to upgrade runway 10/28 and make it ready to handle CAT III-B flight operations," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

'By 2030, 80% of our new onboardings will be EVs'

Logistics startup Porter is aiming to bring in more driver partners and customers into its fold. In a video interaction with UdiShah Srivastava, cofounder and executive vice-chairman, Praveen Goel, talks about the recent fundraising, how the amount is being used, the company's expansion plans and partnership with ONDC, among others. Edited excerpts:

Let us know about the company's recent fundraising and how is the amount being used?

■ It's been a fairly large fundraise, a mix of both primary and secondary capital. With this amount, we want to go deeper and launch more categories. Over the years, we realised that there's still 20 per cent of customers that we are not able to service.

■ Delhi is the biggest city, because of different requirements. So, the intent is to solve that. E-loader is one segment that we want to launch across India. The other big objective is to go wider and replicate the same business model into multiple cities in India.

■ Also, launch in more international geographies where this model makes sense.

What are the top cities for operations for Porter? Which vehicle categories are the high-frequency ones?

■ Delhi is the biggest city, given its size and scale. After Delhi, there are Mumbai and Bengaluru. Chennai, Hyderabad, and Ahmedabad follow. We probably have around 10 vehicle categories and they're fairly distributed. We have four high-frequency categories, including two-wheelers, three-wheelers, and entry-level four-wheelers. They represent 80 per cent of our revenues. The other six categories comprise nearly 20 per cent of the revenues.

What are the targets for the year to come?

■ In the next five years, we will move from 2 million to 10 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver

partners, and that number will exceed 1.2 million. We are present in close to 22 cities in India and this number will be around 50 cities.

■ There is also a massive sustainability goal. (EVs).

What are the top cities for operations for Porter? Which vehicle categories are the high-frequency ones?

■ Delhi is the biggest city, given its size and scale. After Delhi, there are Mumbai and Bengaluru. Chennai, Hyderabad, and Ahmedabad follow. We probably have around 10 vehicle categories and they're fairly distributed. We have four high-frequency categories, including two-wheelers, three-wheelers, and entry-level four-wheelers. They represent 80 per cent of our revenues. The other six categories comprise nearly 20 per cent of the revenues.

Do you also have fleet partners or is it a driver-owned model completely?

■ We are a completely asset-light model where the driver-partner has his vehicle. In



IN THE NEXT FIVE YEARS, WE WILL MOVE FROM 2 MILLION SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES WHO COME TO THE PLATFORM EVERY MONTH TO SERVICING MORE THAN 10 MILLION CUSTOMERS

more than 90 per cent of the cases, the owner and the driver are one person. We also have fleet operators, but they comprise less than 10 per cent of our volumes. There are more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

What's the company's revenue breakdown?

■ Around 85 per cent of our revenue comes from micro, small, and medium enter-

prises (MSMEs), which are local retail stores, small manufacturers, furniture shops, paints and chemicals shops, among others. Then, more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

What's the company's revenue breakdown?

■ Around 85 per cent of our revenue comes from micro, small, and medium enter-

FROM PAGE 1

Experts flag infra limitations at major airports as hurdle for ATR operations

The Indian carrier, which currently operates a fleet of about 46 ATR 72-600s, had earlier placed an order for 50 such aircraft in 2017 as part of a strategy to expand its regional footprint under the government's UDAN

scheme to improve air connectivity to underserved towns. Four aircraft since have been sold or leased to other.

Deliveries under that contract were completed by early 2025.

The ATR 72-600 is a twin-engine turboprop aircraft typically seating around 70 passengers, although IndiGo configures its planes in a high-density 78-seat layout. The aircraft is primarily deployed on short regional routes, with a range of about 1,370km.

"IndiGo has utilised the ATRs on all sorts of routes, from monopoly under regional connectivity scheme UDAN to some intra-metro high frequency ones in South India," said Ameya Joshi, aviation analyst and founder of the blog Network Thoughts. "The airline has also experimented with routes, some working well and some not continuing," he said.

The turboprop fleet enabled IndiGo to expand its network to smaller destinations such as Kolhapur, Kishanganj and Kadapa, which are not feasible for the airline's Airbus fleet, according to Joshi.

But the also flagged infrastructure limitations at major airports as a major hurdle for ATR operations. "One of the biggest challenges has been getting slots at Delhi or Mumbai for the ATR," he said. "The development of secondary airports — like Navi Mumbai and Jewar — could ease this constraint and support rapid network expansion. How much does the government incentivise going forward also needs to be seen."

Since 2023, IndiGo has placed several aircraft orders. Last Sunday, it announced an order for 30 additional Airbus A320neo Widebody planes, adding to its April 2024 order for 30 A320s, bringing its total widebody order to 60 aircraft. Deliveries will begin in 2027 and continue into the

next decade. These widebody planes, which have larger fuel tanks than narrow-body A320s, are key to IndiGo's long-haul expansion, targeting routes like India-US, India-Europe, and India-Australia to compete with Air India and Gulf carriers.

The recent widebody orders followed IndiGo's record-breaking June 2023 order for 50 Airbus A320neo family aircraft to boost its narrow-body fleet for domestic and short-haul

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED)

Corporate Identification Number: L74140MPT1984PLC002592
Registered Office: 232, Park-5, The Zodiac Mall, Bichol, Marolund, Indore (M.P.) - 452001
Contact Details: 7383330911 | Email-ID: info@indraindustries.in | Website: www.indraindustries.in

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE ISSUE

RIGHTS ISSUE OF UP TO 4,85,78,025 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) (EQUITY SHARES) EACH AT A PRICE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) PER EQUITY SHARE (EIGHTY SHARES) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹ 48,57,80,250 (RUPEES FORTY EIGHT CRORE FIFTY SEVEN LAKHS EIGHTY THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED) (COMPANY OR ISSUER) AT THE RATIO OF 15 (FIFTEEN) EQUITY SHARES FOR EVERY 2 (TWO) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, THURSDAY MAY 09, 2025 (ISSUE). THE ISSUE PRICE IS 1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE BEGINNING PAGE 130 OF THIS LETTER OF OFFER.'

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") - ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MAY 9, 2025

This notice should be read in conjunction with the LDF filed by the Company with the Stock Exchange and the ADFP and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please read the following:

This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday 23rd May 2025 and was scheduled to close on Wednesday, Friday 06th June 2025, has now been extended to Monday, June 09, 2025, by the Rights Issue Committee in meeting held on June 06, 2025 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Monday, 09, June, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, 09, June, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE

ISSUE OPENING DATE	ISSUE CLOSING DATE
FRIDAY 23RD MAY 2025	MONDAY 09TH JUNE 2025

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).
**Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms or on before the Issue Closing Date.
#Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee (on or prior to the Issue Closing Date).
This addendum shall be available on the respective websites of the Company at info@indraindustries.in in the Registrar to the Issue at www.purushare.com and the Stock Exchanges at www.bseindia.com.

Accordingly, there is no change in the LDF and ADFP dated May 09, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing Date. Please note the Issue Closing Date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of Issue Closing Date.

INVESTORS MAY CHANGE THE LETTER OF OFFER, ABROGATED LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.
All capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For Bluegod Entertainment Limited
(Formerly Known As Indra Industries Limited) Sd/-
Nitinashok Kumar Khanna
Managing Director

Date: May 09, 2025
Place: Indore

For Registrar to the Issue Sd/-
Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
CIN: 856008

Place: Mumbai
Date: 06th June, 2025

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the BSE Limited. The Draft Letter of Offer is available on the website of Stock Exchanges where the Equity Shares are listed, i.e. BSE at www.bseindia.com, our Company at info@indraindustries.in and the Registrar to the Issue at www.purushare.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Draft Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 31 of the Draft Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

LLOYDS ENTERPRISES LIMITED
Registered Address: A-2, 2nd Floor, Madhu Estate,
Parvathy Bahadur Marg, Lower Park, Mumbai - 400013
www.lloydentertainment.in
Tel: 022-69119111 Email: lloydentertainment@lloyds.in

NOTICE FOR POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION
MEMBERS ARE HEREBY INFORMED THAT:

In compliance with Section 108 and 110 of Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Act" including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Rules") of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by Institute of Company Secretaries of India and any other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), Lloyds Enterprises Limited (the "Company") has completed dispatch of Postal Ballot Notice along with explanatory statement on Friday, 06th June, 2025 through electronic mode only to those Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited or with their Depository/Depository Participants on Friday, 30th May, 2025 ("Cut-off Date"). The requirement of sending physical copy of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form has been dispensed with vide relevant MCA circulars.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mitesh Shah, Partner of Mitesh Shah & Co., Practising Company Secretary (FCS No. 10070 and CP No. 12891), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and Postal Ballot.

In this regard, the Members are hereby informed that:

- The Business relating to approval of:

Sl. No.	Type of Resolution	Description of Resolution
1.	Special Resolution	Approval for Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
2.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Subsidiary Companies in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
3.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Associate Company, in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
4.	Special Resolution	Approval for the provision of loan by the Company for the purchase of its own shares by the trust / trustees for the benefit of employees under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
5.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Engineering Works Limited (formerly known as Lloyds Steel Industries Limited).
6.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals and Energy Limited.
7.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Realty Developers Limited.
8.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Indrajit Properties Private Limited.
9.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Infrastructure & Construction Limited.
10.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals & Minerals Trading LLP.

b. The e-voting period commences from Saturday, 07th June, 2025 (09:00 AM (IST)).

c. The e-voting period ends on Sunday, 08th June, 2025 (05:00 PM (IST)) when remote e-voting will be blocked and voting shall not be allowed beyond the said time.

d. Only those Members, whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date, i.e., Friday, 30th May, 2025 are entitled to cast their votes on the Resolutions. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.

e. Members who have not received Postal Ballot Notice may write to investor@lloydentertainment.in and obtain the same.

f. For any query or grievance connected with the voting by electronic means, members may address to Mr. Rakesh Dahiya, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 29 Floor, Marathon Floor, Malabar Hill Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Park (E), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk@cDSL.com or call on 022-23058424/43. Members may also write to the Company at the Email ID: investor@lloyds.in

Members who have not registered their e-mail address with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company/Depository Participant, are required to register by completing the process for registration of e-mail address as under:

- Members holding shares in physical form can get their E-mail Id registered by contacting their respective Depository Participant.
- Members holding shares in demat form can get their E-mail Id registered by contacting our Registrar and Share Transfer Agent "Bigshare Services Private Limited" or their Email ID investor@lloydentertainment.in along with relevant documents to our Registrar and Share Transfer Agent Office No. 307, 3rd Floor, Lower Park Business Park, next to Anura Centre, Malabar Cross Road, (Anura East), Mumbai - 400005.

g. The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.lloydentertainment.in and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of CDSL at www.evotingindia.com.

Result of Postal Ballot shall be declared within two working days from the conclusion of the Postal Ballot and shall be displayed on the website of the Company's Registrar www.lloydentertainment.in and Central Depository Services (India) Limited www.evotingindia.com after communication to Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The Scrutinizer's decision on validity of the Postal Ballot shall be final.

For Lloyds Enterprises Limited Sd/-
Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
CIN: 856008

Place: Mumbai
Date: 06th June, 2025

ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED
Regd. Office: 18th floor, A Wing, Marathon Futurex,
N.M. Joshi Marg, Lower Park, Mumbai 400 013
Tel: 91 22 7106 1234 Fax: 91 22 2300 2107
CIN: L92132MH1982PLC028767
Website: www.zee.com

NOTICE OF THE POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ("Act") (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, other Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars") and other applicable laws, each as amended, seeking approval of the Members of Zee Entertainment Enterprises Limited (the "Company"), on the Resolutions set forth in the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025.

Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025 along with explanatory statement through electronic mode on June 6, 2025 to those Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners and whose e-mail IDs are registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants ("DPs") as on the cut-off date i.e. Friday, May 30, 2025. Accordingly, a physical copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

The Members, whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, May 30, 2025, being the cut-off date, are entitled to vote on the Resolutions set forth in Postal Ballot Notice through remote e-voting only. The voting rights of Members shall be in proportion to their shareholdings in the equity share capital of the Company as on the said cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Company has obtained the services of National Securities Depository Limited ("NSDL"), for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure to remote e-voting by the Members is provided in the Postal Ballot Notice. The remote e-voting period will commence Monday, June 9, 2025, at 9:00 a.m. (IST) and conclude on Tuesday, June 8, 2025, at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting will be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on resolutions is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The resolutions passed by the Members through the Postal Ballot (through remote e-voting) shall be deemed to have been passed as it has been passed at a General Meeting of the Members. The resolutions, if approved by the requisite majority of Members by means of Postal Ballot, shall be deemed to have been passed on the last date of remote e-voting, i.e. on July 8, 2025. Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by sending a mail along with the relevant documents to the Company's RTA, MFGS Intime India Private Limited (earlier known as Link Intime India Private Limited, Unit: Zee Entertainment Enterprises Limited, C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West-400083 or the scanned copies of the documents may alternatively be mailed to RTA at mt.helpdesk@nse.com or to the Company at share@zee.com. Members holding shares in demat form who have not updated their email addresses with the depository/ depository participant are requested to approach the concerned depository participant to update their email addresses.

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website i.e. www.zee.com and also on the website of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evotingindia.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Vinita Nair, (Membership No. F10559, COP No. 11902) Joint Managing Partner, M/s. Vinod Kohari & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of the e-voting by Postal Ballot will be announced on or before Wednesday, July 9, 2025. The result declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website i.e. www.zee.com and on the website of NSDL www.evotingindia.com. The Company shall simultaneously intimate to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed.

In case of any query on remote e-voting, Members may refer to FAQs and/or e-voting user manual available on website of NSDL at www.evotingindia.com or call on toll free no. 022-4986 7000.

By Order of the Board
For Zee Entertainment Enterprises Limited Sd/-
Ashish Agarwal
Company Secretary
Date: June 3, 2025 Membership No. FCS 6669



Over 7% flights cancelled for 3 mths at Delhi airport

DIAL CEO cites runway upgrade as reason for cancellations

DEEPAK PATEL
New Delhi, 6 June

About 7.5 per cent daily flights to and from the Delhi airport will be cancelled between June 15 and September 15 as one of its four runways undergoes an upgrade, Delhi International Airport Limited (DIAL) Chief Executive Officer (CEO) Videsh Kumar Jaipuria said on Friday.

GMR Group-led DIAL operates the Delhi airport, which is the largest in the country.

"The Delhi airport handles 1,450 aircraft movements per day. Of these, 114 daily movements will be cancelled during the runway upgrade," Jaipuria said at a press conference.

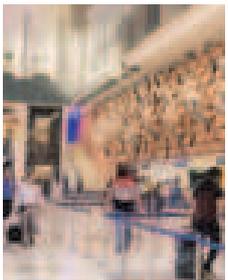
"The number of cancellations will be in the range of 7-7.5 per cent, compared to the usual 3-4 per cent on a normal day. However, this time we have coordinated with airlines in advance and rescheduled flights accordingly, which will help reduce any cascading impact," he said.

Referring to a similar upgrade effort earlier this year, he added, "Last time, the lack of proper rescheduling led to cascading disruptions when wind patterns changed. This time, the impact on passengers will be much lower. Since they've been informed in advance, they will have enough time to rebook or make alternative arrangements," he added.

The upgrade of runway 10/28 will include installing an instrument landing system (ILS) and make it compliant with CAT III-B operations. CAT III-B is a precision landing system that allows aircraft to land in very low visibility conditions, such as dense fog.

It was originally scheduled for April-May. However, unexpected changes in wind patterns during that time severely affected flight operations, causing delays.

As a result, the Ministry of Civil Aviation — on April 21 — directed DIAL to postpone the upgrade and resume oper-



The airport will see flight cancellations between June 15 and September 15.

ations on the runway. The runway was made operational again on May 6, and the upgrade was deferred to June 15-September 15.

"The revised timeline was agreed upon by all airlines," Jaipuria said.

Following this, airlines collaborated with DIAL to rework slot allocations and align with the revised arrival capacity.

"The objective was to ensure optimum use of available runway capacity while maintaining on-time performance," he added.

"During the fog season, the arrival capacity of all runways comes down due to safety concerns, as arriving aircraft have to be spaced out," Jaipuria said.

"In case of westerly winds, arrivals drop from 42 per hour to 30 during CAT III-B operations. But with easterly winds, arrivals fall sharply from 42 per hour to just 15. Once the upgrade is complete, this number will go up to 30 even with easterly winds, significantly improving efficiency," he added.

"Every hour of fog disruption takes three hours for us to return to normal operations. This becomes much worse with easterly winds, where every hour of disruption takes six hours to recover. This impacts not just Delhi airport but also nearby ones."

Therefore, we decided to upgrade runway 10/28 and make it ready to handle CAT III-B flight operations," he said. Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Akasa to launch over 100 weekly flights from Navi Mumbai airport

Akasa Air will start more than 100 weekly domestic flights from the upcoming Navi Mumbai International Airport (NMAIA), expanding to more than 300 domestic and over 50 international weekly departures in the winter schedule, it said on Friday.

Akasa joins IndiGo in confirming its early commitment to NMAIA.

"No airline in India will have a larger percentage of its fleet and operations based out of NMAIA than Akasa Air," said Vinay Dube, founder and chief executive officer (CEO) of Akasa Air.

AAHL CEO Arun Bansal welcomed Akasa as an inaugural partner, stressing the airline's rapid growth and forward-looking approach.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

'By 2030, 80% of our new onboardings will be EVs'

Logistics startup Porter is aiming to bring in more driver partners and customers into its fold. In a video interaction with Uditsha Srivastava,

co-founder and executive vice-chairman, Praveen Goel, talks about the recent fundraising, how the amount is being used, the company's expansion plans and partnership with ONDC, among others. Edited excerpts:

Let us know about the company's recent fundraising and how is the amount being used?
■ It's been a fairly large fundraise, a mix of both primary and secondary capital. With this amount, we want to go deeper and launch more categories. Over the years, we realised that there's still 20 per cent of customers that we are not able to service.

■ Delhi is the biggest city, because of different requirements. So, the intent is to solve that. E-loader is one segment that we want to launch across India. The other big objective is to go wider and replicate the same business model into multiple cities in India. Also, launch in more international geographies where this model makes sense.

What are the top cities of operations for Porter?
Which vehicle categories are the high-frequency ones?
■ Delhi is the biggest city, given its size and scale. After Delhi, there are Mumbai and Bengaluru. Chennai, Hyderabad, and Ahmedabad follow. We probably have around 10 vehicle categories and they're fairly distributed. We have four high-frequency categories, including two-wheelers, three-wheelers, and entry-level four-wheelers. They represent 80 per cent of our revenues. The other six categories comprise nearly 20 per cent of the revenues.

Do you also have fleet partners or is it a driver-owner model completely?
■ We are a completely asset-light model where the driver-partner has his vehicle. In

What percentage of vehicles is currently electric?
■ Metro, Tier-1 cities typically do slightly better compared to Tier-II markets. In Delhi, 70 per cent of three-wheelers are EVs. At an overall level, this number might be around 30-40 per cent. In cargo vehicles, India still doesn't have EVs for all payload capacities.

What's the company's revenue breakdown?
■ Around 85 per cent of our revenue comes from micro, small, and medium enter-



IN THE NEXT FIVE YEARS, WE WILL MOVE FROM 2 MILLION SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES WHO COME TO THE PLATFORM EVERY MONTH TO SERVICING MORE THAN 10 MILLION CUSTOMERS

prises (MSMEs), which are local retail stores, small manufacturers, furniture shops, paints and chemicals stores, among others. Then, more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?
■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

FROM PAGE 1

Experts flag infra limitations at major airports as hurdle for ATR operations

The Indian carrier, which currently operates a fleet of about 46 ATR 72-600s, had earlier placed an order for 50 such aircraft in 2017 as part of a strategy to expand its regional footprint under the government's UDAN

scheme to improve air connectivity to underserved towns. Four aircraft since have been sold or leased to other.

Deliveries under that contract were completed by early 2025.

The ATR 72-600 is a twin-engine turboprop aircraft typically seating around 70 passengers, although IndiGo configures its planes in a high-density 78-seat layout. The aircraft is primarily deployed on short regional routes, with a range of about 1,300km.

"IndiGo has utilised the ATRs on all sorts of routes, from monopoly under regional connectivity scheme UDAN to some intra-metro high frequency ones in South India," said Ameya Joshi, aviation analyst and founder of the blog Network Thoughts. "The airline has also experimented with routes, some working well and some not continuing," he said.

The turboprop fleet enabled IndiGo to expand its network to smaller destinations such as Kolhapur, Kishanganj and Kadapa, which are not feasible for the airline's Airbus fleet, according to Joshi.

But the also flagged infrastructure limitations at major airports as a major hurdle for ATR operations. "One of the biggest challenges has been getting slots at Delhi or Mumbai for the ATR," he said. "The development of secondary airports — like Navi Mumbai and Jewar — could ease this constraint and support rapid network expansion. How much does the government incentivise going forward also needs to be seen."

Since 2023, IndiGo has placed several aircraft orders. Last Sunday, it announced an order for 30 additional Airbus A320neo Widebody planes, adding to its April 2024 order for 30 A320s, bringing its total widebody order to 60 aircraft. Deliveries will begin in 2027 and continue into the

next decade. These widebody planes, which have larger fuel tanks than narrow-body A320s, are key to IndiGo's long-haul expansion, targeting routes like India-US, India-Europe, and India-Australia to compete with Air India and Gulf carriers.

The recent widebody orders followed IndiGo's record-breaking June 2023 order for 50 Airbus A320neo family aircraft to boost its narrow-body fleet for domestic and short-haul

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 430 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes. The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 430 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes. The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 430 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes. The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 430 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes. The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 430 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes. The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

LLOYDS ENTERPRISES LIMITED
Registered Address: A-2, 2nd Floor, Madhu Estate, Parsipalya Bahadur Marg, Lower Park, Mumbai - 400013
Tel: 022-6911 9111 Email: lloydsestimates@lloyds.in www.lloydsestimates.in
CIN: L27100MH1988PLC041252

NOTICE FOR POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION
MEMBERS ARE HEREBY INFORMED THAT:

In compliance with Section 108 and 110 of Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Act" including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Rules") of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), Lloyds Enterprises Limited ("the Company") has completed dispatch of Postal Ballot Notice along with explanatory statement on Friday, 06th June, 2025 through electronic mode only to those Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited or with their Depository/Depository Participants on Friday, 30th May, 2025 ("Cut-off Date"). The requirement of sending physical copy of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form has been dispensed with vide relevant MCA circulars.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mitesh Shah, Partner of Mitesh Shah & Co., Practising Company Secretary (FCS No. 10070 and CP No. 12891), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and Postal Ballot.

In this regard, the Members are hereby informed that:

- The Business relating to approval of:

Sl. No.	Type of Resolution	Description of Resolution
1.	Special Resolution	Approval for Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
2.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Subsidiary Companies, in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
3.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Associate Company, in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
4.	Special Resolution	Approval for the provision of loan by the Company for the purchase of its own shares by the trust / trustees for the benefit of employees under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
5.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Engineering Works Limited (formerly known as Lloyds Steel Industries Limited).
6.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals and Energy Limited.
7.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Realty Developers Limited.
8.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Indrajit Properties Private Limited.
9.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Infrastructure & Construction Limited.
10.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals & Minerals Trading LLP.

b. The e-voting period commences from Saturday, 07th June, 2025 (09:00 AM (IST)).

c. The e-voting period ends on Sunday, 08th June, 2025 (05:00 PM (IST)). When remote e-voting will be blocked and voting shall not be allowed beyond the said time.

d. Only those Members, whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date i.e., Friday, 30th May, 2025 are entitled to cast their votes on the Resolutions. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.

e. Members who have not received Postal Ballot Notice may write to investor@lloydsestimates.in and obtain the same.

f. For any query or grievance connected with the voting by electronic means, members may address to Mr. Rakesh Dahiya, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 2nd Floor, Marathon Floor, Malabar Hill Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Park, Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk@cDSL.com or call on 022-23058424/43. Members may also write to the Company at the Email ID: investor@lloydsestimates.in.

Members who have not registered their e-mail address with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company/Depository Participant, are required to register by completing the process for registration of e-mail address as under:

- Members holding shares in physical form can get their E-mail Id registered by contacting their respective Depository Participant.
- Members holding shares in demat form can get their E-mail Id registered by contacting our Registrar and Share Transfer Agent "Bigshare Services Private Limited" or their Email ID investor@lloydsestimates.in along with relevant documents to our Registrar and Share Transfer Agent Office No. 30th Floor, Maheshwari Business Park, next to Anura Centre, Malabar Cross Road, Andheri (East), Mumbai - 400095.

g. The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.lloydsestimates.in and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of CDSL at www.evotingindia.com.

Result of Postal Ballot shall be declared within two working days from the conclusion of the Postal Ballot and shall be displayed on the Company's website at www.lloydsestimates.in and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of NSDL at www.evotingindia.com.

For Lloyds Enterprises Limited
Sd/-
Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
CIN: 690018

Place: Mumbai
Date: 06th June, 2025

ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED
Regd. Office: 18th floor, A Wing, Marathon Futurax, N.M. Joshi Marg, Lower Park, Mumbai 400 013
Tel: 91 22 7106 1234 Fax: 91 22 2001 2107
CIN: L92132MH1982PLC028767
Website: www.zee.com

NOTICE OF THE POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION
NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ("Act") (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, other Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars") and other applicable laws, each as amended, seeking approval of the Members of Zee Entertainment Enterprises Limited ("the Company"), on the Resolutions set forth in the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025.

Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025 along with explanatory statement through electronic mode on June 6, 2025 to those Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners and whose e-mail IDs are registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) / Depository Participants ("DPs") as on the cut-off date i.e. Friday, May 30, 2025. Accordingly, a physical copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

The Members, whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, May 30, 2025, being the cut-off date, are entitled to vote on the Resolutions set forth in Postal Ballot Notice through remote e-voting only. The voting rights of Members shall be in proportion to their shareholdings in the equity share capital of the Company as on the said cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Company has obtained the services of National Securities Depository Limited ("NSDL"), for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure to remote e-voting is given in the Postal Ballot Notice. The remote e-voting period will commence Monday, June 9, 2025, at 9:00 a.m. (IST) and conclude on Tuesday, June 8, 2025, at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting will be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on resolutions is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The resolutions passed by the Members through the Postal Ballot (through remote e-voting) shall be deemed to have been passed as it has been passed at a General Meeting of the Members. The resolutions, if approved by the requisite majority of Members by means of Postal Ballot, shall be deemed to have been passed on the last date of remote e-voting, i.e. on July 8, 2025. Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by sending a mail along with the relevant documents to the Company's RTA, MIFUG Intime India Private Limited (earlier known as Link Intime India Private Limited, Unit: Zee Entertainment Enterprises Limited, C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West-400083 or the scanned copies of the documents may alternatively be mailed to RTA at mt.helpdesk@nse.in or to the Company at share@zee.com. Members holding shares in demat form who have not updated their email addresses with the depository/ depository participant are requested to approach the concerned depository participant to update their email addresses.

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website i.e. www.zee.com and also on the website of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evotingindia.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Vinita Nair, (Membership No. F10559, COP No. 11902) Joint Managing Partner, Ms. Vinod Kohari & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of the e-voting by Postal Ballot will be announced on or before Wednesday, July 9, 2025. The result declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website i.e. www.zee.com and on the website of NSDL www.evotingindia.com. The Company shall simultaneously intimate to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed.

In case of any query on remote e-voting, Members may refer to FAQs and/or e-voting user manual available on website of NSDL at www.evotingindia.com or call on toll free no. 022-4986 7000.

By Order of the Board
For Zee Entertainment Enterprises Limited
Sd/-
Ashish Agarwal
Company Secretary
Date: June 3, 2025
Membership No. FCS 6669



Over 7% flights cancelled for 3 mths at Delhi airport

DIAL CEO cites runway upgrade as reason for cancellations

DEEPAK PATEL
New Delhi, 6 June

About 7.5 per cent daily flights to and from the Delhi airport will be cancelled between June 15 and September 15 as one of its four runways undergoes an upgrade, Delhi International Airport Limited (DIAL) Chief Executive Officer (CEO) Vaidh Kumar Jaipuria said on Friday.

GMR Group-led DIAL operates the Delhi airport, which is the largest in the country.

"The Delhi airport handles 1,45,000 aircraft movements per day. Of these, 114 daily movements will be cancelled during the runway upgrade," Jaipuria said at a press conference.

"The number of cancellations will be in the range of 7-7.5 per cent, compared to the usual 3-4 per cent on a normal day. However, this time we have coordinated with airlines in advance and rescheduled flights accordingly, which will help reduce any cascading impact," he said.

Referring to a similar upgrade effort earlier this year, he added, "Last time, the lack of proper rescheduling led to cascading disruptions when wind patterns changed. This time, the impact on passengers will be much lower. Since they've been informed in advance, they will have enough time to rebook or make alternative arrangements," he added.

The upgrade of runway 10/28 will include installing an instrument landing system (ILS) and make it compliant with CAT III-B operations. CAT III-B is a precision landing system that allows aircraft to land in very low visibility conditions, such as dense fog.

It was originally scheduled for April-May. However, unexpected changes in wind patterns during that time severely affected flight operations, causing delays.

As a result, the Ministry of Civil Aviation — on April 21 — directed DIAL to postpone the upgrade and resume oper-



The airport will see flight cancellations between June 15 and September 15.

ations on the runway. The runway was made operational again on May 6, and the upgrade was deferred to June 15-September 15.

"The revised timeline was agreed upon by all airlines," Jaipuria said. Following this, airlines collaborated with DIAL to rework slot allocations and align with the revised arrival capacity.

"The objective was to ensure optimum use of available runway capacity while maintaining on-time performance," he added.

"During the fog season, the arrival capacity of all runways comes down due to safety concerns, as arriving aircraft have to be spaced out," Jaipuria said.

"In case of westerly winds, arrivals drop from 42 per hour to 30 during CAT III-B operations. But with easterly winds, arrivals fall sharply from 42 per hour to just 15. Once the upgrade is complete, this number will go up to 30 even with easterly winds, significantly improving efficiency," he added.

"Every hour of fog disruption takes three hours for us to return to normal operations. This becomes much worse with easterly winds, where every hour of disruption takes six hours to recover. This impacts not just Delhi airport but also nearby ones."

Therefore, we decided to upgrade runway 10/28 and make it ready to handle CAT III-B flight operations," he said. Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Akasa to launch over 100 weekly flights from Navi Mumbai airport

Akasa joins IndiGo in confirming its early commitment to NMA.

"No airline in India will have a larger percentage of its fleet and operations based out of NMA than Akasa Air," said Vinay Dube, founder and chief executive officer (CEO) of Akasa Air.

AAHL CEO Arun Bansal welcomed Akasa as an inaugural partner, stressing the airline's rapid growth and forward-looking approach.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Therefore, we decided to upgrade runway 10/28 and make it ready to handle CAT III-B flight operations," he said. Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

'By 2030, 80% of our new onboardings will be EVs'

Logistics startup Porter is aiming to bring in more driver partners and customers into its fold. In a video interaction with Udit Shah Srivastava,

co-founder and executive vice-chairman, Praveen Goel, talks about the recent fundraising, how the amount is being used, the company's expansion plans and partnership with ONDC, among others. Edited excerpts:

Let us know about the company's recent fundraising and how is the amount being used?

It's been a fairly large fundraise, a mix of both primary and secondary capital. With this amount, we want to go deeper and launch more categories. Over the years, we realised that there's still 20 per cent of customers that we are not able to service.

Delhi is the biggest city, because of different requirements. So, the intent is to solve that. E-loader is one segment that we want to launch across India. The other big objective is to go wider and replicate the same business model into multiple cities in India.

Also, launch in more international geographies where this model makes sense.

What are the top cities for operations for Porter? Which vehicle categories are the high-frequency ones?

Delhi is the biggest city, given its size and scale. After Delhi, there are Mumbai and Bengaluru. Chennai, Hyderabad, and Ahmedabad follow. We probably have around 10 vehicle categories and they're fairly distributed. We have four high-frequency categories, including two-wheelers, three-wheelers, and entry-level four-wheelers. They represent 80 per cent of our revenues. The other six categories comprise nearly 20 per cent of the revenues.

In the next five years, we will move from 12 million to 20 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver partners, and that number will exceed 1.2 million. We are present in close to 22 cities in India and this number will be around 50 cities.

It's also a massive sustainability goal. (EVs).

What are the top cities for operations for Porter? Which vehicle categories are the high-frequency ones?

Delhi is the biggest city, given its size and scale. After Delhi, there are Mumbai and Bengaluru. Chennai, Hyderabad, and Ahmedabad follow. We probably have around 10 vehicle categories and they're fairly distributed. We have four high-frequency categories, including two-wheelers, three-wheelers, and entry-level four-wheelers. They represent 80 per cent of our revenues. The other six categories comprise nearly 20 per cent of the revenues.

In the next five years, we will move from 12 million to 20 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver partners, and that number will exceed 1.2 million. We are present in close to 22 cities in India and this number will be around 50 cities.

It's also a massive sustainability goal. (EVs).

What are the top cities for operations for Porter? Which vehicle categories are the high-frequency ones?

Delhi is the biggest city, given its size and scale. After Delhi, there are Mumbai and Bengaluru. Chennai, Hyderabad, and Ahmedabad follow. We probably have around 10 vehicle categories and they're fairly distributed. We have four high-frequency categories, including two-wheelers, three-wheelers, and entry-level four-wheelers. They represent 80 per cent of our revenues. The other six categories comprise nearly 20 per cent of the revenues.

In the next five years, we will move from 12 million to 20 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver partners, and that number will exceed 1.2 million. We are present in close to 22 cities in India and this number will be around 50 cities.

It's also a massive sustainability goal. (EVs).

What are the top cities for operations for Porter? Which vehicle categories are the high-frequency ones?

Delhi is the biggest city, given its size and scale. After Delhi, there are Mumbai and Bengaluru. Chennai, Hyderabad, and Ahmedabad follow. We probably have around 10 vehicle categories and they're fairly distributed. We have four high-frequency categories, including two-wheelers, three-wheelers, and entry-level four-wheelers. They represent 80 per cent of our revenues. The other six categories comprise nearly 20 per cent of the revenues.

In the next five years, we will move from 12 million to 20 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver partners, and that number will exceed 1.2 million. We are present in close to 22 cities in India and this number will be around 50 cities.

It's also a massive sustainability goal. (EVs).

What are the top cities for operations for Porter? Which vehicle categories are the high-frequency ones?

Delhi is the biggest city, given its size and scale. After Delhi, there are Mumbai and Bengaluru. Chennai, Hyderabad, and Ahmedabad follow. We probably have around 10 vehicle categories and they're fairly distributed. We have four high-frequency categories, including two-wheelers, three-wheelers, and entry-level four-wheelers. They represent 80 per cent of our revenues. The other six categories comprise nearly 20 per cent of the revenues.

In the next five years, we will move from 12 million to 20 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver partners, and that number will exceed 1.2 million. We are present in close to 22 cities in India and this number will be around 50 cities.

It's also a massive sustainability goal. (EVs).

What are the top cities for operations for Porter? Which vehicle categories are the high-frequency ones?

Delhi is the biggest city, given its size and scale. After Delhi, there are Mumbai and Bengaluru. Chennai, Hyderabad, and Ahmedabad follow. We probably have around 10 vehicle categories and they're fairly distributed. We have four high-frequency categories, including two-wheelers, three-wheelers, and entry-level four-wheelers. They represent 80 per cent of our revenues. The other six categories comprise nearly 20 per cent of the revenues.

In the next five years, we will move from 12 million to 20 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver partners, and that number will exceed 1.2 million. We are present in close to 22 cities in India and this number will be around 50 cities.

It's also a massive sustainability goal. (EVs).



IN THE NEXT FIVE YEARS, WE WILL MOVE FROM 2 MILLION SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES WHO COME TO THE PLATFORM EVERY MONTH TO SERVICING MORE THAN 10 MILLION CUSTOMERS

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

Praveen Goel, co-founder and executive vice-chairman of Zeo Entertainment, is seen in a meeting with investors and partners.

FROM PAGE 1

Experts flag infra limitations at major airports as hurdle for ATR operations

The Indian carrier, which currently operates a fleet of about 46 ATR 72-600s, had earlier placed an order for 50 such aircraft in 2017 as part of a strategy to expand its regional footprint under the government's UDAN

scheme to improve air connectivity to underserved towns. Four aircraft since have been sold or leased to other.

Deliveries under that contract were completed by early 2025.

The ATR 72-600 is a twin-engine turboprop aircraft typically seating around 70 passengers, although IndiGo configures its planes in a high-density 78-seat layout. The aircraft is primarily deployed on short regional routes, with a range of about 1,300km.

"IndiGo has utilised the ATRs on all sorts of routes, from monopoly under regional connectivity scheme UDAN to some intra-metro high frequency ones in South India," said Ameya Joshi, aviation analyst and founder of the blog Network Thoughts. "The airline has also experimented with routes, some working well and some not continuing," he said.

The turboprop fleet enabled IndiGo to expand its network to smaller destinations such as Kolhapur, Kishanganj and Kadapa, which are not feasible for the airline's Airbus fleet, according to Joshi.

But the also flagged infrastructure limitations at major airports as a major hurdle for ATR operations.

"One of the biggest challenges has been getting slots at Delhi or Mumbai for the ATR," he said. "The development of secondary airports — like Navi Mumbai and Jewar — could ease this constraint and support rapid network expansion. How much does the government incentivise going forward also needs to be seen."

Since 2023, IndiGo has placed several aircraft orders. Last Sunday, it announced an order for 30 additional Airbus A320neo Widebody planes, adding to its April 2024 order for 30 A320s, bringing its total widebody order to 60 aircraft. Deliveries will begin in 2027 and continue into the

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

LLOYDS ENTERPRISES LIMITED
Registered Address: A-2, 2nd Floor, Madhu Estate, Parkside, Bandra West, Mumbai - 400015
Tel: 022-6911 9111 Email: lloydsestimates@lloyds.in www.lloydsestimates.in
(CIN) L27100MH1988PLC041252

NOTICE FOR POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

MEMBERS ARE HEREBY INFORMED THAT: In compliance with Section 108 and 110 of Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Act" including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force; read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Rules") of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretarial Standards on General Meetings (SS-G) issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), Lloyds Enterprises Limited ("the Company") has completed dispatch of Postal Ballot Notice along with explanatory statement on Friday, 06th June, 2025 through electronic mode only to those Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited or with their Depository/Depository Participants on Friday, 30th May, 2025 ("Cut-off Date"). The requirement of sending physical copy of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form has been dispensed with vide relevant MCA circulars.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mitesh Shah, Partner of Mitesh Shah & Co., Practising Company Secretary (FCS No. 10070 and CP No. 12891), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and Postal Ballot.

In this regard, the Members are hereby informed that:

- a. The Business relating to approval of:

Sl. No.	Type of Resolution	Description of Resolution
1.	Special Resolution	Approval for Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
2.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Subsidiary Companies in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
3.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Associate Company, in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
4.	Special Resolution	Approval for the provision of loan by the Company for the purchase of its own shares by the trust / trustees for the benefit of employees under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
5.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Engineering Works Limited (formerly known as Lloyds Steel Industries Limited).
6.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals and Energy Limited.
7.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Realty Developers Limited.
8.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Indrajit Properties Private Limited.
9.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Infrastructure & Construction Limited.
10.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals & Minerals Trading LLP.

b. The e-voting period commences from Saturday, 07th June, 2025 (09:00 AM (IST)).

c. The e-voting period ends on Sunday, 08th June, 2025 (05:00 PM (IST)). When remote e-voting will be blocked and voting shall not be allowed beyond the said time.

d. Only those Members, whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date i.e., Friday, 30th May, 2025 are entitled to cast their votes on the Resolutions. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.

e. Members who have not received Postal Ballot Notice may write to investor@lloydsestimates.in and obtain the same.

f. For any query or grievance connected with the voting by electronic means, members may address to Mr. Rakesh Dahiya, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 2nd Floor, Marathon Floor, Malabar Hill Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400017 or send an email to helpdesk@cDSL.com or call on 022-2305842/43. Members may also write to the Company at the Email ID: investor@lloydsestimates.in

Members who have not registered their e-mail address with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company/Depository Participant, are required to register by completing the process for registration of email address as under:

• Members holding shares in physical form can get their E-mail Id registered by contacting their respective Depository Participant.

• Members holding shares in demat form can get their E-mail Id registered by contacting our Registrar and Share Transfer Agent "Bigshare Services Private Limited" or their Email ID investor@lloydsestimates.in along with relevant documents to our Registrar and Share Transfer Agent Office No. 207, 2nd Floor, Parkside, Bandra West, Mumbai - 400015.

• The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.lloydsestimates.in and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of CDSL at www.evotingindia.com

Result of Postal Ballot shall be declared within two working days from the conclusion of the Postal Ballot and shall be displayed on the Company's website at www.lloydsestimates.in and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The Scrutinizer's decision on validity of the Postal Ballot shall be final.

For Lloyds Enterprises Limited
Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 06th June, 2025

BLUEGOD ENT

Over 7% flights cancelled for 3 mths at Delhi airport

DIAL CEO cites runway upgrade as reason for cancellations

DEEPAK PATEL
New Delhi, 6 June

About 7.5 per cent daily flights to and from the Delhi airport will be cancelled between June 15 and September 15 as one of its four runways undergoes an upgrade, Delhi International Airport Limited (DIAL) Chief Executive Officer (CEO) Videsh Kumar Jaipuria said on Friday.

GMR Group-led DIAL operates the Delhi airport, which is the largest in the country.

"The Delhi airport handles 1,450 aircraft movements per day. Of these, 114 daily movements will be cancelled during the runway upgrade," Jaipuria said at a press conference.

"The number of cancellations will be in the range of 7-7.5 per cent, compared to the usual 3-4 per cent on a normal day. However, this time we have coordinated with airlines in advance and rescheduled flights accordingly, which will help reduce any cascading impact," he said.

Referring to a similar upgrade effort earlier this year, he added, "Last time, the lack of proper rescheduling led to cascading disruptions when wind patterns changed. This time, the impact on passengers will be much lower. Since they've been informed in advance, they will have enough time to rebook or make alternative arrangements," he added.

The upgrade of runway 10/28 will include installing an instrument landing system (ILS) and make it compliant with CAT III-B operations. CAT III-B is a precision landing system that allows aircraft to land in very low visibility conditions, such as dense fog.

It was originally scheduled for April-May. However, unexpected changes in wind patterns during that time severely affected flight operations, causing delays.

As a result, the Ministry of Civil Aviation — on April 21 — directed DIAL to postpone the upgrade and resume oper-



The airport will see flight cancellations between June 15 and September 15.

ations on the runway. The runway was made operational again on May 6, and the upgrade was deferred to June 15-September 15.

"The revised timeline was agreed upon by all airlines," Jaipuria said.

Following this, airlines collaborated with DIAL to rework slot allocations and align with the revised arrival capacity.

"The objective was to ensure optimum use of available runway capacity while maintaining on-time performance," he added.

"During the fog season, the arrival capacity of all runways comes down due to safety concerns, as arriving aircraft have to be spaced out," Jaipuria said.

"In case of westerly winds, arrivals drop from 42 per hour to 30 during CAT III-B operations. But with easterly winds, arrivals fall sharply from 42 per hour to just 15. Once the upgrade is complete, this number will go up to 30 even with easterly winds, significantly improving efficiency," he added.

"Every hour of fog disruption takes

Akasa to launch over 100 weekly flights from Navi Mumbai airport

Akasa Air will start more than 100 weekly domestic flights from the upcoming Navi Mumbai International Airport (NMAIA), expanding to more than 300 domestic and over 50 international weekly departures in the winter schedule, it said on Friday.

Akasa joins IndiGo in confirming its early commitment to NMAIA.

"No airline in India will have a larger percentage of its fleet and operations based out of NMAIA than Akasa Air," said Vinay Dube, founder and chief executive officer (CEO) of Akasa Air.

AAHL CEO Arun Bansal welcomed Akasa as an inaugural partner, stressing the airline's rapid growth and forward-looking approach.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

three hours for us to return to normal operations. This becomes much worse with easterly winds, where every hour of disruption takes six hours to recover. This impacts not just Delhi airport but also nearby ones.

Therefore, we decided to upgrade runway 10/28 and make it ready to handle CAT III-B flight operations," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

'By 2030, 80% of our new onboardings will be EVs'

Logistics startup Porter is aiming to bring in more driver partners and customers into its fold. In a video interaction with Uditsha Srivastava, cofounder and executive vice-chairman, Praveen Goel, talks about the recent fundraising, how the amount is being used, the company's expansion plans and partnership with ONDC, among others. Edited excerpts:

Let us know about the company's recent fundraising and how is the amount being used?

■ It's been a fairly large fundraise, a mix of both primary and secondary capital. With this amount, we want to go deeper and launch more categories. Over the years, we realised that there's still 20 per cent of customers that we are not able to service.

■ Delhi is the biggest city, because of different requirements. So, the intent is to solve that. E-loader is one segment that we want to launch across India. The other big objective is to go wider and replicate the same business model into multiple cities in India.

■ Also, launch in more international geographies where this model makes sense.

What are the target for the years to come?

■ In the next five years, we will move from 2 million to 10 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver

partners, and that number will exceed 1.2 million. We are present in close to 22 cities in India and this number will be around 50 cities.

■ There is also a massive sustainability goal. (EVs).

What are the top cities of operations for Porter? Which vehicle categories are the high-frequency ones?

■ Delhi is the biggest city, given its size and scale. After Delhi, there are Mumbai and Bengaluru. Chennai, Hyderabad, and Ahmedabad follow. We probably have around 10 vehicle categories and they're fairly distributed. We have four high-frequency categories, including two-wheelers, three-wheelers, and entry-level four-wheelers. They represent 80 per cent of our revenues. The other six categories comprise nearly 20 per cent of the revenues.

Do you also have fleet partners or is it a driver-owned model completely?

■ We are a completely asset-light model where the driver-partner has his vehicle. In



more than 90 per cent of the cases, the owner and the driver are one person. We also have fleet operators, but they comprise less than 10 per cent of our volumes. There are more than 100 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

What's the company's revenue breakdown?

■ Around 85 per cent of our revenue comes from micro, small, and medium enter-

prises (MSMEs), which are local retail stores, small manufacturers, furniture shops, paints and chemicals shops, among others. Then, more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

FROM PAGE 1

Experts flag infra limitations at major airports as hurdle for ATR operations

The Indian carrier, which currently operates a fleet of about 46 ATR 72-600s, had earlier placed an order for 50 such aircraft in 2017 as part of a strategy to expand its regional footprint under the government's UDAN scheme to improve air connectivity to underserved towns. Four aircraft since have been sold or leased to other.

Deliveries under that contract were completed by early 2025.

The ATR 72-600 is a twin-engine turboprop aircraft typically seating around 70 passengers, although IndiGo configures its planes in a high-density 78-seat layout. The aircraft is primarily deployed on short regional routes, with a range of about 1,370km.

"IndiGo has utilised the ATRs on all sorts of routes, from monopoly under regional connectivity scheme UDAN to some intra-metro high frequency ones in South India," said Ameya Joshi, aviation analyst and founder of the blog Network Thoughts. "The airline has also experimented with routes, some working well and some not continuing," he said.

The turboprop fleet enabled IndiGo to expand its network to smaller destinations such as Kolhapur, Kishanganj and Kadapa, which are not feasible for the airline's Airbus fleet, according to Joshi.

But the also flagged infrastructure limitations at major airports as a major hurdle for ATR operations. "One of the biggest challenges has been getting slots at Delhi or Mumbai for the ATR," he said. "The development of secondary airports — like Navi Mumbai and Jewar — could ease this constraint and support rapid network expansion. How much does the government incentivise going forward also needs to be seen."

Since 2023, IndiGo has placed several aircraft orders. Last Sunday, it announced an order for 30 additional Airbus A320neo Widebody planes, adding to its April 2024 order for 30 A320s, bringing its total widebody order to 60 aircraft. Deliveries will begin in 2027 and continue into the

next decade. These widebody planes, which have larger fuel tanks than narrow-body A320s, are key to IndiGo's long-haul expansion, targeting routes like India-US, India-Europe, and India-Australia to compete with Air India and Gulf carriers.

The recent widebody orders followed IndiGo's record-breaking June 2023 order for 50 Airbus A320neo family aircraft to boost its narrow-body fleet for domestic and short-haul

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent widebody orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED)
Corporate Identification Number: L74140MPT1984PLC002592
Registered Office: 232, Park-5, The Zodiac Mall, Bichol, Marolund, Indore (MP), 452001
Contact Details: 7383330911 | Email-ID: info@indraindustries.in | Website: www.indraindustries.in
Contact Person: Ms. Sweety Purohit, Company Secretary & Compliance Officer.

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE ISSUE
RIGHTS ISSUE OF UP TO 4,85,78,025 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) (EQUITY SHARES) EACH AT A PRICE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) PER EQUITY SHARE (EIGHTY SHARES) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹ 48,57,80,250 (RUPEES FORTY EIGHT CRORE FIFTY SEVEN LAKHS EIGHTY THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED) (COMPANY OR ISSUER) AT THE RATIO OF 15 (FIFTEEN) EQUITY SHARES FOR EVERY 2 (TWO) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, THURSDAY MAY 09, 2025 (ISSUE). THE ISSUE PRICE IS 1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE BEGINNING PAGE 130 OF THIS LETTER OF OFFER.'

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") - ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MAY 9, 2025
This notice should be read in conjunction with the LDF filed by the Company with the Stock Exchange and the ADFP and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please read the following:
This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday 23rd May 2025 and was scheduled to close on Wednesday, Friday 06th June 2025, has now been extended to Monday, June 09, 2025, by the Rights Issue Committee in meeting held on June 06, 2025 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Monday, 09, June, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, 09, June, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE

ISSUE OPENING DATE	ISSUE CLOSING DATE
FRIDAY 23RD MAY 2025	MONDAY 09TH MAY 2025

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).
**Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms on or before the Issue Closing Date.
#Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee (on or prior to the Issue Closing Date).
This addendum shall be available on the respective websites of the Company at info@indraindustries.in the Registrar to the Issue at www.purushare.com and the Stock Exchanges at www.bseindia.com.
Accordingly, there is no change in the LDF and ADFP dated May 09, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing Date. Please note the Issue Closing Date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of Issue Closing Date.
INVESTORS MAY CHANGE THE ISSUE OFFER, ABROGATED LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.
All capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For Bluegod Entertainment Limited
(Formerly Known As Indra Industries Limited)
Sd/-
Nilnashok Kumar Khanna
Managing Director
Date: May 09, 2025
Place: Indore

For Bluegod Entertainment Limited
(Formerly Known As Indra Industries Limited)
Sd/-
Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 06th June, 2025
Place: Mumbai

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the BSE Limited. The Draft Letter of Offer is available on the website of Stock Exchanges where the Equity Shares are listed, i.e. BSE at www.bseindia.com, our Company at info@indraindustries.in and the Registrar to the Issue at www.purushare.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Draft Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 31 of the Draft Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

LLOYDS ENTERPRISES LIMITED
Registered Address: A-2, 2nd Floor, Madhu Estate,
Parvathy Bahadur Marg, Lower Park, Mumbai - 400013
www.lloydenterprises.in
Tel: 022-69119111 Email: lloydenterprises@lloyd.in

NOTICE FOR POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION
MEMBERS ARE HEREBY INFORMED THAT:
In compliance with Section 108 and 110 of Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Act" including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Rules") of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), Lloyds Enterprises Limited (the "Company") has completed dispatch of Postal Ballot Notice along with explanatory statement on Friday, 06th June, 2025 through electronic mode only to those Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited or with their Depository/Depository Participants on Friday, 30th May, 2025 ("cut-off date"). The requirement of sending physical copy of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form has been dispensed with vide relevant MCA circulars.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mitesh Shah, Partner of Mitesh Shah & Co., Practising Company Secretary (FCS No. 10070 and CP No. 12891), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and Postal Ballot.

In this regard, the Members are hereby informed that:

- The Business relating to approval of:

Sl. No.	Type of Resolution	Description of Resolution
1.	Special Resolution	Approval for Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
2.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Subsidiary Companies in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
3.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Associate Company, in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
4.	Special Resolution	Approval for the provision of loan by the Company for the purchase of its own shares by the trust / trustees for the benefit of employees under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
5.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Engineering Works Limited (formerly known as Lloyds Steel Industries Limited).
6.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals and Energy Limited.
7.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Realty Developers Limited.
8.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Indrajit Properties Private Limited.
9.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Infrastructure & Construction Limited.
10.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals & Minerals Trading LLP.

- The e-voting period commences from Saturday, 07th June, 2025 (09:00 AM (IST)).
- The e-voting period ends on Sunday, 08th June, 2025 (05:00 PM (IST)).
- Only those Members, whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date, i.e., Friday, 30th May, 2025 are entitled to cast their votes on the Resolutions. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.
- Members who have not received Postal Ballot Notice may write to investor@lloydenterprises.in and obtain the same.
- For any query or grievance connected with the voting by electronic means, members may address to Mr. Rakesh Dahiya, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 29 Floor, Marathon Floor, Malabar Hill Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Park, Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk@cDSL.com or call on 022-23058424/43. Members may also write to the Company at the Email ID: investor@lloydenterprises.in.
- The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.lloydenterprises.in and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of CDSL at www.evotingindia.com.
- Result of Postal Ballot shall be declared within two working days from the conclusion of the Postal Ballot and shall be displayed on the Company's website at www.lloydenterprises.in and Central Depository Services (India) Limited www.evotingindia.com after communication to Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The Scrutinizer's decision on validity of the Postal Ballot shall be final.

Members who have not registered their e-mail address with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company/Depository Participant, are requested to register by completing the process for registration of e-mail address as under:

- Members holding shares in physical form can get their E-mail Id registered by contacting their respective Depository Participant.
- Members holding shares in demat form can get their E-mail Id registered by contacting our Registrar and Share Transfer Agent "Bigshare Services Private Limited" or their Email ID investor@lloydenterprises.in along with relevant documents to our Registrar and Share Transfer Agent Office No. 307, 3rd Floor, Lower Park, near to Ahura Centre, Malabar Cross Road, (Andheri East), Mumbai - 400095.

By Order of the Board

For Bluegod Entertainment Limited
Sd/-
Ashish Agarwal
Company Secretary
Date: June 3, 2025
Place: Mumbai

ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED
Regd. Office: 18th floor, A Wing, Marathon Futurex,
N.M. Joshi Marg, Lower Park, Mumbai 400 013
Tel: 91 22 7106 1234 Fax: 91 22 2000 2107
CIN: L92132MH1982PLC028767
Website: www.zee.com

NOTICE OF THE POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION
NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ("Act") (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, other Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars") and other applicable laws, each as amended, seeking approval of the Members of Zee Entertainment Enterprises Limited (the "Company"), on the Resolutions set forth in the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025.

Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025 along with explanatory statement through electronic mode on June 6, 2025 to those Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners and whose e-mail IDs are registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants ("DPs") as on the cut-off date i.e. Friday, May 30, 2025. Accordingly, a physical copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

The Members, whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, May 30, 2025, being the cut-off date, are entitled to vote on the Resolutions set forth in Postal Ballot Notice through remote e-voting only. The voting rights of Members shall be in proportion to their shareholdings in the equity share capital of the Company as on the said cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Company has obtained the services of National Securities Depository Limited ("NSDL"), for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure to remote e-voting is given in the Postal Ballot Notice. The remote e-voting period will commence Monday, June 9, 2025, at 9:00 a.m. (IST) and conclude on Tuesday, June 8, 2025, at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting will be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on resolutions is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The resolutions passed by the Members through the Postal Ballot (through remote e-voting) shall be deemed to have been passed as it has been passed at a General Meeting of the Members. The resolutions, if approved by the requisite majority of Members by means of Postal Ballot, shall be deemed to have been passed on the last date of remote e-voting, i.e. on July 8, 2025. Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by sending a mail along with the relevant documents to the Company's RTA, MIFUG Intime India Private Limited (earlier known as Link Intime India Private Limited, Unit: Zee Entertainment Enterprises Limited, C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West-400083 or the scanned copies of the documents may alternatively be mailed to RTA at mt.helpdesk@nse.com or to the Company at share@zee.com. Members holding shares in demat form who have not updated their email addresses with the depository/ depository participant are requested to approach the concerned depository participant to update their email addresses.

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website i.e. www.zee.com and also on the website of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evotingindia.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Vinita Nair, (Membership No. F10559, COP No. 11902) Joint Managing Partner, M/s. Vinod Kohari & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of the e-voting by Postal Ballot will be announced on or before Wednesday, June 9, 2025. The result declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website i.e. www.zee.com and on the website of NSDL www.evotingindia.com. The Company shall simultaneously intimate to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed.

In case of any query on remote e-voting, Members may refer to FAQs and/or e-voting user manual available on website of NSDL at www.evotingindia.com or call on toll free no. 022-4986 7000.

By Order of the Board

For Zee Entertainment Enterprises Limited
Sd/-
Ashish Agarwal
Company Secretary
Date: June 3, 2025
Place: Mumbai

Over 7% flights cancelled for 3 mths at Delhi airport

DIAL CEO cites runway upgrade as reason for cancellations

DEEPAK PATEL
New Delhi, 6 June

About 7.5 per cent daily flights to and from the Delhi airport will be cancelled between June 15 and September 15 as one of its four runways undergoes an upgrade, Delhi International Airport Limited (DIAL) Chief Executive Officer (CEO) Videsh Kumar Jaipuria said on Friday.

GMR Group-led DIAL operates the Delhi airport, which is the largest in the country.

"The Delhi airport handles 1,450 aircraft movements per day. Of these, 114 daily movements will be cancelled during the runway upgrade," Jaipuria said at a press conference.

"The number of cancellations will be in the range of 7-7.5 per cent, compared to the usual 3-4 per cent on a normal day. However, this time we have coordinated with airlines in advance and rescheduled flights accordingly, which will help reduce any cascading impact," he said.

Referring to a similar upgrade effort earlier this year, he added, "Last time, the lack of proper rescheduling led to cascading disruptions when wind patterns changed. This time, the impact on passengers will be much lower. Since they've been informed in advance, they will have enough time to rebook or make alternative arrangements," he added.

The upgrade of runway 10/28 will include installing an instrument landing system (ILS) and make it compliant with CAT III-B operations. CAT III-B is a precision landing system that allows aircraft to land in very low visibility conditions, such as dense fog.

It was originally scheduled for April-May. However, unexpected changes in wind patterns during that time severely affected flight operations, causing delays.

As a result, the Ministry of Civil Aviation — on April 21 — directed DIAL to postpone the upgrade and resume oper-



The airport will see flight cancellations between June 15 and September 15.

ations on the runway. The runway was made operational again on May 6, and the upgrade was deferred to June 15-September 15.

"The revised timeline was agreed upon by all airlines," Jaipuria said.

Following this, airlines collaborated with DIAL to rework slot allocations and align with the revised arrival capacity.

"The objective was to ensure optimum use of available runway capacity while maintaining on-time performance," he added.

"During the fog season, the arrival capacity of all runways comes down due to safety concerns, as arriving aircraft have to be spaced out," Jaipuria said.

"In case of westerly winds, arrivals drop from 42 per hour to 30 during CAT III-B operations. But with easterly winds, arrivals fall sharply from 42 per hour to just 15. Once the upgrade is complete, this number will go up to 30 even with easterly winds, significantly improving efficiency," he added.

"Every hour of fog disruption takes

Akasa to launch over 100 weekly flights from Navi Mumbai airport

Akasa Air will start more than 100 weekly domestic flights from the upcoming Navi Mumbai International Airport (NMAIA), expanding to more than 300 domestic and over 50 international weekly departures in the winter schedule, it said on Friday.

Akasa joins IndiGo in confirming its early commitment to NMAIA.

"No airline in India will have a larger percentage of its fleet and operations based out of NMAIA than Akasa Air," said Vinay Dube, founder and chief executive officer (CEO) of Akasa Air.

AAHL CEO Arun Bansal welcomed Akasa as an inaugural partner, stressing the airline's rapid growth and forward-looking approach.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

three hours for us to return to normal operations. This becomes much worse with easterly winds, where every hour of disruption takes six hours to recover. This impacts not just Delhi airport but also nearby ones.

Therefore, we decided to upgrade runway 10/28 and make it ready to handle CAT III-B flight operations," he said.

Jaipuria also acknowledged the growing impact of changing weather conditions on airport operations.

"We are conducting a study as part of our climate change mitigation plan. This kind of erratic weather behaviour is increasing every year. Based on the findings, we will develop a mitigation strategy," he said.

'By 2030, 80% of our new onboardings will be EVs'

Logistics startup Porter is aiming to bring in more driver partners and customers into its fold. In a video interaction with Uditsha Srivastava, cofounder and executive vice-chairman, Praveen Goel, talks about the recent fundraising, how the amount is being used, the company's expansion plans and partnership with ONDC, among others. Edited excerpts:

Let us know about the company's recent fundraising and how is the amount being used?

■ It's been a fairly large fundraise, a mix of both primary and secondary capital. With this amount, we want to go deeper and launch more categories. Over the years, we realised that there's still 20 per cent of customers that we are not able to service.

■ Delhi is the biggest city, because of different requirements. So, the intent is to solve that. E-loader is one segment that we want to launch across India. The other big objective is to go wider and replicate the same business model into multiple cities in India.

■ Also, launch in more international geographies where this model makes sense.

■ In the next five years, we will move from 2 million to 10 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver

partners, and that number will exceed 1.2 million. We are present in close to 22 cities in India and this number will be around 50 cities.

■ There is also a massive sustainability goal. (EVs).

■ Delhi is the biggest city, because of different requirements. So, the intent is to solve that. E-loader is one segment that we want to launch across India. The other big objective is to go wider and replicate the same business model into multiple cities in India.

■ Also, launch in more international geographies where this model makes sense.

■ In the next five years, we will move from 2 million to 10 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver

partners, and that number will exceed 1.2 million. We are present in close to 22 cities in India and this number will be around 50 cities.

■ There is also a massive sustainability goal. (EVs).

■ Delhi is the biggest city, because of different requirements. So, the intent is to solve that. E-loader is one segment that we want to launch across India. The other big objective is to go wider and replicate the same business model into multiple cities in India.

■ Also, launch in more international geographies where this model makes sense.

■ In the next five years, we will move from 2 million to 10 million and medium enterprises (SMEs) who come to the platform every month to servicing more than 10 million customers. We have around 300,000 driver



IN THE NEXT FIVE YEARS, WE WILL MOVE FROM 2 MILLION SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES WHO COME TO THE PLATFORM EVERY MONTH TO SERVING MORE THAN 10 MILLION CUSTOMERS

What percentage of vehicles is currently electric?

■ Metro, Tier-1 cities typically do slightly better compared to Tier-II markets. In Delhi, 70 per cent of three-wheelers are EVs. At an overall level, this number might be around 30-40 per cent. In cargo vehicles, India still doesn't have EVs for all payload capacities.

■ We are a completely asset-light model where the driver-partner has his vehicle. In

prises (MSMEs), which are local retail stores, small manufacturers, furniture shops, paints and chemicals shops, among others. Then, more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

■ Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

■ We are a completely asset-light model where the driver-partner has his vehicle. In

prises (MSMEs), which are local retail stores, small manufacturers, furniture shops, paints and chemicals shops, among others. Then, more than 10 per cent comes from consumers directly. The remaining 5 per cent is from large enterprises like e-commerce firms, courier companies, fast moving consumer goods (FMCG) firms and direct-to-consumer (D2C) brands.

■ Porter integrated with ONDC in September 2024. How is it working out?

■ It's another demand channel for us. There's been a positive trend line in terms of orders. Earlier, we only used to have two-wheeler orders, but now we see a blend of two-wheelers and mini trucks. Since our integration, we have seen a 30 per cent month-on-month increase in orders.

FROM PAGE 1

Experts flag infra limitations at major airports as hurdle for ATR operations

The Indian carrier, which currently operates a fleet of about 46 ATR 72-600s, had earlier placed an order for 50 such aircraft in 2017 as part of a strategy to expand its regional footprint under the government's UDAN

scheme to improve air connectivity to underserved towns. Four aircraft since have been sold or leased to other.

Deliveries under that contract were completed by early 2025.

The ATR 72-600 is a twin-engine turboprop aircraft typically seating around 70 passengers, although IndiGo configures its planes in a high-density 78-seat layout. The aircraft is primarily deployed on short regional routes, with a range of about 1,370km.

"IndiGo has utilised the ATRs on all sorts of routes, from monopoly under regional connectivity scheme UDAN to some intra-metro high frequency ones in South India," said

international operations. Airbus Chief Commercial Officer Benoit de Saint-Exupery said on Sunday that IndiGo's total order book now stands at 1,400 aircraft, including these recent wide-body orders and earlier large-scale A320 family purchases over the past decade.

ATR is a joint venture between Airbus and the Italian aerospace group Leonardo, with each owning a 50 per cent stake in the manufacturer. IndiGo's current fleet

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

The Paris Air Show, held biennially at Le Bourget near Paris, is one of the world's largest aerospace exhibitions, where major aircraft manufacturers and airlines announce new products, technologies, and commercial deals. This year's edition will take place from June 16 to 22.

stands at about 400 aircraft, comprising 46 ATR 72-600s, three leased widebody aircraft, and a mix of narrow-body Airbus planes.

LLOYDS ENTERPRISES LIMITED

Registered Address: A-2, 2nd Floor, Madhu Estate, Parsipada, Barabar, Madhav Nagar, Mumbai - 400013
Tel: 022-69119111 Email: lloydsevents@lloyds.in www.lloydsevents.in
(CIN) L2710MH1988PLC041252

NOTICE FOR POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

MEMBERS ARE HEREBY INFORMED THAT: In compliance with Section 108 and 110 of Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Act" including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions if any ("the Rules") of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification(s), amendments), classification(s), substitution(s) and re-enactment(s) thereof at the time being in force), Lloyds Enterprises Limited ("the Company") has completed dispatch of Postal Ballot Notice along with explanatory statement on Friday, 06th June, 2025 through electronic mode only to those Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited or with their Depository Participant(s) on Friday, 30th May, 2025 ("Cut-off Date"). The requirement of sending physical copy of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form has been dispensed with vide relevant MCA circulars.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mitesh Shah, Partner of Mitesh Shah & Co., Practising Company Secretary (FCS No. 10070 and CP No. 12891), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and Postal Ballot.

In this regard, the Members are hereby informed that:

- a. The Business relating to approval of:

Sl. No.	Type of Resolution	Description of Resolution
1.	Special Resolution	Approval for Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
2.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Subsidiary Company, in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
3.	Special Resolution	Approval of grant of options to the employees of Associate Company, in India or outside India under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
4.	Special Resolution	Approval for the provision of loan by the Company for the purchase of its own shares by the trust / trustees for the benefit of employees under Lloyds Enterprises Limited Employee Stock Option Plan - 2025.
5.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Engineering Works Limited (formerly known as Lloyds Metals and Energy Limited).
6.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals and Energy Limited.
7.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Realty Developers Limited.
8.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Indrajit Properties Private Limited.
9.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Infrastructure & Construction Limited.
10.	Ordinary Resolution	Approval for material related party transaction with Lloyds Metals & Minerals Trading LLP.

b. The e-voting period commences from Saturday, 07th June, 2025 (09:00 AM (IST)).

c. The e-voting period ends on Sunday, 08th June, 2025 (05:00 PM (IST)). When remote e-voting will be blocked and voting shall not be allowed beyond the said time.

d. Only those Members, whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date i.e., Friday, 30th May, 2025 are entitled to cast their votes on the Resolutions. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.

e. Members who have not received Postal Ballot Notice may write to investor@lloydsevents.in and obtain the same.

f. For any query or grievance connected with the voting by electronic means, members may address to Mr. Rakesh Dahiya, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 29th Floor, Marathon Futurex, Malabar Hill Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk@cDSL.com or call on 022-23058424/43. Members may also write to the Company at the Email ID: investor@lloydsevents.in.

Members who have not registered their e-mail address with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company/Depository Participant, are required to register by completing the process for registration of e-mail address as under:

- Members holding shares in physical form can get their E-mail Ids registered by contacting their respective Depository Participant.
- Members holding shares in demat form can get their E-mail Ids registered by contacting our Registrar and Share Transfer Agent "Bigshare Services Private Limited" or their Email ID investor@lloydsevents.in along with relevant documents to our Registrar and Share Transfer Agent Office No. 30th Floor, Marathon Futurex, Malabar Hill Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013. Members may also write to the Company at the Email ID: investor@lloydsevents.in.

• The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.lloydsevents.in and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of CDSL at www.evotingindia.com.

Result of Postal Ballot shall be declared within two working days from the conclusion of the Postal Ballot and shall be displayed on the Company's website at www.lloydsevents.in and on the Stock Exchanges i.e. website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on website of CDSL at www.evotingindia.com.

The Scrutinizer's decision on validity of the Postal Ballot shall be final.

For Lloyds Enterprises Limited
Pranjali Mahapatra
Company Secretary & Compliance Officer
CIN: 690108

Place: Mumbai Date: 06th June, 2025

ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: 18th floor, A Wing, Marathon Futurex, N.M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013
Tel: 91 22 7106 1234 Fax: 91 22 2001 2107
CIN: L9210MH1982PLC028767
Website: www.zee.com

NOTICE OF THE POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ("Act") (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, other Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars") and other applicable laws, each as amended, seeking approval of the Members of Zee Entertainment Enterprises Limited ("the Company"), on the Resolutions set forth in the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025.

Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the Postal Ballot Notice dated June 3, 2025 along with explanatory statement through electronic mode on June 6, 2025 to those Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners and whose e-mail IDs are registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent (RTA)/ Depository Participant ("DPs") as on the cut-off date i.e. Friday, May 30, 2025. Accordingly, a physical copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

The Members, whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, May 30, 2025, being the cut-off date, are entitled to vote on the Resolutions set forth in Postal Ballot Notice through remote e-voting only. The voting rights of Members shall be in proportion to their shareholdings in the equity share capital of the Company as on the said cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Company has obtained the services of National Securities Depository Limited ("NSDL"), for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure for remote e-voting is available on the Company's website with the Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

The Company has obtained the services of National Securities Depository Limited ("NSDL"), for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure for remote e-voting is available on the Company's website with the Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

The Company has obtained the services of National Securities Depository Limited ("NSDL"), for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure for remote e-voting is available on the Company's website with the Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

The Company has obtained the services of National Securities Depository Limited ("NSDL"), for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure for remote e-voting is available on the Company's website with the Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

The Company has obtained the services of National Securities Depository Limited ("NSDL"), for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure for remote e-voting is available on the Company's website with the Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

The Company has obtained the services of National Securities Depository Limited ("NSDL"), for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure for remote e-voting is available on the Company's website with the Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members.

For Zee Entertainment Enterprises Limited
Sd/-
Ashish Agarwal
Company Secretary
Membership No. FCS 6669

Place: Mumbai Date: June 3, 2025

3 प्रतिशत सीआरआर नया सामान्य स्तर

प्रभावी नकदी प्रबंधन के लिए 3 प्रतिशत सीआरआर पर्याप्त

अंजलि कुमारी
मुंबई, 6 जून

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) जरूरतों को 100 आधार अंक घटाकर शुद्ध मांग और सावधि देनदारी (एनडीटीएल) का 3 प्रतिशत करने का फैसला किया है। यह फैसला चरणबद्ध तरीके से 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाले पखवाड़ों से प्रभावी होगा।

सीआरआर में कटौती से दिसंबर 2025 तक बैंकिंग व्यवस्था में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये की प्राथमिक नकदी आएगी। ऐतिहासिक रूप से सामान्य समय में सीआरआर 4 प्रतिशत बहाल रखा जाता रहा है। यह राशि बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखनी पड़ती है और इस पर उन्हें ब्याज नहीं मिलता है। कोविड-19 महामारी के दौरान सीआरआर घटाकर 3 प्रतिशत किया गया था।

अब माना जा रहा है कि 3 प्रतिशत सीआरआर नया सामान्य स्तर हो सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सीआरआर घटाने की वजह बताते हुए कहा, 'इससे न सिर्फ नकदी में सुधार होगा, बल्कि इससे बैंकों को फंड की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी।'

मल्होत्रा ने नीतिगत फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'पिछले 12-13 साल के आंकड़ों से पता चलता है और कोई भी इसे देख सकता है कि सीआरआर ज्यादातर समय 4 प्रतिशत पर रहा है। कोविड के दौरान हमने इसे 1 प्रतिशत घटाया। अब इस रिजर्व को दरअसल नकदी प्रबंधन के लिए रखा जाता है। ऐसे में अब तक के अनुभव हमें बताते हैं कि



रिजर्व बैंक के फैसले से न सिर्फ नकदी में सुधार होगा, बल्कि बैंकों को फंड की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी

यह 4 प्रतिशत रखने की जरूरत नहीं है और शायद 3 प्रतिशत पर्याप्त है।'

उन्होंने कहा, 'हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा। अब ऐसा लग रहा है कि 3 प्रतिशत आरक्षित अनुपात नकदी प्रबंधन के लिए सहज है।' मल्होत्रा ने कहा कि सीआरआर में कटौती से मौद्रिक नीति का असर भी तेज होगा। उन्होंने जोर दिया कि रिजर्व बैंक नकदी और वित्तीय बाजार की स्थिति की निगरानी जारी रखेगा और जरूरत के मुताबिक सक्रिय रूप से भविष्य में कदम उठाएगा।

सीआरआर में कटौती के कारण बैंकों को मिलने वाली नकदी का उपयोग अब राजस्व आय परिसंपत्तियों में किया जा सकेगा, जिससे बैंकों को मार्जिन में सुधार करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर नीतिगत दर में 100 आधार अंक की कटौती से बैंकों के ब्याज से शुद्ध मुनाफे पर दबाव कम होगा। रिजर्व बैंक के

अनुमान के मुताबिक बैंकों का मार्जिन 7 आधार अंक सुधरेगा। उन्होंने कहा, 'नकदी मुहैया कराने के अलावा इसकी वजह से लागत भी घटेगी और हमारे अनुमान के मुताबिक उनका शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) कम से कम करीब 7 आधार अंक सुधरेगा। (हम नकदी मुहैया करा रहे हैं) इसलिए नीतिगत फैसले का बेहतर और तेजी से ट्रांसमिशन होगा।'

आईडीएफसी फ्रस्ट बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट गौरा सेनगुप्ता ने कहा, 'आकलन पूरी तरह से बदल गया है। कोविड के पहले सीआरआर कभी भी 4 प्रतिशत से नीचे नहीं आया। हाल के इतिहास में... संभवतः 1960 के दशक में ऐसा हुआ होगा। यही कारण है कि कोई सीआरआर में कटौती की उम्मीद नहीं कर रहा था। बिना संकट वाले दौर के पर दबाव कम होगा। रिजर्व बैंक के

देखा गया था। अब सीआरआर 3 प्रतिशत करने का मतलब यह है कि रिजर्व बैंक के विचार में बदलाव आया है कि सामान्य दिनों में कितना पर्याप्त है। अब यह गैर संकट के दौर का सामान्य स्तर लग रहा है।' उन्होंने कहा, 'इसका और भी कुछ मतलब है। रिजर्व बैंक नकदी बढ़ाने के लिए ओएमओ का विकल्प चुना। यह निर्णय खासकर बैंकों के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ से नकदी बढ़ाने की जरूरत बताता है। ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक बैंकों के लिए मार्जिन का प्रबंध करते हुए नकदी तक उनकी पहुंच आसान करने की कोशिश कर रहा है।' पिछली बार दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति की घोषणा में रिजर्व बैंक ने सीआरआर 50 आधार अंक घटाकर 4 प्रतिशत किया था।

सवाल जवाब

पहले की तुलना में समिति के फैसलों का तेज असर

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर जवाब दिए। उन्होंने कहा कि पिछले रुझानों को देखते तो मौद्रिक नीति का असर बहुत तेजी से हुआ है। मुद्रा बाजारों में जो हमने किया है उससे भी अधिक असर हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह आकलन मुश्किल होगा कि मौद्रिक नीति से ऋण की दरों और वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इसका असर कैसा रहेगा। संपादित अंश:

इस चक्र में आप दरों को कहां टिकता देख रहे हैं? हमने रुख को उदार से तटस्थ कर दिया है। साथ ही इसमें उल्लेख किया गया है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वास्तव में मौद्रिक नीति को लेकर अब बहुत सीमित गुंजाइश है। आप मौजूदा हालात के बारे में जानते हैं, वृद्धि दर करीब 6.5 प्रतिशत है। इस वर्ष के लिए हम महंगाई दर 3.7 प्रतिशत और अगले वर्ष 4 प्रतिशत से ऊपर या करीब 4.5 प्रतिशत रखने का अनुमान लगा रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए एमपीसी के लिए बहुत कम गुंजाइश बची है। हमने अब रुख तटस्थ कर दिया है। समिति का यह भी कहना है कि आने वाले उन आंकड़ों और आधारों पर खासकर अनिश्चितताओं को देखते हुए लगातार नजर रखी जाएगी। हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, यह मुख्य रूप से आंकड़ों पर निर्भर होगा।

रुख अब तटस्थ कर दिया गया है। क्या लंबे समय का विराम होगा?

यह अब आंकड़ों पर निर्भर करेगा। तटस्थ का यही मतलब है। मैंने इसे पहले एमपीसी के ब्योरे में साफ किया था कि तटस्थ का मतलब है कि यह किसी भी दिशा में जा सकता है। यह इस पर निर्भर होगा कि आंकड़े कैसे आते हैं। अगर वृद्धि कमजोर है, तो इसका मतलब है कि यह नीचे जाएगी। अगर वृद्धि अच्छी है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि रीपो रेट बढ़ सकती है। इसलिए यह इस बात पर निर्भर करेगा कि महंगाई और वृद्धि के आंकड़े कैसे आते हैं।

क्या रुख पर मतदान हुआ था?

रुख पर मतदान को लेकर हमने पहले ही उल्लेख किया है कि कानून में मतदान अनिवार्य नहीं है। इस पर चर्चा हुई। निश्चित रूप से हमें संकेत देने, अनुमान देने की जरूरत थी। यह अनुमान है, जो हमें बाजार के प्रतिभागियों को देना होता है। इसलिए इस पर चर्चा हुई और समिति के सभी 6 सदस्यों का विचार था कि हमें तटस्थ रुख रखना चाहिए। इसलिए कोई मतदान नहीं हुआ। समिति के सभी सदस्यों का विचार यह है कि आगे चलकर रुख बदलकर उदार से तटस्थ किया जाना चाहिए।

क्या नीति के अब तक हुए असर से संतुष्ट हैं?

पिछले रुझानों को देखते तो मौद्रिक नीति का असर बहुत तेजी से हुआ है। मुद्रा बाजारों में आप बड़ा असर देख सकते हैं। जो हमने किया है उससे भी अधिक असर हुआ है। खासकर कम अवधि के हिसाब से मुद्रा बाजारों में 50 आधार अंक की तुलना में भी अधिक असर दिख रहा है। ऋण पर भी शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। ज्यादातर बैंकों ने थोक और खुदरा दोनों जमा दरों में करीब 40 आधार अंक की कमी की है। औसतन करीब 27 आधार अंक कमी हुई



है। ऋण के हिसाब से देखें तो बचे हुए ऋण पर 17 आधार अंक कमी आई है। नए ऋण के हिसाब से देखें तो असर थोड़ा धीमा है।

हमारे आंकड़ों के मुताबिक यह करीब 6 आधार अंक है। इस तरह से यह सुस्त है, लेकिन इससे पहले के वक्त की तुलना में बहुत तेज है। आम तौर पर इसमें 6 से 9 महीने लगते हैं। पहली नीतिगत कटौती से केवल 4 महीने हुए हैं। इसलिए 25 आधार अंक की पहली नीतिगत कटौती के मुकाबले जमा में 27 आधार अंक और ऋण में 17 आधार अंक और नए ऋण के लिए 6 आधार अंक की कटौती हुई है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा ट्रांसमिशन है। लेकिन हमें इसे और तेजी से करने की जरूरत है, इसलिए इस बार हमने कुछ कार्रवाई पहले ही कर ली है।

रीपो रेट में कुल 100 आधार अंक की कटौती से आप वृद्धि में कितनी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं? क्या वित्त वर्ष 2026 के वृद्धि अनुमान में संशोधन होगा?

जाहिर है, इसका (वृद्धि पर) सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह आकलन करना बहुत मुश्किल होगा कि मौद्रिक नीति से ऋण की दरों और उसके बाद वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इसका असर कैसा रहेगा। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इसका असर दिखले में कम से कम 6 से 9 महीने लगते हैं। हम इसे तेज करना चाहते हैं, लेकिन इसका असर दूसरी छमाही में ही दिखेगा। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इस साल जब इतनी अनिश्चितता है, हम कुछ ठोस रूप से बताने की स्थिति में नहीं हैं कि जीडीपी के आंकड़ों पर इसका कितना असर होगा।

यह नकदी का वृद्धि पर वाकई कैसे असर डालती है? व्यवस्था में अधिक नकदी का क्या लाभ है?

यह अन्य कारकों पर भी निर्भर करेगा। मौद्रिक नीति पर्याप्त नहीं, लेकिन जरूरी है। हमें विश्वास है कि इससे ऋण वृद्धि बेहतर होगी। मैं कोई स्पष्ट आंकड़ा देने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन भरोसे के साथ यह कहा जा सकता है कि इससे ऋण प्रवाह बढ़ेगा। इसलिए नकदी महत्वपूर्ण है। रीपो रेट में कमी महत्वपूर्ण है। इसमें कितना वक्त लगेगा, यह कहना कठिन है।

नीतिगत दर में 50 आधार अंक की कटौती, सीआरआर में 100 आधार अंक की कटौती और रुख को बदलकर तटस्थ करने का फैसला अप्रत्याशित रूप से आश्चर्यजनक था।



नीतिगत दर में 50 आधार अंक की कटौती, सीआरआर में 100 आधार अंक की कटौती और रुख को बदलकर तटस्थ करने का फैसला अप्रत्याशित रूप से आश्चर्यजनक था।

सीएस शेट्टी
चेयरमैन, भारतीय स्टेट बैंक

मौद्रिक नीति समिति ने सुखद रूप से बाजारों को आश्चर्य-चकित कर दिया है। अतिरिक्त नकदी के साथ ब्याज दर कम होने से उधारी की लागत कम होगी और आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा।

पीडी सिंह
सीईओ, भारत-दक्षिण एशिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

रिजर्व बैंक द्वारा ढील दिए जाने के तरीकों को आगे बढ़ाने का फैसला भारत की वृद्धि की कहानी को और मजबूती से आगे बढ़ाता है। इन उपायों से नीति का तेज असर होगा और ऋण की लागत घटेगी



के बाला सुब्रमण्यन
सीईओ सिटी बैंक

परिपक्व बाजार का संकेत

धन वापसी के कारण शुद्ध एफडीआई में कमी आई

अभिजित लेले
मुंबई, 6 जून

वित्त वर्ष 2025 के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में तेज गिरावट धन वापस अपने देश भेजने की वजह से आई है। यह परिपक्व बाजार का संकेत है, जिसमें निवेशक आसानी से बाजार में कदम रख सकते और निकल सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा करते हुए यह बात कही।

इस महीने की शुरुआत में जारी रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध एफडीआई की आवक घटकर 0.4 अरब डॉलर रह गई है जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 10.1 अरब डॉलर थी। सकल

एफडीआई की आवक मजबूत बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह 14 प्रतिशत बढ़कर 8.1 अरब डॉलर हो गया है जो एक साल पहले 7.13 अरब डॉलर था।

मल्होत्रा ने कहा, 'यह बताना मुनासिब है कि (शुद्ध एफडीआई में) यह कमी धन वापस भेजने में इजाफा और शुद्ध रूप से विदेश में निवेशक आसानी से बाजार में कदम रख सकते और निकल सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा करते हुए यह बात कही।' 'इस महीने की शुरुआत में जारी रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध एफडीआई की आवक घटकर 0.4 अरब डॉलर रह गई है जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 10.1 अरब डॉलर थी। सकल



प्रवासी भारतीयों ने जमा किया ज्यादा धन

उन्होंने कहा कि बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) और प्रवासी भारतीयों की जमा में शुद्ध आवक पिछले के वित्त वर्ष की तुलना में अधिक रही है। भारत में ईसीबी से शुद्ध आवक वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 18.7 अरब डॉलर

हो गई है, जो एक साल पहले 3.6 अरब डॉलर थी। अप्रैल 2025 में शुद्ध ईसीबी बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गई जो पिछले वर्ष 0.5 अरब डॉलर थी। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रवासी जमा बढ़कर 16.2 अरब डॉलर हो गई है जो एक साल पहले 14.7 अरब डॉलर थी। उन्होंने कहा, 'कुल मिलाकर भारत का बाहरी क्षेत्र मजबूत बना हुआ है और प्रमुख बाहरी क्षेत्र के उतार-चढ़ाव वाले संकेतकों में सुधार जारी है। हमें भरोसा है कि हम अपनी बाहरी विदेशी वित्तपोषण की जरूरतें पूरी कर लेंगे।' वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश तेजी से गिरकर 1.7 अरब डॉलर रह गया है क्योंकि शेयर बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मुनाफावसूली की है।

बॉन्ड बाजार

3 साल की तुलना में सर्वाधिक उतार-चढ़ाव

अंजलि कुमारी
मुंबई, 6 जून

बॉन्ड बाजार में शुक्रवार को भारी उतार-चढ़ाव रहा। डीलरों ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक के फैसलों के बाद ऐसी अस्थिरता अगस्त 2022 के बाद से लगभग 3 वर्षों में पहली बार सबसे अधिक रही है। कई आश्चर्यजनक कदमों ने बाजार को चौंकाया।

समिति ने नीतिगत रीपो दर में 50 आधार अंक की कटौती का फैसला किया जबकि आम राय 25 आधार अंक कटौती की थी। रुख भी बदलकर तटस्थ कर दिया। यह एक

और आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था क्योंकि पिछली बैठक में रुख तटस्थ से बदलकर अनुकूल किया गया था। इसके अलावा सीआरआर जरूरतों को चरणबद्ध तरीके से 100 आधार अंक घटाने का फैसला किया गया।

शुक्रवार को कारोबार के दौरान बेंचमार्क गिल्ड 15 आधार अंक बढ़ा जो 5 अगस्त, 2022 के बाद सबसे ऊपर का स्तर है। तब एक दिन में गिल्ड 21 आधार अंक बढ़ा था। तटस्थ रुख में बदलाव के बाद 10 साल के बॉन्ड ने बाद में कुछ बढ़त गंवा दी। बेंचमार्क बॉन्ड ने कारोबार के अंत तक सभी बढ़त



कई मोर्चों पर फैसलों से हक्का-बक्का रह गया बॉन्ड बाजार

खत्म कर दगी और वह 6.29 प्रतिशत पर बंद हुआ जो पिछले बंद 6.25 प्रतिशत के मुकाबले 4 आधार अंक अधिक है। पीएनबी गिल्ड्स में वरिष्ठ

कार्यकारी वाइस प्रेसीडेंट विजय शर्मा ने कहा, 'रीपो दर में अप्रत्याशित कटौती से शुरुआत में बॉन्ड में तेजी आई। लेकिन नीतिगत रुख में बदलाव की बात से बाजार

भौचक रह गया। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के ताज्जुबों के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव रहा। सीआरआर में कटौती से फिर राहत मिली, लेकिन सारे नीतिगत कदम तभी घोषित कर दिए गए और भविष्य में आरबीआई की ओर से कदम उठाने का कोई संकेत नहीं मिला तो तो बाजार ने पोजीशन बेचनी शुरू कर दी।'

कम अवधि वाले खासकर 5 साल तक के सेगमेंट में एसएलआर और गैर एसएलआर (कॉर्पोरेट बॉन्ड) श्रेणी दोनों में ही बेहतर प्रदर्शन रहा है। फंडिंग लागत में कमी के कारण ऐसा हुआ।

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated May 09, 2025 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with BSE Limited ("BSE")

BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED)
Corporate Identification Number: L74140MP1984PLC002592
Registered Office: 228 Part-B, The Zodiac Mall, Bicholi Mardana, Indore (MP) - 452001
Contact Details: 7383380911; Email-ID: info@indraindustries.in; Website: www.indraindustries.in
Contact Person: Ms. Sweetsy Purohit, Company Secretary & Compliance Officer:

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE ISSUE

RIGHTS ISSUE OF UP TO 4,85,78,025*FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (RUPEE TEN ONLY) (EQUITY SHARES) EACH AT A PRICE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) PER EQUITY SHARE ("RIGHT SHARES") FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹48,57,80,250/- (RUPEES FOURTY EIGHT CRORE FIFTY SEVEN LAKHS EIGHTY THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED) (COMPANY OR 'ISSUER') IN THE RATIO OF 15 (FIFTEEN) EQUITY SHARES FOR EVERY 2 (TWO) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE. THURSDAY, MAY 09, 2025 ('ISSUE'). THE ISSUE PRICE IS 1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 130 OF THIS LETTER OF OFFER.

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") - ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MAY 9, 2025

This notice should be read in conjunction with the LOF filed by the Company with the Stock Exchange and the ALOF and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please note the following:

This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday 23rd May 2025 and was scheduled to close on Wednesday, Friday 06th June 2025, has now been extended to Monday, June 09, 2025, by the Rights Issue Committee in its meeting held on June 06 2025 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Monday, 09 June, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, 09 June, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE	
ISSUE OPENING DATE	ISSUE CLOSING DATE
FRIDAY 23RD MAY 2025	MONDAY 09TH MAY 2025

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).
** Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms on or before the Issue Closing Date.
#Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.
This addendum shall be available on the respective websites of our Company at info@indraindustries.in the Registrar to the Issue at www.purvashare.com, and the Stock Exchanges at www.bseindia.com.
Accordingly, there is no change in the LOF and ALOF dated May 09, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing date. Change in Issue closing date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date.
INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.
All Capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For Bluegod Entertainment Limited
(Formerly Known As Indra Industries Limited)
Sd/-
Nitinashok kumar Khanna
Managing Director

Date: May 09, 2025
Place: Indore

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the BSE Limited The Draft Letter of Offer is available on the website of the Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com. Our Company at info@indraindustries.in and the Registrar to the Issue at www.purvashare.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Draft Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 31 of the Draft Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

3 प्रतिशत सीआरआर नया सामान्य स्तर

प्रभावी नकदी प्रबंधन के लिए 3 प्रतिशत सीआरआर पर्याप्त

अंजलि कुमारी
मुंबई, 6 जून

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) जरूरतों को 100 आधार अंक घटाकर शुद्ध मांग और सावधि देनदारी (एनडीटीएल) का 3 प्रतिशत करने का फैसला किया है। यह फैसला चरणबद्ध तरीके से 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाले पखवाड़ों से प्रभावी होगा।



रिजर्व बैंक के फैसले से न सिर्फ नकदी में सुधार होगा, बल्कि बैंकों को फंड की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी

यह 4 प्रतिशत रखने की जरूरत नहीं है और शायद 3 प्रतिशत पर्याप्त है। उन्होंने कहा, 'हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा। अब ऐसा लग रहा है कि 3 प्रतिशत आरक्षित अनुपात नकदी प्रबंधन के लिए सहज है।' मल्होत्रा ने कहा कि सीआरआर में कटौती से मौद्रिक नीति का असर भी तेज होगा। उन्होंने जोर दिया कि रिजर्व बैंक नकदी और वित्तीय बाजार की स्थिति की निगरानी जारी रखेगा और जरूरत के मुताबिक सक्रिय रूप से भविष्य में कदम उठाएगा।

सीआरआर में कटौती के कारण बैंकों को मिलने वाली नकदी का उपयोग अब राजस्व आय परिसंपत्तियों में किया जा सकेगा, जिससे बैंकों को मार्जिन में सुधार करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर नीतिगत दर में 100 आधार अंक की कटौती से बैंकों के ब्याज से शुद्ध मुनाफे पर दबाव कम होगा। रिजर्व बैंक के

अनुमान के मुताबिक बैंकों का मार्जिन 7 आधार अंक सुधरेगा। उन्होंने कहा, 'नकदी मुहैया कराने के अलावा इसकी वजह से लागत भी घटेगी और हमारे अनुमान के मुताबिक उनका शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) कम से कम करीब 7 आधार अंक सुधरेगा। (हम नकदी मुहैया करा रहे हैं) इसलिए नीतिगत फैसले का बेहतर और तेजी से ट्रांसमिशन होगा।'

आईडीएफसी फ्रस्ट बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट गौरा सेनगुप्ता ने कहा, 'आकलन पूरी तरह से बदल गया है। कोविड के पहले सीआरआर कभी भी 4 प्रतिशत से नीचे नहीं आया। हाल के इतिहास में... संभवतः 1960 के दशक में ऐसा हुआ होगा। यही कारण है कि कोई सीआरआर में कटौती की उम्मीद नहीं कर रहा था। बिना संकट वाले दौर के पर दबाव कम होगा। रिजर्व बैंक के

देखा गया था। अब सीआरआर 3 प्रतिशत करने का मतलब यह है कि रिजर्व बैंक के विचार में बदलाव आया है कि सामान्य दिनों में कितना पर्याप्त है। अब यह गैर संकट के दौर का सामान्य स्तर लग रहा है।' उन्होंने कहा, 'इसका और भी कुछ मतलब है। रिजर्व बैंक नकदी बढ़ाने के लिए ओएमओ का विकल्प चुना। यह निर्णय खासकर बैंकों के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ से नकदी बढ़ाने की जरूरत बताता है।' ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक बैंकों के लिए मार्जिन का प्रबंध करते हुए नकदी तक उनकी पहुंच आसान करने की कोशिश कर रहा है।' पिछली बार दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति की घोषणा में रिजर्व बैंक ने सीआरआर 50 आधार अंक घटाकर 4 प्रतिशत किया था।

सवाल जवाब

पहले की तुलना में समिति के फैसलों का तेज असर

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर जवाब दिए। उन्होंने कहा कि पिछले रुझानों को देखें तो मौद्रिक नीति का असर बहुत तेजी से हुआ है। मुद्रा बाजारों में जो हमने किया है उससे भी अधिक असर हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह आकलन मुश्किल होगा कि मौद्रिक नीति से ऋण की दरों और वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इसका असर कैसा रहेगा। संपादित अंश:



इस चक्र में आप दरों को कहां टिकता देख रहे हैं? हमने रुख को उदार से तटस्थ कर दिया है। साथ ही इसमें उल्लेख किया गया है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वास्तव में मौद्रिक नीति को लेकर अब बहुत सीमित गुंजाइश है। आप मौजूदा हालात के बारे में जानते हैं, वृद्धि दर करीब 6.5 प्रतिशत है। इस वर्ष के लिए हम महंगाई दर 3.7 प्रतिशत और अगले वर्ष 4 प्रतिशत से ऊपर या करीब 4.5 प्रतिशत रखने का अनुमान लगा रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए एमपीसी के लिए बहुत कम गुंजाइश बची है। हमने अब रुख तटस्थ कर दिया है। समिति का यह भी कहना है कि आने वाले उन आंकड़ों और आधारों पर खासकर अनिश्चितताओं को देखते हुए लगातार नजर रखी जाएगी। हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, यह मुख्य रूप से आंकड़ों पर निर्भर होगा।

रुख अब तटस्थ कर दिया गया है। क्या लंबे समय का विराम होगा? यह अब आंकड़ों पर निर्भर करेगा। तटस्थ का यही मतलब है। मैंने इसे पहले एमपीसी के ब्योरे में साफ किया था कि तटस्थ का मतलब है कि यह किसी भी दिशा में जा सकता है। यह इस पर निर्भर होगा कि आंकड़े कैसे आते हैं। अगर वृद्धि कमजोर है, तो इसका मतलब है कि यह नीचे जाएगी। अगर वृद्धि अच्छी है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि रीपो रेट बढ़ सकती है। इसलिए यह इस बात पर निर्भर करेगा कि महंगाई और वृद्धि के आंकड़े कैसे आते हैं।

क्या रुख पर मतदान हुआ था? रुख पर मतदान को लेकर हमने पहले ही उल्लेख किया है कि कानून में मतदान अनिवार्य नहीं है। इस पर चर्चा हुई। निश्चित रूप से हमें संकेत देने, अनुमान देने की जरूरत थी। यह अनुमान है, जो हमें बाजार के प्रतिभागियों को देना होता है। इसलिए इस पर चर्चा हुई और समिति के सभी 6 सदस्यों का विचार था कि हमें तटस्थ रुख रखना चाहिए। इसलिए कोई मतदान नहीं हुआ। समिति के सभी सदस्यों का विचार यह है कि आगे चलकर रुख बदलकर उदार से तटस्थ किया जाना चाहिए।

क्या नीति के अब तक हुए असर से संतुष्ट हैं? पिछले रुझानों को देखें तो मौद्रिक नीति का असर बहुत तेजी से हुआ है। मुद्रा बाजारों में आप बड़ा असर देख सकते हैं। जो हमने किया है उससे भी अधिक असर हुआ है। खासकर कम अवधि के हिसाब से मुद्रा बाजारों में 50 आधार अंक की तुलना में भी अधिक असर दिख रहा है। ऋण पर भी शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। ज्यादातर बैंकों ने थोक और खुदरा दोनों जमा दरों में करीब 40 आधार अंक की कमी की है। औसतन करीब 27 आधार अंक कमी हुई

है। ऋण के हिसाब से देखें तो बचे हुए ऋण पर 17 आधार अंक कमी आई है। नए ऋण के हिसाब से देखें तो असर थोड़ा धीमा है। हमारे आंकड़ों के मुताबिक यह करीब 6 आधार अंक है। इस तरह से यह सुस्त है, लेकिन इससे पहले के वक्त की तुलना में बहुत तेज है। आम तौर पर इसमें 6 से 9 महीने लगते हैं। पहली नीतिगत कटौती से केवल 4 महीने हुए हैं। इसलिए 25 आधार अंक की पहली नीतिगत कटौती के मुकाबले जमा में 27 आधार अंक और ऋण में 17 आधार अंक और नए ऋण के लिए 6 आधार अंक की कटौती हुई है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा ट्रांसमिशन है। लेकिन हमें इसे और तेजी से करने की जरूरत है, इसलिए इस बार हमने कुछ कार्रवाई पहले ही कर ली है।

रीपो रेट में कुल 100 आधार अंक की कटौती से आप वृद्धि में कितनी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं? क्या वित्त वर्ष 2026 के वृद्धि अनुमान में संशोधन होगा?

जाहिर है, इसका (वृद्धि पर) सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह आकलन करना बहुत मुश्किल होगा कि मौद्रिक नीति से ऋण की दरों और उसके बाद वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इसका असर कैसा रहेगा। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इसका असर दिखले में कम से कम 6 से 9 महीने लगते हैं। हम इसे तेज करना चाहते हैं, लेकिन इसका असर दूसरी छमाही में ही दिखेगा। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इस साल जब इतनी अनिश्चितता है, हम कुछ ठोस रूप से बताने की स्थिति में नहीं हैं कि जीडीपी के आंकड़ों पर इसका कितना असर होगा।

यह नकदी का वृद्धि पर वाकई कैसे असर डालती है? व्यवस्था में अधिक नकदी का क्या लाभ है? यह अन्य कारकों पर भी निर्भर करेगा। मौद्रिक नीति पर्याप्त नहीं, लेकिन जरूरी है। हमें विश्वास है कि इससे ऋण वृद्धि बेहतर होगी। मैं कोई स्पष्ट आंकड़ा देने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन भरोसे के साथ यह कहा जा सकता है कि इससे ऋण प्रवाह बढ़ेगा। इसलिए नकदी महत्वपूर्ण है। रीपो रेट में कमी महत्वपूर्ण है। इसमें कितना वक्त लगेगा, यह कहना कठिन है।

नीतिगत दर में 50 आधार अंक की कटौती, सीआरआर में 100 आधार अंक की कटौती और रुख को बदलकर तटस्थ करने का फैसला अप्रत्याशित रूप से आश्चर्यजनक था।



मौद्रिक नीति समिति ने सुखद रूप से बाजारों को आश्चर्य-चकित कर दिया है। अतिरिक्त नकदी के साथ ब्याज दर कम होने से उधारी की लागत कम होगी और आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा।

पीडी सिंह
सीईओ, भारत-दक्षिण एशिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

रिजर्व बैंक द्वारा ढील दिए जाने के तरीकों को आगे बढ़ाने का फैसला भारत की वृद्धि की कहानी को और मजबूती से आगे बढ़ाता है। इन उपायों से नीति का तेज असर होगा और ऋण की लागत घटेगी



के बाला सुब्रमण्यन
सीईओ सिटी बैंक

परिपक्व बाजार का संकेत

धन वापसी के कारण शुद्ध एफडीआई में कमी आई

अभिजित लेले
मुंबई, 6 जून

वित्त वर्ष 2025 के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में तेज गिरावट धन वापस अपने देश भेजने की वजह से आई है। यह परिपक्व बाजार का संकेत है, जिसमें निवेशक आसानी से बाजार में कदम रख सकते और निकल सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा करते हुए यह बात कही।

एफडीआई की आवक मजबूत बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह 14 प्रतिशत बढ़कर 81 अरब डॉलर हो गया है जो एक साल पहले 71.3 अरब डॉलर था।

मल्होत्रा ने कहा, 'यह बताना मुनासिब है कि (शुद्ध एफडीआई में) यह कमी धन वापस भेजने में इजाफा और शुद्ध रूप से विदेश में निवेशक आसानी से बाजार में कदम रख सकते और निकल सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा करते हुए यह बात कही। इस महीने की शुरुआत में जारी रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध एफडीआई की आवक घटकर 0.4 अरब डॉलर रह गई है जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 10.1 अरब डॉलर थी। सकल



प्रवासी भारतीयों ने जमा किया ज्यादा धन

उन्होंने कहा कि बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) और प्रवासी भारतीयों की जमा में शुद्ध आवक पिछले के वित्त वर्ष की तुलना में अधिक रही है। भारत में ईसीबी से शुद्ध आवक वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 18.7 अरब डॉलर

हो गई है, जो एक साल पहले 3.6 अरब डॉलर थी। अप्रैल 2025 में शुद्ध ईसीबी बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गई जो पिछले वर्ष 0.5 अरब डॉलर थी। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रवासी जमा बढ़कर 16.2 अरब डॉलर हो गई है जो एक साल पहले 14.7 अरब डॉलर थी। उन्होंने कहा, 'कुल मिलाकर भारत का बाहरी क्षेत्र मजबूत बना हुआ है और प्रमुख बाहरी क्षेत्र के उतार-चढ़ाव वाले संकेतकों में सुधार जारी है। हमें भरोसा है कि हम अपनी बाहरी विदेशी वित्तपोषण की जरूरतें पूरी कर लेंगे।' वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश तेजी से गिरकर 1.7 अरब डॉलर रह गया है क्योंकि शेयर बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मुनाफावसूली की है।

बॉन्ड बाजार

3 साल की तुलना में सर्वाधिक उतार-चढ़ाव

अंजलि कुमारी
मुंबई, 6 जून

बॉन्ड बाजार में शुक्रवार को भारी उतार-चढ़ाव रहा। डीलरों ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक के फैसलों के बाद ऐसी अस्थिरता अगस्त 2022 के बाद से लगभग 3 वर्षों में पहली बार सबसे अधिक रही है। कई आश्चर्यजनक कदमों ने बाजार को चौंकाया।

और आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था क्योंकि पिछली बैठक में रुख तटस्थ से बदलकर अनुकूल किया गया था। इसके अलावा सीआरआर जरूरतों को चरणबद्ध तरीके से 100 आधार अंक घटाने का फैसला किया गया।

शुक्रवार को कारोबार के दौरान बेंचमार्क गिल्ड 15 आधार अंक बढ़ा जो 5 अगस्त, 2022 के बाद सबसे ऊपर का स्तर है। तब एक दिन में गिल्ड 21 आधार अंक बढ़ा था। तटस्थ रुख में बदलाव के बाद 10 साल के बॉन्ड ने बाद में कुछ बढ़त गंवा दी। बेंचमार्क बॉन्ड ने कारोबार के अंत तक सभी बढ़त



कई मोर्चों पर फैसलों से हक्का-बक्का रह गया बॉन्ड बाजार

खत्म कर दगी और वह 6.29 प्रतिशत पर बंद हुआ जो पिछले बंद 6.25 प्रतिशत के मुकाबले 4 आधार अंक अधिक है।

पीएनबी गिल्ड्स में वरिष्ठ कार्यकारी वाइस प्रेसीडेंट विजय शर्मा ने कहा, 'रीपो दर में अप्रत्याशित कटौती से शुरुआत में बॉन्ड में तेजी आई। लेकिन नीतिगत रुख में बदलाव की बात से बाजार

भौंक रह गया। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के ताज्जुबों के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव रहा। सीआरआर में कटौती से फिर राहत मिली, लेकिन सारे नीतिगत कदम तभी घोषित कर दिए गए और भविष्य में आरबीआई की ओर से कदम उठाने का कोई संकेत नहीं मिला तो तो बाजार ने पोजीशन बेचनी शुरू कर दी।'

कम अवधि वाले खासकर 5 साल तक के सेगमेंट में एसएलआर और गैर एसएलआर (कॉर्पोरेट बॉन्ड) श्रेणी दोनों में ही बेहतर प्रदर्शन रहा है। फंडिंग लागत में कमी के कारण ऐसा हुआ।

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated May 09, 2025 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with BSE Limited ("BSE")

BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED)
Corporate Identification Number: L74140MP1984PLC002592
Registered Office: 228 Part-B, The Zodiac Mall, Bicholi Mardana, Indore (MP) - 452001
Contact Details: 7383380911; Email-ID: info@indraindustries.in; Website: www.indraindustries.in
Contact Person: Ms. Sweetsy Purohit, Company Secretary & Compliance Officer:

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE ISSUE

RIGHTS ISSUE OF UP TO 4,85,78,025*FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (RUPEE TEN ONLY) (EQUITY SHARES) EACH AT A PRICE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) PER EQUITY SHARE ("RIGHT SHARES") FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹ 48,57,80,250/- (RUPEES FOURTY EIGHT CRORE FIFTY SEVEN LAKHS EIGHTY THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED) (COMPANY OR 'ISSUER') IN THE RATIO OF 15 (FIFTEEN) EQUITY SHARES FOR EVERY 2 (TWO) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE. THURSDAY, MAY 09, 2025 ('ISSUE'). THE ISSUE PRICE IS 1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 130 OF THIS LETTER OF OFFER.

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") - ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MAY 9, 2025

This notice should be read in conjunction with the LOF filed by the Company with the Stock Exchange and the ALOF and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please note the following:

This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday 23rd May 2025 and was scheduled to close on Wednesday, Friday 06th June 2025, has now been extended to Monday, June 09, 2025, by the Rights Issue Committee in its meeting held on June 06 2025 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Monday, 09 June, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, 09 June, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE	
ISSUE OPENING DATE	ISSUE CLOSING DATE
FRIDAY 23RD MAY 2025	MONDAY 09TH MAY 2025

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).
** Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms on or before the Issue Closing Date.
#Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.
This addendum shall be available on the respective websites of our Company at info@indraindustries.in the Registrar to the Issue at www.purvashare.com, and the Stock Exchanges at www.bseindia.com.
Accordingly, there is no change in the LOF and ALOF dated May 09, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing date. Change in Issue closing date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date.
INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.
All Capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For Bluegod Entertainment Limited (Formerly Known As Indra Industries Limited)
Sd/-
Nitinashok kumar Khanna
Managing Director

Date: May 09, 2025
Place: Indore

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the BSE Limited The Draft Letter of Offer is available on the website of Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com. Our Company at info@indraindustries.in and the Registrar to the Issue at www.purvashare.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Draft Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 31 of the Draft Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

3 प्रतिशत सीआरआर नया सामान्य स्तर

प्रभावी नकदी प्रबंधन के लिए 3 प्रतिशत सीआरआर पर्याप्त

अंजलि कुमारी
मुंबई, 6 जून

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) जरूरतों को 100 आधार अंक घटाकर शुद्ध मांग और सावधि देनदारी (एनडीटीएल) का 3 प्रतिशत करने का फैसला किया है। यह फैसला चरणबद्ध तरीके से 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाले पखवाड़ों से प्रभावी होगा।

सीआरआर में कटौती से दिसंबर 2025 तक बैंकिंग व्यवस्था में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये की प्राथमिक नकदी आएगी। ऐतिहासिक रूप से सामान्य समय में सीआरआर 4 प्रतिशत बहाल रखा जाता रहा है। यह राशि बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखनी पड़ती है और इस पर उन्हें ब्याज नहीं मिलता है। कोविड-19 महामारी के दौरान सीआरआर घटाकर 3 प्रतिशत किया गया था।

अब माना जा रहा है कि 3 प्रतिशत सीआरआर नया सामान्य स्तर हो सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सीआरआर घटाने की वजह बताते हुए कहा, 'इससे न सिर्फ नकदी में सुधार होगा, बल्कि इससे बैंकों को फंड की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी।'

मल्होत्रा ने नीतिगत फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'पिछले 12-13 साल के आंकड़ों से पता चलता है और कोई भी इसे देख सकता है कि सीआरआर ज्यादातर समय 4 प्रतिशत पर रहा है। कोविड के दौरान हमने इसे 1 प्रतिशत घटाया। अब इस रिजर्व को दरअसल नकदी प्रबंधन के लिए रखा जाता है। ऐसे में अब तक के अनुभव हमें बताते हैं कि



रिजर्व बैंक के फैसले से न सिर्फ नकदी में सुधार होगा, बल्कि बैंकों को फंड की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी

यह 4 प्रतिशत रखने की जरूरत नहीं है और शायद 3 प्रतिशत पर्याप्त है।

उन्होंने कहा, 'हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा। अब ऐसा लग रहा है कि 3 प्रतिशत आरक्षित अनुपात नकदी प्रबंधन के लिए सहज है।' मल्होत्रा ने कहा कि सीआरआर में कटौती से मौद्रिक नीति का असर भी तेज होगा। उन्होंने जोर दिया कि रिजर्व बैंक नकदी और वित्तीय बाजार की स्थिति की निगरानी जारी रखेगा और जरूरत के मुताबिक सक्रिय रूप से भविष्य में कदम उठाएगा।

सीआरआर में कटौती के कारण बैंकों को मिलने वाली नकदी का उपयोग अब राजस्व आय परिसंपत्तियों में किया जा सकेगा, जिससे बैंकों को मार्जिन में सुधार करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर नीतिगत दर में 100 आधार अंक की कटौती से बैंकों के ब्याज से शुद्ध मुनाफे पर दबाव कम होगा। रिजर्व बैंक के

अनुमान के मुताबिक बैंकों का मार्जिन 7 आधार अंक सुधरेगा। उन्होंने कहा, 'नकदी मुहैया कराने के अलावा इसकी वजह से लागत भी घटेगी और हमारे अनुमान के मुताबिक उनका शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) कम से कम करीब 7 आधार अंक सुधरेगा। (हम नकदी मुहैया करा रहे हैं) इसलिए नीतिगत फैसले का बेहतर और तेजी से ट्रांसमिशन होगा।'

आईडीएफसी फ्रस्ट बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट गौरा सेनगुप्ता ने कहा, 'आकलन पूरी तरह से बदल गया है। कोविड के पहले सीआरआर कभी भी 4 प्रतिशत से नीचे नहीं आया। हाल के इतिहास में... संभवतः 1960 के दशक में ऐसा हुआ होगा। यही कारण है कि कोई सीआरआर में कटौती की उम्मीद नहीं कर रहा था। बिना संकट वाले दौर के पर दबाव कम होगा। रिजर्व बैंक के

देखा गया था। अब सीआरआर 3 प्रतिशत करने का मतलब यह है कि रिजर्व बैंक के विचार में बदलाव आया है कि सामान्य दिनों में कितना पर्याप्त है। अब यह गैर संकट के दौर का सामान्य स्तर लग रहा है।' उन्होंने कहा, 'इसका और भी कुछ मतलब है। रिजर्व बैंक नकदी बढ़ाने के लिए ओएमओ का विकल्प चुना। यह निर्णय खासकर बैंकों के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ से नकदी बढ़ाने की जरूरत बताता है। ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक बैंकों के लिए मार्जिन का प्रबंध करते हुए नकदी तक उनकी पहुंच आसान करने की कोशिश कर रहा है।' पिछली बार दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति की घोषणा में रिजर्व बैंक ने सीआरआर 50 आधार अंक घटाकर 4 प्रतिशत किया था।

सवाल जवाब

पहले की तुलना में समिति के फैसलों का तेज असर

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर जवाब दिए। उन्होंने कहा कि पिछले रुझानों को देखते तो मौद्रिक नीति का असर बहुत तेजी से हुआ है। मुद्रा बाजारों में जो हमने किया है उससे भी अधिक असर हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह आकलन मुश्किल होगा कि मौद्रिक नीति से ऋण की दरों और वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इसका असर कैसा रहेगा। संपादित अंश:

इस चक्र में आप दरों को कहां टिकता देख रहे हैं? हमने रुख को उदार से तटस्थ कर दिया है। साथ ही इसमें उल्लेख किया गया है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वास्तव में मौद्रिक नीति को लेकर अब बहुत सीमित गुंजाइश है। आप मौजूदा हालात के बारे में जानते हैं, वृद्धि दर करीब 6.5 प्रतिशत है। इस वर्ष के लिए हम महंगाई दर 3.7 प्रतिशत और अगले वर्ष 4 प्रतिशत से ऊपर या करीब 4.5 प्रतिशत रखने का अनुमान लगा रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए एमपीसी के लिए बहुत कम गुंजाइश बची है। हमने अब रुख तटस्थ कर दिया है। समिति का यह भी कहना है कि आने वाले उन आंकड़ों और आधारों पर खासकर अनिश्चितताओं को देखते हुए लगातार नजर रखी जाएगी। हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, यह मुख्य रूप से आंकड़ों पर निर्भर होगा।

रुख अब तटस्थ कर दिया गया है। क्या लंबे समय का विराम होगा?

यह अब आंकड़ों पर निर्भर करेगा। तटस्थ का यही मतलब है। मैंने इसे पहले एमपीसी के ब्योरे में साफ किया था कि तटस्थ का मतलब है कि यह किसी भी दिशा में जा सकता है। यह इस पर निर्भर होगा कि आंकड़े कैसे आते हैं। अगर वृद्धि कमजोर है, तो इसका मतलब है कि यह नीचे जाएगी। अगर वृद्धि अच्छी है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि रीपो रेट बढ़ सकती है। इसलिए यह इस बात पर निर्भर करेगा कि महंगाई और वृद्धि के आंकड़े कैसे आते हैं।

क्या रुख पर मतदान हुआ था?

रुख पर मतदान को लेकर हमने पहले ही उल्लेख किया है कि कानून में मतदान अनिवार्य नहीं है। इस पर चर्चा हुई। निश्चित रूप से हमें संकेत देने, अनुमान देने की जरूरत थी। यह अनुमान है, जो हमें बाजार के प्रतिभागियों को देना होता है। इसलिए इस पर चर्चा हुई और समिति के सभी 6 सदस्यों का विचार था कि हमें तटस्थ रुख रखना चाहिए। इसलिए कोई मतदान नहीं हुआ। समिति के सभी सदस्यों का विचार यह है कि आगे चलकर रुख बदलकर उदार से तटस्थ किया जाना चाहिए।

क्या नीति के अब तक हुए असर से संतुष्ट हैं?

पिछले रुझानों को देखते तो मौद्रिक नीति का असर बहुत तेजी से हुआ है। मुद्रा बाजारों में आप बड़ा असर देख सकते हैं। जो हमने किया है उससे भी अधिक असर हुआ है। खासकर कम अवधि के हिसाब से मुद्रा बाजारों में 50 आधार अंक की तुलना में भी अधिक असर दिख रहा है। ऋण पर भी शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। ज्यादातर बैंकों ने थोक और खुदरा दोनों जमा दरों में करीब 40 आधार अंक की कमी की है। औसतन करीब 27 आधार अंक कमी हुई



है। ऋण के हिसाब से देखें तो बचे हुए ऋण पर 17 आधार अंक कमी आई है। नए ऋण के हिसाब से देखें तो असर थोड़ा धीमा है।

हमारे आंकड़ों के मुताबिक यह करीब 6 आधार अंक है। इस तरह से यह सुस्त है, लेकिन इससे पहले के वक्त की तुलना में बहुत तेज है। आम तौर पर इसमें 6 से 9 महीने लगते हैं। पहली नीतिगत कटौती से केवल 4 महीने हुए हैं। इसलिए 25 आधार अंक की पहली नीतिगत कटौती के मुकाबले जमा में 27 आधार अंक और ऋण में 17 आधार अंक और नए ऋण के लिए 6 आधार अंक की कटौती हुई है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा ट्रांसमिशन है। लेकिन हमें इसे और तेजी से करने की जरूरत है, इसलिए इस बार हमने कुछ कार्रवाई पहले ही कर ली है।

रीपो रेट में कुल 100 आधार अंक की कटौती से आप वृद्धि में कितनी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं? क्या वित्त वर्ष 2026 के वृद्धि अनुमान में संशोधन होगा?

जाहिर है, इसका (वृद्धि पर) सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह आकलन करना बहुत मुश्किल होगा कि मौद्रिक नीति से ऋण की दरों और उसके बाद वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इसका असर कैसा रहेगा। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इसका असर दिखले में कम से कम 6 से 9 महीने लगते हैं। हम इसे तेज करना चाहते हैं, लेकिन इसका असर दूसरी छमाही में ही दिखेगा। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इस साल जब इतनी अनिश्चितता है, हम कुछ ठोस रूप से बताने की स्थिति में नहीं हैं कि जीडीपी के आंकड़ों पर इसका कितना असर होगा।

यह नकदी का वृद्धि पर वाकई कैसे असर डालती है? व्यवस्था में अधिक नकदी का क्या लाभ है?

यह अन्य कारकों पर भी निर्भर करेगा। मौद्रिक नीति पर्याप्त नहीं, लेकिन जरूरी है। हमें विश्वास है कि इससे ऋण वृद्धि बेहतर होगी। मैं कोई स्पष्ट आंकड़ा देने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन भरोसे के साथ यह कहा जा सकता है कि इससे ऋण प्रवाह बढ़ेगा। इसलिए नकदी महत्वपूर्ण है। रीपो रेट में कमी महत्वपूर्ण है। इसमें कितना वक्त लगेगा, यह कहना कठिन है।



नीतिगत दर में 50 आधार अंक की कटौती, सीआरआर में 100 आधार अंक की कटौती और रुख को बदलकर तटस्थ करने का फैसला अप्रत्याशित रूप से आश्चर्यजनक था।



मौद्रिक नीति समिति ने सुखद रूप से बाजारों को आश्चर्य-चकित कर दिया है। अतिरिक्त नकदी के साथ ब्याज दर कम होने से उधारी की लागत कम होगी और आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा।



पीडी सिंह
सीईओ, भारत-दक्षिण एशिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

रिजर्व बैंक द्वारा ढील दिए जाने के तरीकों को आगे बढ़ाने का फैसला भारत की वृद्धि की कहानी को और मजबूती से आगे बढ़ाता है। इन उपायों से नीति का तेज असर होगा और ऋण की लागत घटेगी



के बाला सुब्रमण्यम
सीईओ सिटी बैंक

परिपक्व बाजार का संकेत

धन वापसी के कारण शुद्ध एफडीआई में कमी आई

अभिजित लेले
मुंबई, 6 जून

वित्त वर्ष 2025 के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में तेज गिरावट धन वापस अपने देश भेजने की वजह से आई है। यह परिपक्व बाजार का संकेत है, जिसमें निवेशक आसानी से बाजार में कदम रख सकते और निकल सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा करते हुए यह बात कही।

इस महीने की शुरुआत में जारी रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध एफडीआई की आवक घटकर 0.4 अरब डॉलर रह गई है जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 10.1 अरब डॉलर थी। सकल

एफडीआई की आवक मजबूत बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह 14 प्रतिशत बढ़कर 8.1 अरब डॉलर हो गया है जो एक साल पहले 7.13 अरब डॉलर था।

मल्होत्रा ने कहा, 'यह बताना मुनासिब है कि (शुद्ध एफडीआई में) यह कमी धन वापस भेजने में इजाफा और शुद्ध रूप से विदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण है, जबकि सकल एफडीआई वास्तव में 14 प्रतिशत बढ़ा है। अपने देश में धन वापस ले जाने में वृद्धि एक परिपक्व बाजार का संकेत है जहां विदेशी निवेशक आसानी से बाजार में प्रवेश कर सकते और निकल सकते हैं, जबकि उच्च सकल एफडीआई इंगित करता है कि भारत लगातार आकर्षक निवेश गंतव्य बना हुआ है।'



प्रवासी भारतीयों ने जमा किया ज्यादा धन

उन्होंने कहा कि बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) और प्रवासी भारतीयों की जमा में शुद्ध आवक पिछले के वित्त वर्ष की तुलना में अधिक रही है। भारत में ईसीबी से शुद्ध आवक वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 18.7 अरब डॉलर

हो गई है, जो एक साल पहले 3.6 अरब डॉलर थी। अप्रैल 2025 में शुद्ध ईसीबी बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गई जो पिछले वर्ष 0.5 अरब डॉलर थी। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रवासी जमा बढ़कर 16.2 अरब डॉलर हो गई है जो एक साल पहले 14.7 अरब डॉलर थी। उन्होंने कहा, 'कुल मिलाकर भारत का बाहरी क्षेत्र मजबूत बना हुआ है और प्रमुख बाहरी क्षेत्र के उतार-चढ़ाव वाले संकेतकों में सुधार जारी है। हमें भरोसा है कि हम अपनी बाहरी विदेशी वित्तपोषण की जरूरतें पूरी कर लेंगे।' वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश तेजी से गिरकर 1.7 अरब डॉलर रह गया है क्योंकि शेयर बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मुनाफावसूली की है।

बॉन्ड बाजार

3 साल की तुलना में सर्वाधिक उतार-चढ़ाव

अंजलि कुमारी
मुंबई, 6 जून

बॉन्ड बाजार में शुक्रवार को भारी उतार-चढ़ाव रहा। डीलरों ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक के फैसलों के बाद ऐसी अस्थिरता अगस्त 2022 के बाद से लगभग 3 वर्षों में पहली बार सबसे अधिक रही है। कई आश्चर्यजनक कदमों ने बाजार को चौंकाया।

समिति ने नीतिगत रीपो दर में 50 आधार अंक की कटौती का फैसला किया जबकि आम राय 25 आधार अंक कटौती की थी। रुख भी बदलकर तटस्थ कर दिया। यह एक

और आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था क्योंकि पिछली बैठक में रुख तटस्थ से बदलकर अनुकूल किया गया था। इसके अलावा सीआरआर जरूरतों को चरणबद्ध तरीके से 100 आधार अंक घटाने का फैसला किया गया।

शुक्रवार को कारोबार के दौरान बेंचमार्क गिल्ड 15 आधार अंक बढ़ा जो 5 अगस्त, 2022 के बाद सबसे ऊपर का स्तर है। तब एक दिन में गिल्ड 21 आधार अंक बढ़ा था। तटस्थ रुख में बदलाव के बाद 10 साल के बॉन्ड ने बाद में कुछ बढ़त गंवा दी। बेंचमार्क बॉन्ड ने कारोबार के अंत तक सभी बढ़त



कई मोर्चों पर फैसलों से हक्का-बक्का रह गया बॉन्ड बाजार

खत्म कर दगी और वह 6.29 प्रतिशत पर बंद हुआ जो पिछले बंद 6.25 प्रतिशत के मुकाबले 4 आधार अंक अधिक है।

पीएनबी गिल्ड्स में वरिष्ठ कार्यकारी वाइस प्रेसीडेंट विजय शर्मा ने कहा, 'रीपो दर में अप्रत्याशित कटौती से शुरुआत में बॉन्ड में तेजी आई। लेकिन नीतिगत रुख में बदलाव की बात से बाजार

भौंक रह गया। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के ताज्जुबों के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव रहा। सीआरआर में कटौती से फिर राहत मिली, लेकिन सारे नीतिगत कदम तभी घोषित कर दिए गए और भविष्य में आरबीआई की ओर से कदम उठाने का कोई संकेत नहीं मिला तो तो बाजार ने पोजीशन बेचनी शुरू कर दी।'

कम अवधि वाले खासकर 5 साल तक के सेगमेंट में एसएलआर और गैर एसएलआर (कॉर्पोरेट बॉन्ड) श्रेणी दोनों में ही बेहतर प्रदर्शन रहा है। फंडिंग लागत में कमी के कारण ऐसा हुआ।

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated May 09, 2025 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with BSE Limited ("BSE")

BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED)
Corporate Identification Number: L74140MP1984PLC002592
Registered Office: 228 Part-B, The Zodiac Mall, Bicholi Mardana, Indore (MP) - 452001
Contact Details: 7383380911; Email-ID: info@indraindustries.in; Website: www.indraindustries.in
Contact Person: Ms. Sweetsy Purohit, Company Secretary & Compliance Officer:

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE ISSUE

RIGHTS ISSUE OF UP TO 4,85,78,025*FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (RUPEE TEN ONLY) (EQUITY SHARES) EACH AT A PRICE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) PER EQUITY SHARE ("RIGHT SHARES") FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹ 48,57,80,250/- (RUPEES FOURTY EIGHT CRORE FIFTY SEVEN LAKHS EIGHTY THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED) ('COMPANY' OR 'ISSUER') IN THE RATIO OF 15 (FIFTEEN) EQUITY SHARES FOR EVERY 2 (TWO) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE. THURSDAY, MAY 09, 2025 ('ISSUE'). THE ISSUE PRICE IS 1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 130 OF THIS LETTER OF OFFER.

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") - ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MAY 9, 2025

This notice should be read in conjunction with the LOF filed by the Company with the Stock Exchange and the ALOF and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please note the following:

This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday 23rd May 2025 and was scheduled to close on Wednesday, Friday 06th June 2025, has now been extended to Monday, June 09, 2025, by the Rights Issue Committee in its meeting held on June 06 2025 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Monday, 09 June, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, 09 June, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE	
ISSUE OPENING DATE	ISSUE CLOSING DATE
FRIDAY 23RD MAY 2025	MONDAY 09TH MAY 2025

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).
** Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms on or before the Issue Closing Date.
#Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.
This addendum shall be available on the respective websites of our Company at info@indraindustries.in the Registrar to the Issue at www.purvashare.com, and the Stock Exchanges at www.bseindia.com.
Accordingly, there is no change in the LOF and ALOF dated May 09, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing date. Change in Issue closing date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date.
INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.
All Capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For Bluegod Entertainment Limited
(Formerly Known As Indra Industries Limited)
Sd/-
Nitinashok kumar Khanna
Managing Director

Date: May 09, 2025
Place: Indore

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the BSE Limited The Draft Letter of Offer is available on the website of the Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com. Our Company at info@indraindustries.in and the Registrar to the Issue at www.purvashare.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Draft Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 31 of the Draft Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

3 प्रतिशत सीआरआर नया सामान्य स्तर

प्रभावी नकदी प्रबंधन के लिए 3 प्रतिशत सीआरआर पर्याप्त

अंजलि कुमारी
मुंबई, 6 जून

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) जरूरतों को 100 आधार अंक घटाकर शुद्ध मांग और सावधि देनदारी (एनडीटीएल) का 3 प्रतिशत करने का फैसला किया है। यह फैसला चरणबद्ध तरीके से 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाले पखवाड़ों से प्रभावी होगा।

सीआरआर में कटौती से दिसंबर 2025 तक बैंकिंग व्यवस्था में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये की प्राथमिक नकदी आएगी। ऐतिहासिक रूप से सामान्य समय में सीआरआर 4 प्रतिशत बहाल रखा जाता रहा है। यह राशि बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखनी पड़ती है और इस पर उन्हें ब्याज नहीं मिलता है। कोविड-19 महामारी के दौरान सीआरआर घटाकर 3 प्रतिशत किया गया था।

अब माना जा रहा है कि 3 प्रतिशत सीआरआर नया सामान्य स्तर हो सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सीआरआर घटाने की वजह बताते हुए कहा, 'इससे न सिर्फ नकदी में सुधार होगा, बल्कि इससे बैंकों को फंड की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी।'

मल्होत्रा ने नीतिगत फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'पिछले 12-13 साल के आंकड़ों से पता चलता है और कोई भी इसे देख सकता है कि सीआरआर ज्यादातर समय 4 प्रतिशत पर रहा है। कोविड के दौरान हमने इसे 1 प्रतिशत घटाया। अब इस रिजर्व को दरअसल नकदी प्रबंधन के लिए रखा जाता है। ऐसे में अब तक के अनुभव हमें बताते हैं कि



रिजर्व बैंक के फैसले से न सिर्फ नकदी में सुधार होगा, बल्कि बैंकों को फंड की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी

यह 4 प्रतिशत रखने की जरूरत नहीं है और शायद 3 प्रतिशत पर्याप्त है।'

उन्होंने कहा, 'हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा। अब ऐसा लग रहा है कि 3 प्रतिशत आरक्षित अनुपात नकदी प्रबंधन के लिए सहज है।' मल्होत्रा ने कहा कि सीआरआर में कटौती से मौद्रिक नीति का असर भी तेज होगा। उन्होंने जोर दिया कि रिजर्व बैंक नकदी और वित्तीय बाजार की स्थिति की निगरानी जारी रखेगा और जरूरत के मुताबिक सक्रिय रूप से भविष्य में कदम उठाएगा।

सीआरआर में कटौती के कारण बैंकों को मिलने वाली नकदी का उपयोग अब राजस्व आय परिसंपत्तियों में किया जा सकेगा, जिससे बैंकों को मार्जिन में सुधार करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर नीतिगत दर में 100 आधार अंक की कटौती से बैंकों के ब्याज से शुद्ध मुनाफे पर दबाव कम होगा। रिजर्व बैंक के

अनुमान के मुताबिक बैंकों का मार्जिन 7 आधार अंक सुधरेगा। उन्होंने कहा, 'नकदी मुहैया कराने के अलावा इसकी वजह से लागत भी घटेगी और हमारे अनुमान के मुताबिक उनका शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) कम से कम करीब 7 आधार अंक सुधरेगा। (हम नकदी मुहैया करा रहे हैं) इसलिए नीतिगत फैसले का बेहतर और तेजी से ट्रांसमिशन होगा।'

आईडीएफसी फ्रस्ट बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट गौरा सेनगुप्ता ने कहा, 'आकलन पूरी तरह से बदल गया है। कोविड के पहले सीआरआर कभी भी 4 प्रतिशत से नीचे नहीं आया। हाल के इतिहास में... संभवतः 1960 के दशक में ऐसा हुआ होगा। यही कारण है कि कोई सीआरआर में कटौती की उम्मीद नहीं कर रहा था। बिना संकट वाले दौर के पर दबाव कम होगा। रिजर्व बैंक के

देखा गया था। अब सीआरआर 3 प्रतिशत करने का मतलब यह है कि रिजर्व बैंक के विचार में बदलाव आया है कि सामान्य दिनों में कितना पर्याप्त है। अब यह गैर संकट के दौर का सामान्य स्तर लग रहा है।' उन्होंने कहा, 'इसका और भी कुछ मतलब है। रिजर्व बैंक नकदी बढ़ाने के लिए ओएमओ का विकल्प चुना। यह निर्णय खासकर बैंकों के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ से नकदी बढ़ाने की जरूरत बताता है।' ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक बैंकों के लिए मार्जिन का प्रबंध करते हुए नकदी तक उनकी पहुंच आसान करने की कोशिश कर रहा है।' पिछली बार दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति की घोषणा में रिजर्व बैंक ने सीआरआर 50 आधार अंक घटाकर 4 प्रतिशत किया था।

सवाल जवाब

पहले की तुलना में समिति के फैसलों का तेज असर

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर जवाब दिए। उन्होंने कहा कि पिछले रुझानों को देखें तो मौद्रिक नीति का असर बहुत तेजी से हुआ है। मुद्रा बाजारों में जो हमने किया है उससे भी अधिक असर हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह आकलन मुश्किल होगा कि मौद्रिक नीति से ऋण की दरों और वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इसका असर कैसा रहेगा। संपादित अंश:

इस चक्र में आप दरों को कहां टिकता देख रहे हैं? हमने रुख को उदार से तटस्थ कर दिया है। साथ ही इसमें उल्लेख किया गया है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वास्तव में मौद्रिक नीति को लेकर अब बहुत सीमित गुंजाइश है। आप मौजूदा हालात के बारे में जानते हैं, वृद्धि दर करीब 6.5 प्रतिशत है। इस वर्ष के लिए हम महंगाई दर 3.7 प्रतिशत और अगले वर्ष 4 प्रतिशत से ऊपर या करीब 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगा रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए एमपीसी के लिए बहुत कम गुंजाइश बची है। हमने अब रुख तटस्थ कर दिया है। समिति का यह भी कहना है कि आने वाले उन आंकड़ों और आधारों पर खासकर अनिश्चितताओं को देखते हुए लगातार नजर रखी जाएगी। हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, यह मुख्य रूप से आंकड़ों पर निर्भर होगा।

रुख अब तटस्थ कर दिया गया है। क्या लंबे समय का विराम होगा?

यह अब आंकड़ों पर निर्भर करेगा। तटस्थ का यही मतलब है। मैंने इसे पहले एमपीसी के ब्योरे में साफ किया था कि तटस्थ का मतलब है कि यह किसी भी दिशा में जा सकता है। यह इस पर निर्भर होगा कि आंकड़े कैसे आते हैं। अगर वृद्धि कमजोर है, तो इसका मतलब है कि यह नीचे जाएगी। अगर वृद्धि अच्छी है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि रीपो रेट बढ़ सकती है। इसलिए यह इस बात पर निर्भर करेगा कि महंगाई और वृद्धि के आंकड़े कैसे आते हैं।

क्या रुख पर मतदान हुआ था?

रुख पर मतदान को लेकर हमने पहले ही उल्लेख किया है कि कानून में मतदान अनिवार्य नहीं है। इस पर चर्चा हुई। निश्चित रूप से हमें संकेत देने, अनुमान देने की जरूरत थी। यह अनुमान है, जो हमें बाजार के प्रतिभागियों को देना होता है। इसलिए इस पर चर्चा हुई और समिति के सभी 6 सदस्यों का विचार था कि हमें तटस्थ रुख रखना चाहिए। इसलिए कोई मतदान नहीं हुआ। समिति के सभी सदस्यों का विचार यह है कि आगे चलकर रुख बदलकर उदार से तटस्थ किया जाना चाहिए।

क्या नीति के अब तक हुए असर से संतुष्ट हैं?

पिछले रुझानों को देखें तो मौद्रिक नीति का असर बहुत तेजी से हुआ है। मुद्रा बाजारों में आप बड़ा असर देख सकते हैं। जो हमने किया है उससे भी अधिक असर हुआ है। खासकर कम अवधि के हिसाब से मुद्रा बाजारों में 50 आधार अंक की तुलना में भी अधिक असर दिख रहा है। ऋण पर भी शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। ज्यादातर बैंकों ने थोक और खुदरा दोनों जमा दरों में करीब 40 आधार अंक की कमी की है। औसतन करीब 27 आधार अंक कमी हुई



है। ऋण के हिसाब से देखें तो बचे हुए ऋण पर 17 आधार अंक कमी आई है। नए ऋण के हिसाब से देखें तो असर थोड़ा धीमा है।

हमारे आंकड़ों के मुताबिक यह करीब 6 आधार अंक है। इस तरह से यह सुस्त है, लेकिन इससे पहले के वक्त की तुलना में बहुत तेज है। आम तौर पर इसमें 6 से 9 महीने लगते हैं। पहली नीतिगत कटौती से केवल 4 महीने हुए हैं। इसलिए 25 आधार अंक की पहली नीतिगत कटौती के मुकाबले जमा में 27 आधार अंक और ऋण में 17 आधार अंक और नए ऋण के लिए 6 आधार अंक की कटौती हुई है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा ट्रांसमिशन है। लेकिन हमें इसे और तेजी से करने की जरूरत है, इसलिए इस बार हमने कुछ कार्रवाई पहले ही कर ली है।

रीपो रेट में कुल 100 आधार अंक की कटौती से आप वृद्धि में कितनी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं? क्या वित्त वर्ष 2026 के वृद्धि अनुमान में संशोधन होगा?

जाहिर है, इसका (वृद्धि पर) सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह आकलन करना बहुत मुश्किल होगा कि मौद्रिक नीति से ऋण की दरों और उसके बाद वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इसका असर कैसा रहेगा। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इसका असर दिखले में कम से कम 6 से 9 महीने लगते हैं। हम इसे तेज करना चाहते हैं, लेकिन इसका असर दूसरी छमाही में ही दिखेगा। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इस साल जब इतनी अनिश्चितता है, हम कुछ ठोस रूप से बताने की स्थिति में नहीं हैं कि जीडीपी के आंकड़ों पर इसका कितना असर होगा।

यह नकदी का वृद्धि पर वाकई कैसे असर डालती है? व्यवस्था में अधिक नकदी का क्या लाभ है? यह अन्य कारकों पर भी निर्भर करेगा। मौद्रिक नीति पर्याप्त नहीं, लेकिन जरूरी है। हमें विश्वास है कि इससे ऋण वृद्धि बेहतर होगी। मैं कोई स्पष्ट आंकड़ा देने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन भरोसे के साथ यह कहा जा सकता है कि इससे ऋण प्रवाह बढ़ेगा। इसलिए नकदी महत्वपूर्ण है। रीपो रेट में कमी महत्वपूर्ण है। इसमें कितना वक्त लगेगा, यह कहना कठिन है।

50 आधार अंक की कटौती, सीआरआर में 100 आधार अंक की कटौती और रुख को बदलकर तटस्थ करने का फैसला अप्रत्याशित रूप से आश्चर्यजनक था।



नीतिगत दर में 50 आधार अंक की कटौती, सीआरआर में 100 आधार अंक की कटौती और रुख को बदलकर तटस्थ करने का फैसला अप्रत्याशित रूप से आश्चर्यजनक था।

सीएस शेट्टी

चेयरमैन, भारतीय स्टेट बैंक



मौद्रिक नीति समिति ने सुखद रूप से बाजारों को आश्चर्य-चकित कर दिया है। अतिरिक्त नकदी के साथ ब्याज दर कम होने से उधारी की लागत कम होगी और आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा।

पीडी सिंह

सीईओ, भारत-दक्षिण एशिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

रिजर्व बैंक द्वारा ढील दिए जाने के तरीकों को आगे बढ़ाने का फैसला भारत की वृद्धि की कहानी को और मजबूती से आगे बढ़ाता है। इन उपायों से नीति का तेज असर होगा और ऋण की लागत घटेगी



के बाला सुब्रमण्यन

सीईओ सिटी बैंक

परिपक्व बाजार का संकेत

धन वापसी के कारण शुद्ध एफडीआई में कमी आई

अभिजित लेले
मुंबई, 6 जून

वित्त वर्ष 2025 के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में तेज गिरावट धन वापस अपने देश भेजने की वजह से आई है। यह परिपक्व बाजार का संकेत है, जिसमें निवेशक आसानी से बाजार में कदम रख सकते और निकल सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा करते हुए यह बात कही।

इस महीने की शुरुआत में जारी रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध एफडीआई की आवक घटकर 0.4 अरब डॉलर रह गई है जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 10.1 अरब डॉलर थी। सकल

एफडीआई की आवक मजबूत बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह 14 प्रतिशत बढ़कर 8.1 अरब डॉलर हो गया है जो एक साल पहले 7.13 अरब डॉलर था।

मल्होत्रा ने कहा, 'यह बताना मुनासिब है कि (शुद्ध एफडीआई में) यह कमी धन वापस भेजने में इजाफा और शुद्ध रूप से विदेश में निवेशक आसानी से बाजार में कदम रख सकते और निकल सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा करते हुए यह बात कही।' 'इस महीने की शुरुआत में जारी रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध एफडीआई की आवक घटकर 0.4 अरब डॉलर रह गई है जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 10.1 अरब डॉलर थी। सकल



प्रवासी भारतीयों ने जमा किया ज्यादा धन

उन्होंने कहा कि बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) और प्रवासी भारतीयों की जमा में शुद्ध आवक पिछले के वित्त वर्ष की तुलना में अधिक रही है। भारत में ईसीबी से शुद्ध आवक वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 18.7 अरब डॉलर

हो गई है, जो एक साल पहले 3.6 अरब डॉलर थी। अप्रैल 2025 में शुद्ध ईसीबी बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गई जो पिछले वर्ष 0.5 अरब डॉलर थी। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रवासी जमा बढ़कर 16.2 अरब डॉलर हो गई है जो एक साल पहले 14.7 अरब डॉलर थी। उन्होंने कहा, 'कुल मिलाकर भारत का बाहरी क्षेत्र मजबूत बना हुआ है और प्रमुख बाहरी क्षेत्र के उतार-चढ़ाव वाले संकेतकों में सुधार जारी है। हमें भरोसा है कि हम अपनी बाहरी विदेशी वित्तपोषण की जरूरतें पूरी कर लेंगे।' वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश तेजी से गिरकर 1.7 अरब डॉलर रह गया है क्योंकि शेयर बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मुनाफावसूली की है।

बॉन्ड बाजार

3 साल की तुलना में सर्वाधिक उतार-चढ़ाव

अंजलि कुमारी
मुंबई, 6 जून

बॉन्ड बाजार में शुक्रवार को भारी उतार-चढ़ाव रहा। डीलरों ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक के फैसलों के बाद ऐसी अस्थिरता अगस्त 2022 के बाद से लगभग 3 वर्षों में पहली बार सबसे अधिक रही है। कई आश्चर्यजनक कदमों ने बाजार को चौंकाया।

समिति ने नीतिगत रीपो दर में 50 आधार अंक की कटौती का फैसला किया जबकि आम राय 25 आधार अंक कटौती की थी। रुख भी बदलकर तटस्थ कर दिया। यह एक

और आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था क्योंकि पिछली बैठक में रुख तटस्थ से बदलकर अनुकूल किया गया था। इसके अलावा सीआरआर जरूरतों को चरणबद्ध तरीके से 100 आधार अंक घटाने का फैसला किया गया।

शुक्रवार को कारोबार के दौरान बेंचमार्क गिल्ड 15 आधार अंक बढ़ा जो 5 अगस्त, 2022 के बाद सबसे ऊपर का स्तर है। तब एक दिन में गिल्ड 21 आधार अंक बढ़ा था। तटस्थ रुख में बदलाव के बाद 10 साल के बॉन्ड ने बाद में कुछ बढ़त गंवा दी। बेंचमार्क बॉन्ड ने कारोबार के अंत तक सभी बढ़त



कई मोर्चों पर फैसलों से हक्का-बक्का रह गया बॉन्ड बाजार

खत्म कर दगी और वह 6.29 प्रतिशत पर बंद हुआ जो पिछले बंद 6.25 प्रतिशत के मुकाबले 4 आधार अंक अधिक है। पीएनबी गिल्ड्स में वरिष्ठ कार्यकारी वाइस प्रेसीडेंट विजय शर्मा ने कहा, 'रीपो दर में अप्रत्याशित कटौती से शुरुआत में बॉन्ड में तेजी आई। लेकिन नीतिगत रुख में बदलाव की बात से बाजार

भौंक रह गया। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के ताज्जुबों के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव रहा। सीआरआर में कटौती से फिर राहत मिली, लेकिन सारे नीतिगत कदम तभी घोषित कर दिए गए और भविष्य में आरबीआई की ओर से कदम उठाने का कोई संकेत नहीं मिला तो तो बाजार ने पोजीशन बेचनी शुरू कर दी।' कम अवधि वाले खासकर 5 साल तक के सेगमेंट में एसएलआर और गैर एसएलआर (कॉर्पोरेट बॉन्ड) श्रेणी दोनों में ही बेहतर प्रदर्शन रहा है। फंडिंग लागत में कमी के कारण ऐसा हुआ।

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated May 09, 2025 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with BSE Limited ("BSE")

BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED)
Corporate Identification Number: L74140MP1984PLC002592
Registered Office: 228 Part-B, The Zodiac Mall, Bicholi Mardana, Indore (MP) - 452001
Contact Details: 7383380911; Email-ID: info@indraindustries.in; Website: www.indraindustries.in
Contact Person: Ms. Sweetsy Purohit, Company Secretary & Compliance Officer:

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE ISSUE

RIGHTS ISSUE OF UP TO 4,85,78,025*FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (RUPEE TEN ONLY) (EQUITY SHARES) EACH AT A PRICE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) PER EQUITY SHARE ("RIGHT SHARES") FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹48,57,80,250/- (RUPEES FOURTY EIGHT CRORE FIFTY SEVEN LAKHS EIGHTY THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED) (COMPANY OR 'ISSUER') IN THE RATIO OF 15 (FIFTEEN) EQUITY SHARES FOR EVERY 2 (TWO) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE. THURSDAY, MAY 09, 2025 ('ISSUE'). THE ISSUE PRICE IS 1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 130 OF THIS LETTER OF OFFER.

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") - ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MAY 9, 2025

This notice should be read in conjunction with the LOF filed by the Company with the Stock Exchange and the ALOF and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please note the following:

This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday 23rd May 2025 and was scheduled to close on Wednesday, Friday 06th June 2025, has now been extended to Monday, June 09, 2025, by the Rights Issue Committee in its meeting held on June 06 2025 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Monday, 09 June, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, 09 June, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE

ISSUE OPENING DATE	ISSUE CLOSING DATE
FRIDAY 23RD MAY 2025	MONDAY 09TH MAY 2025

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).
** Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms on or before the Issue Closing Date.
#Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.
This addendum shall be available on the respective websites of our Company at info@indraindustries.in the Registrar to the Issue at www.puravshare.com, and the Stock Exchanges at www.bseindia.com.
Accordingly, there is no change in the LOF and ALOF dated May 09, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing date. Change in Issue closing date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date.
INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.
All Capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For Bluegod Entertainment Limited (Formerly Known As Indra Industries Limited)
Sd/-
Nitinashok kumar Khanna
Managing Director

Date: May 09, 2025
Place: Indore

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the BSE Limited The Draft Letter of Offer is available on the website of Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com. Our Company at info@indraindustries.in and the Registrar to the Issue at www.puravshare.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Draft Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 31 of the Draft Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

3 प्रतिशत सीआरआर नया सामान्य स्तर

प्रभावी नकदी प्रबंधन के लिए 3 प्रतिशत सीआरआर पर्याप्त

अंजलि कुमारी
मुंबई, 6 जून

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) जरूरतों को 100 आधार अंक घटाकर शुद्ध मांग और सावधि देनदारी (एनडीटीएल) का 3 प्रतिशत करने का फैसला किया है। यह फैसला चरणबद्ध तरीके से 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाले पखवाड़ों से प्रभावी होगा।

सीआरआर में कटौती से दिसंबर 2025 तक बैंकिंग व्यवस्था में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये की प्राथमिक नकदी आएगी। ऐतिहासिक रूप से सामान्य समय में सीआरआर 4 प्रतिशत बहाल रखा जाता रहा है। यह राशि बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखनी पड़ती है और इस पर उन्हें ब्याज नहीं मिलता है। कोविड-19 महामारी के दौरान सीआरआर घटाकर 3 प्रतिशत किया गया था।

अब माना जा रहा है कि 3 प्रतिशत सीआरआर नया सामान्य स्तर हो सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सीआरआर घटाने की वजह बताते हुए कहा, 'इससे न सिर्फ नकदी में सुधार होगा, बल्कि इससे बैंकों को फंड की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी।'

मल्होत्रा ने नीतिगत फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'पिछले 12-13 साल के आंकड़ों से पता चलता है और कोई भी इसे देख सकता है कि सीआरआर ज्यादातर समय 4 प्रतिशत पर रहा है। कोविड के दौरान हमने इसे 1 प्रतिशत घटाया। अब इस रिजर्व को दरअसल नकदी प्रबंधन के लिए रखा जाता है। ऐसे में अब तक के अनुभव हमें बताते हैं कि



रिजर्व बैंक के फैसले से न सिर्फ नकदी में सुधार होगा, बल्कि बैंकों को फंड की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी

यह 4 प्रतिशत रखने की जरूरत नहीं है और शायद 3 प्रतिशत पर्याप्त है।'

उन्होंने कहा, 'हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा। अब ऐसा लग रहा है कि 3 प्रतिशत आरक्षित अनुपात नकदी प्रबंधन के लिए सहज है।' मल्होत्रा ने कहा कि सीआरआर में कटौती से मौद्रिक नीति का असर भी तेज होगा। उन्होंने जोर दिया कि रिजर्व बैंक नकदी और वित्तीय बाजार की स्थिति की निगरानी जारी रखेगा और जरूरत के मुताबिक सक्रिय रूप से भविष्य में कदम उठाएगा। सीआरआर में कटौती के कारण बैंकों को मिलने वाली नकदी का उपयोग अब राजस्व आय परिसंपत्तियों में किया जा सकेगा, जिससे बैंकों को मार्जिन में सुधार करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर नीतिगत दर में 100 आधार अंक की कटौती से बैंकों के ब्याज से शुद्ध मुनाफे पर दबाव कम होगा। रिजर्व बैंक के

अनुमान के मुताबिक बैंकों का मार्जिन 7 आधार अंक सुधरेगा। उन्होंने कहा, 'नकदी मुहैया कराने के अलावा इसकी वजह से लागत भी घटेगी और हमारे अनुमान के मुताबिक उनका शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) कम से कम करीब 7 आधार अंक सुधरेगा। (हम नकदी मुहैया करा रहे हैं) इसलिए नीतिगत फैसले का बेहतर और तेजी से ट्रांसमिशन होगा।'

आईडीएफसी फ्रस्ट बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट गौरा सेनगुप्ता ने कहा, 'आकलन पूरी तरह से बदल गया है। कोविड के पहले सीआरआर कभी भी 4 प्रतिशत से नीचे नहीं आया। हाल के इतिहास में... संभवतः 1960 के दशक में ऐसा हुआ होगा। यही कारण है कि कोई सीआरआर में कटौती की उम्मीद नहीं कर रहा था। बिना संकट वाले दौर के पर दबाव कम होगा। रिजर्व बैंक के

देखा गया था। अब सीआरआर 3 प्रतिशत करने का मतलब यह है कि रिजर्व बैंक के विचार में बदलाव आया है कि सामान्य दिनों में कितना पर्याप्त है। अब यह गैर संकट के दौर का सामान्य स्तर लग रहा है।' उन्होंने कहा, 'इसका और भी कुछ मतलब है। रिजर्व बैंक नकदी बढ़ाने के लिए ओएमओ का विकल्प चुना। यह निर्णय खासकर बैंकों के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ से नकदी बढ़ाने की जरूरत बताता है। ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक बैंकों के लिए मार्जिन का प्रबंध करते हुए नकदी तक उनकी पहुंच आसान करने की कोशिश कर रहा है।' पिछली बार दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति की घोषणा में रिजर्व बैंक ने सीआरआर 50 आधार अंक घटाकर 4 प्रतिशत किया था।

सवाल जवाब

पहले की तुलना में समिति के फैसलों का तेज असर

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर जवाब दिए। उन्होंने कहा कि पिछले रुझानों को देखते तो मौद्रिक नीति का असर बहुत तेजी से हुआ है। मुद्रा बाजारों में जो हमने किया है उससे भी अधिक असर हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह आकलन मुश्किल होगा कि मौद्रिक नीति से ऋण की दरों और वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इसका असर कैसा रहेगा। संपादित अंश:

इस चक्र में आप दरों को कहां टिकता देख रहे हैं? हमने रुख को उदार से तटस्थ कर दिया है। साथ ही इसमें उल्लेख किया गया है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वास्तव में मौद्रिक नीति को लेकर अब बहुत सीमित गुंजाइश है। आप मौजूदा हालात के बारे में जानते हैं, वृद्धि दर करीब 6.5 प्रतिशत है। इस वर्ष के लिए हम महंगाई दर 3.7 प्रतिशत और अगले वर्ष 4 प्रतिशत से ऊपर या करीब 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगा रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए एमपीसी के लिए बहुत कम गुंजाइश बची है। हमने अब रुख तटस्थ कर दिया है। समिति का यह भी कहना है कि आने वाले उन आंकड़ों और आधारों पर खासकर अनिश्चितताओं को देखते हुए लगातार नजर रखी जाएगी। हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, यह मुख्य रूप से आंकड़ों पर निर्भर होगा।

रुख अब तटस्थ कर दिया गया है। क्या लंबे समय का विराम होगा?

यह अब आंकड़ों पर निर्भर करेगा। तटस्थ का यही मतलब है। मैंने इसे पहले एमपीसी के ब्योरे में साफ किया था कि तटस्थ का मतलब है कि यह किसी भी दिशा में जा सकता है। यह इस पर निर्भर होगा कि आंकड़े कैसे आते हैं। अगर वृद्धि कमजोर है, तो इसका मतलब है कि यह नीचे जाएगी। अगर वृद्धि अच्छी है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि रीपो रेट बढ़ सकती है। इसलिए यह इस बात पर निर्भर करेगा कि महंगाई और वृद्धि के आंकड़े कैसे आते हैं।

क्या रुख पर मतदान हुआ था?

रुख पर मतदान को लेकर हमने पहले ही उल्लेख किया है कि कानून में मतदान अनिवार्य नहीं है। इस पर चर्चा हुई। निश्चित रूप से हमें संकेत देने, अनुमान देने की जरूरत थी। यह अनुमान है, जो हमें बाजार के प्रतिभागियों को देना होता है। इसलिए इस पर चर्चा हुई और समिति के सभी 6 सदस्यों का विचार था कि हमें तटस्थ रुख रखना चाहिए। इसलिए कोई मतदान नहीं हुआ। समिति के सभी सदस्यों का विचार यह है कि आगे चलकर रुख बदलकर उदार से तटस्थ किया जाना चाहिए।

क्या नीति के अब तक हुए असर से संतुष्ट हैं?

पिछले रुझानों को देखते तो मौद्रिक नीति का असर बहुत तेजी से हुआ है। मुद्रा बाजारों में आप बड़ा असर देख सकते हैं। जो हमने किया है उससे भी अधिक असर हुआ है। खासकर कम अवधि के हिसाब से मुद्रा बाजारों में 50 आधार अंक की तुलना में भी अधिक असर दिख रहा है। ऋण पर भी शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। ज्यादातर बैंकों ने थोक और खुदरा दोनों जमा दरों में करीब 40 आधार अंक की कमी की है। औसतन करीब 27 आधार अंक कमी हुई



है। ऋण के हिसाब से देखें तो बचे हुए ऋण पर 17 आधार अंक कमी आई है। नए ऋण के हिसाब से देखें तो असर थोड़ा धीमा है।

हमारे आंकड़ों के मुताबिक यह करीब 6 आधार अंक है। इस तरह से यह सुस्त है, लेकिन इससे पहले के वक्त की तुलना में बहुत तेज है। आम तौर पर इसमें 6 से 9 महीने लगते हैं। पहली नीतिगत कटौती से केवल 4 महीने हुए हैं। इसलिए 25 आधार अंक की पहली नीतिगत कटौती के मुकाबले जमा में 27 आधार अंक और ऋण में 17 आधार अंक और नए ऋण के लिए 6 आधार अंक की कटौती हुई है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा ट्रांसमिशन है। लेकिन हमें इसे और तेजी से करने की जरूरत है, इसलिए इस बार हमने कुछ कार्रवाई पहले ही कर ली है।

रीपो रेट में कुल 100 आधार अंक की कटौती से आप वृद्धि में कितनी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं? क्या वित्त वर्ष 2026 के वृद्धि अनुमान में संशोधन होगा?

जाहिर है, इसका (वृद्धि पर) सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह आकलन करना बहुत मुश्किल होगा कि मौद्रिक नीति से ऋण की दरों और उसके बाद वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इसका असर कैसा रहेगा। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इसका असर दिखले में कम से कम 6 से 9 महीने लगते हैं। हम इसे तेज करना चाहते हैं, लेकिन इसका असर दूसरी छमाही में ही दिखेगा। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इस साल जब इतनी अनिश्चितता है, हम कुछ ठोस रूप से बताने की स्थिति में नहीं हैं कि जीडीपी के आंकड़ों पर इसका कितना असर होगा।

यह नकदी का वृद्धि पर वाकई कैसे असर डालती है? व्यवस्था में अधिक नकदी का क्या लाभ है? यह अन्य कारकों पर भी निर्भर करेगा। मौद्रिक नीति पर्याप्त नहीं, लेकिन जरूरी है। हमें विश्वास है कि इससे ऋण वृद्धि बेहतर होगी। मैं कोई स्पष्ट आंकड़ा देने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन भरोसे के साथ यह कहा जा सकता है कि इससे ऋण प्रवाह बढ़ेगा। इसलिए नकदी महत्वपूर्ण है। रीपो रेट में कमी महत्वपूर्ण है। इसमें कितना वक्त लगेगा, यह कहना कठिन है।



नीतिगत दर में 50 आधार अंक की कटौती, सीआरआर में 100 आधार अंक की कटौती और रुख को बदलकर तटस्थ करने का फैसला अप्रत्याशित रूप से आश्चर्यजनक था।



मौद्रिक नीति समिति ने सुखद रूप से बाजारों को आश्चर्य-चकित कर दिया है। अतिरिक्त नकदी के साथ ब्याज दर कम होने से उधारी की लागत कम होगी और आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा।



पीडी सिंह
सीईओ, भारत-दक्षिण एशिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

रिजर्व बैंक द्वारा ढील दिए जाने के तरीकों को आगे बढ़ाने का फैसला भारत की वृद्धि की कहानी को और मजबूती से आगे बढ़ाता है। इन उपायों से नीति का तेज असर होगा और ऋण की लागत घटेगी



के बाला सुब्रमण्यम
सीईओ सिटी बैंक

परिपक्व बाजार का संकेत

धन वापसी के कारण शुद्ध एफडीआई में कमी आई

अभिजित लेले
मुंबई, 6 जून

वित्त वर्ष 2025 के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में तेज गिरावट धन वापस अपने देश भेजने की वजह से आई है। यह परिपक्व बाजार का संकेत है, जिसमें निवेशक आसानी से बाजार में कदम रख सकते और निकल सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा करते हुए यह बात कही।

इस महीने की शुरुआत में जारी रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध एफडीआई की आवक घटकर 0.4 अरब डॉलर रह गई है जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 10.1 अरब डॉलर थी। सकल

एफडीआई की आवक मजबूत बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह 14 प्रतिशत बढ़कर 8.1 अरब डॉलर हो गया है जो एक साल पहले 7.13 अरब डॉलर था।

मल्होत्रा ने कहा, 'यह बताना मुनासिब है कि (शुद्ध एफडीआई में) यह कमी धन वापस भेजने में इजाफा और शुद्ध रूप से विदेश में निवेशक आसानी से बाजार में कदम रख सकते और निकल सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा करते हुए यह बात कही।' 'इस महीने की शुरुआत में जारी रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध एफडीआई की आवक घटकर 0.4 अरब डॉलर रह गई है जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 10.1 अरब डॉलर थी। सकल



प्रवासी भारतीयों ने जमा किया ज्यादा धन

उन्होंने कहा कि बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) और प्रवासी भारतीयों की जमा में शुद्ध आवक पिछले के वित्त वर्ष की तुलना में अधिक रही है। भारत में ईसीबी से शुद्ध आवक वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 18.7 अरब डॉलर

हो गई है, जो एक साल पहले 3.6 अरब डॉलर थी। अप्रैल 2025 में शुद्ध ईसीबी बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गई जो पिछले वर्ष 0.5 अरब डॉलर थी। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रवासी जमा बढ़कर 16.2 अरब डॉलर हो गई है जो एक साल पहले 14.7 अरब डॉलर थी। उन्होंने कहा, 'कुल मिलाकर भारत का बाहरी क्षेत्र मजबूत बना हुआ है और प्रमुख बाहरी क्षेत्र के उतार-चढ़ाव वाले संकेतकों में सुधार जारी है। हमें भरोसा है कि हम अपनी बाहरी विदेशी वित्तपोषण की जरूरतें पूरी कर लेंगे।' वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश तेजी से गिरकर 1.7 अरब डॉलर रह गया है क्योंकि शेयर बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मुनाफावसूली की है।

बॉन्ड बाजार

3 साल की तुलना में सर्वाधिक उतार-चढ़ाव

अंजलि कुमारी
मुंबई, 6 जून

बॉन्ड बाजार में शुक्रवार को भारी उतार-चढ़ाव रहा। डीलरों ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक के फैसलों के बाद ऐसी अस्थिरता अगस्त 2022 के बाद से लगभग 3 वर्षों में पहली बार सबसे अधिक रही है। कई आश्चर्यजनक कदमों ने बाजार को चौंकाया।

समिति ने नीतिगत रीपो दर में 50 आधार अंक की कटौती का फैसला किया जबकि आम राय 25 आधार अंक कटौती की थी। रुख भी बदलकर तटस्थ कर दिया। यह एक

और आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था क्योंकि पिछली बैठक में रुख तटस्थ से बदलकर अनुकूल किया गया था। इसके अलावा सीआरआर जरूरतों को चरणबद्ध तरीके से 100 आधार अंक घटाने का फैसला किया गया।

शुक्रवार को कारोबार के दौरान बेंचमार्क गिल्ड 15 आधार अंक बढ़ा जो 5 अगस्त, 2022 के बाद सबसे ऊपर का स्तर है। तब एक दिन में गिल्ड 21 आधार अंक बढ़ा था। तटस्थ रुख में बदलाव के बाद 10 साल के बॉन्ड ने बाद में कुछ बढ़त गंवा दी। बेंचमार्क बॉन्ड ने कारोबार के अंत तक सभी बढ़त



कई मोर्चों पर फैसलों से हक्का-बक्का रह गया बॉन्ड बाजार

खत्म कर दगी और वह 6.29 प्रतिशत पर बंद हुआ जो पिछले बंद 6.25 प्रतिशत के मुकाबले 4 आधार अंक अधिक है। पीएनबी गिल्ड्स में वरिष्ठ

कार्यकारी वाइस प्रेसीडेंट विजय शर्मा ने कहा, 'रीपो दर में अप्रत्याशित कटौती से शुरुआत में बॉन्ड में तेजी आई। लेकिन नीतिगत रुख में बदलाव की बात से बाजार

भौंक रह गया। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के ताज्जुबों के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव रहा। सीआरआर में कटौती से फिर राहत मिली, लेकिन सारे नीतिगत कदम तभी घोषित कर दिए गए और भविष्य में आरबीआई की ओर से कदम उठाने का कोई संकेत नहीं मिला तो तो बाजार ने पोजीशन बेचनी शुरू कर दी।' कम अवधि वाले खासकर 5 साल तक के सेगमेंट में एसएलआर और गैर एसएलआर (कॉर्पोरेट बॉन्ड) श्रेणी दोनों में ही बेहतर प्रदर्शन रहा है। फंडिंग लागत में कमी के कारण ऐसा हुआ।

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated May 09, 2025 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with BSE Limited ("BSE")

BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED)
Corporate Identification Number: L74140MP1984PLC002592
Registered Office: 228 Part-B, The Zodiac Mall, Bicholi Mardana, Indore (MP) - 452001
Contact Details: 7383380911; Email-ID: info@indraindustries.in; Website: www.indraindustries.in
Contact Person: Ms. Sweetsy Purohit, Company Secretary & Compliance Officer:

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE ISSUE

RIGHTS ISSUE OF UP TO 4,85,78,025*FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (RUPEE TEN ONLY) (EQUITY SHARES) EACH AT A PRICE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) PER EQUITY SHARE ("RIGHT SHARES") FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹ 48,57,80,250/- (RUPEES FOURTY EIGHT CRORE FIFTY SEVEN LAKHS EIGHTY THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF BLUEGOD ENTERTAINMENT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDRA INDUSTRIES LIMITED) (COMPANY OR 'ISSUER') IN THE RATIO OF 15 (FIFTEEN) EQUITY SHARES FOR EVERY 2 (TWO) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE. THURSDAY, MAY 09, 2025 ('ISSUE'). THE ISSUE PRICE IS 1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 130 OF THIS LETTER OF OFFER.

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") - ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MAY 9, 2025

This notice should be read in conjunction with the LOF filed by the Company with the Stock Exchange and the ALOF and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please note the following:

This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday 23rd May 2025 and was scheduled to close on Wednesday, Friday 06th June 2025, has now been extended to Monday, June 09, 2025, by the Rights Issue Committee in its meeting held on June 06 2025 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Monday, 09 June, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, 09 June, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE	
ISSUE OPENING DATE	ISSUE CLOSING DATE
FRIDAY 23RD MAY 2025	MONDAY 09TH MAY 2025

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).
** Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms on or before the Issue Closing Date.
#Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.
This addendum shall be available on the respective websites of our Company at info@indraindustries.in the Registrar to the Issue at www.purvashare.com, and the Stock Exchanges at www.bseindia.com.
Accordingly, there is no change in the LOF and ALOF dated May 09, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing date. Change in Issue closing date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date.
INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.
All Capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For Bluegod Entertainment Limited (Formerly Known As Indra Industries Limited)
Sd/-
Nitinashok kumar Khanna
Managing Director

Date: May 09, 2025
Place: Indore

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the BSE Limited The Draft Letter of Offer is available on the website of the Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com. Our Company at info@indraindustries.in and the Registrar to the Issue at www.purvashare.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Draft Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 31 of the Draft Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.